चिंतन

आर्थिक और खाद्य संकट की ओर बढ़ रही दुनिया

दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां युद्ध की चिंगारी केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन को अपनी चपेट में ले रही है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस आशंका को और गहरा कर दिया है कि आने वाले समय में दुनिया आर्थिक और खाद्य संकट की ओर तेजी से बढ़ सकती है। सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहला असर ऊर्जा बाजार पर दिख रहा है। खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता और तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें 115 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। यूरोप में गैस की कीमतों में 30-35 प्रतिशत तक उछाल दर्ज किया गया है। ऊर्जा महंगी होने का सीधा मतलब है हर चीज महंगी होना। परिवहन, उत्पादन, बिजली और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत बढ़ती है, जिसका बोझ अंततः आम आदमी पर ही पड़ता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह स्थिति और चुनौतीपूर्ण है। भारतीय रुपया लगातार दबाव में है और आयात महंगा हो रहा है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं, जिससे महंगाई की पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। यही कारण है कि जियोपॉलिटिकल तनाव का असर केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रसोई तक पहुंच जाता है। खाद्य संकट की आशंका भी उतनी ही गंभीर है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के कारण फास्फेट, यूरिया और अन्य उर्वरकों की आपूर्ति बाधित हो सकती है। भारत, चीन और ब्राजील जैसे बड़े कृषि उत्पादक देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। उर्वरकों की कमी से फसल उत्पादन घटेगा, जिससे खाद्यान्न की कीमतें बढ़ेंगी और गरीब वर्ग पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। युद्ध का एक और बड़ा प्रभाव सप्लाई चेन पर पड़ता है। पहले ही कोविड-19 के दौरान वैश्विक आपूर्ति प्रणाली कमजोर हो चुकी है, और अब नए संघर्ष ने इसे और अस्थिर बना दिया है। समुद्री मार्गों में बाधा, ऊर्जा सुविधाओं पर हमले और व्यापारिक अनिश्चितता ये सभी कारक मिलकर वैश्विक व्यापार को धीमा कर रहे हैं। यदि यह स्थिति लंबी चली, तो दुनिया को खाद्य वस्तुओं की कमी और महंगाई के दोहरे संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसका ताजा उदाहरण शेयर बाजार में आई भारी गिरावट है। 19 मार्च को सेंसेक्स में 2497 अंकों की गिरावट और निफ्टी में 776 अंकों की गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। एक ही दिन में लगभग 13 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान इस बात का संकेत है कि बाजार में भय का माहौल है। जब निवेशक जोखिम से बचने के लिए शेयर बेचने लगते हैं, तो पूंजी सुरक्षित ठिकानों की ओर भागती है, जिससे आर्थिक गतिविधियां और धीमी पड़ती हैं। हालांकि, इस संकट के बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ओमान के सुल्तान और मलेशिया के प्रधानमंत्री से बातचीत कर तनाव कम करने की कोशिश की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रयास पर्याप्त होंगे? इतिहास गवाह है कि जब तक वैश्विक शक्तियां एकजुट होकर निर्णायक हस्तक्षेप नहीं करतीं, तब तक ऐसे संघर्ष लंबे खिंचते हैं। यदि समय रहते इस आग को नहीं बुझाया गया, तो इसके दुष्परिणाम भयावह हो सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य संकट और आर्थिक मंदी ये सभी मिलकर वैश्विक अस्थिरता को जन्म देंगे। अंततः सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब और विकासशील देशों को होगा, जो पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।

महिलाओं के सहकारी नेतृत्व से बदलता देश

सहकारिता

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के साथ इतने उपक्रम को अपनाया है कि उससे भारतीय सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। भारत आज नेतृत्व, आर्थिक भागीदारी, सरकारी सहयोग, क्षेत्रीय सक्रियता, सामाजिक प्रभाव के अध्ययन व सशक्तिकरण की निति व नीतिगत बदलाव के लिए कार्य कर रहा है। इसमें अभिरुचि एवं अवसर दोनों बहुत मायने रखते हैं। यदि इनका समन्वय हो सका तो नि:संदेह आने वाला सहकारिता इतिहास स्त्रियों के नेतृत्व से परिपूर्ण दिखेगा और भारत तेजी से बदलता हुआ दिखेगा भी। आवश्यकता इस बात की है कि हम समय की पहचान करके सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाएं।

अधिकार, न्याय व कार्रवाई थीम पर केंद्रित इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सुर्खियों में रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र दस दिन तक विश्व की महिलाओं के साथ उत्साहपूर्ण वातावरण में खूब बातें कर रहा है। यूएन महासभा अध्यक्ष ऐनालेना बेयरबॉक का मानना है कि जब लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती हैं तो अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, जब महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं तो उत्पादकता बढ़ती है और जब शान्ति वार्ताओं में महिलाएं शामिल होती हैं तो शान्ति समझौते अधिक समय तक टिकाऊ साबित होते हैं। भारत में महिलाओं के शैक्षणिक बदलाव हो रहे हैं लेकिन जो कम पढ़ी-लिखी महिलाएं हैं, उन्होंने भी सहकारिता से जुड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य किया है। सहकार से समृद्धि की मिसाल पेश करतीं हमारे देश की महिलाओं का आत्मबल व आत्मविश्वास दोनों बहुत ही मजबूत है। राष्ट्रीय नई सहकारिता नीति एक विज़न, एक मिशन के साथ आगे बढ़ चुकी है।

भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के साथ इतने उपक्रम को अपनाया है कि उससे भारतीय सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। छः रणनीतिक मिशन जिसमें नींव का सशक्तिकरण करने का संकल्प है, इसके अंतर्गत सहकारी आंदोलन की नींव को और भी मजबूत करने की कोशिश है। जीवंतता को प्रोत्साहित करने का संकल्प है जिसके अंतर्गत जीवंत और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन होगा। तीसरा, सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करने की कोशिश, जिसमें सहकारी समितियों को पेशेवर और सतत आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित किया जाएगा। चौथा समावेशिता को बढ़ावा देकर पहुंच का विस्तार प्रदान करने के लिए सहकार आधारित समावेशी विकास और सहकारी समितियों को जन आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करने पर बल है। साथ ही नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार हो, इसके लिए ऐसी योजना है कि सहकारी समितियों के नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार को प्रोत्साहित किया जाए। सबसे अहम संकल्प यह है कि सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करने को प्रोत्साहन मिले, जिसका उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को प्रेरित कर उन्हें अनुभवजन्य सहकारी ज्ञान प्रदान करके भारत निर्माण में उन्हें जोड़ा जाए। यह न केवल ग्रामीण सहकारी परिवेश से उनके जुड़ाव को विकसित करेगा बल्कि गांव की संस्कृति से भागते युवाओं को पुनः गांव से जोड़ने का कार्य करेगा। स्त्री युवा शक्ति इसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाली हैं, यह तो तय है। । इसका उल्लेख अब पूरे विश्व में हो रहा है। एनडीडीबी से जुड़ी स्त्रियों की सफलता की कहानियां अब शोध और अध्ययन का हिस्सा बनने जा रही हैं। भारतीय सहकारिता आन्दोलन को देखकर आज कुछ ऐसा ही स्पष्ट हो रहा है कि भारत सरकार कितनी जागरूकता के साथ सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी व्यवस्था, लोग और खासकर स्त्री-शक्ति-सशक्तिकरण पर कार्य कर रही है।

यह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अगर बहुत संजीदगी से देखा जाए तो विभिन्न विश्लेषण बताते हैं कि सरकार डेयरी, कृषि, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्यमों जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के गठन और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित कर अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर विभिन्न संस्थानों और

योजनाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। श्वेत क्रांति 2.0 ने तो मानों देश में एक नई आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ने को तत्पर है। ऐसा सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 46,422 मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों के सशक्तिकरण के अलावा, 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। डेयरी सहकारी समितियां महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने की दिशा में इससे बढ़ चुकी हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-एनसीडीसी ने भी महिला केंद्रित योजनाएं शुरू की हैं जिसमें स्वयं शक्ति सहकार योजना, नंदिनी सहकार योजना एवं युवा सहकार योजनाओं ने तो आमूलचूल परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया है।

स्वयं शक्ति सहकार योजना से एक तरफ आय सृजन कार्यकलापों, उद्यमिता विकास और महिला एसएचजी की क्षमता निर्माण होगा, वहीं दूसरी तरफ वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला सहकारी समितियों को बढ़ावा मिलेगा और स्त्रियां सशक्त होंगी। नंदिनी सहकार योजना से डेयरी, पशु पालन, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य संबद्ध क्षेत्रों जैसे कार्यकलापों में लगी महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता मिलेगी तो इससे सहकारी उद्यमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। युवा महिला उद्यमियों को एनसीडीसी के माध्यम से वित्तीय सहायता और समर्थन मिलेगा। उभरते और अभिनव क्षेत्रों में सहकारी उद्यमों की स्थापना होने से प्रबंधन में प्रोत्साहित होंगी। चीन की राजधानी बीजिंग में वर्ष 1995 में दुनिया के देशों ने एक साथ आकर एक घोषणापत्र बीजिंग प्लेटफ़ॉर्म को पारित किया था, जिसे महिला अधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जाता है। इस पड़ाव के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आर्थिक उन्नति, समावेशिता और उन्नत स्वास्थ्य के साथ पूर्णतया प्रतिभागिता को यह सम्मेलन संबोधित करता है. भारत में सहकारिता क्षेत्र में कार्य कर रही स्त्रियों को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह सहकारिता आन्दोलन बीजिंग घोषणापत्र का भी सम्मान क्षेत्र है. भारत में सशक्तिकरण अब एक नारा नहीं है अपितु सशक्तिकरण की मिसाल है सहकारिता।

भारतीय स्त्रियां जो सहकारिता क्षेत्र अब पढ़-लिखकर व शोध करके आने वाले समय में भारत के लिए कार्य करने वाली हैं, उसकी गाथा आने वाले वर्षों में शोध का विषय होंगी। यह एक ऐतिहासिक बदलाव है जिसे भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ अमित शाह के नेतृत्व में अर्जित कर रही है क्योंकि उनकी इच्छाशक्ति और कार्य को मूर्तरूप प्रदान करने की निराने शक्ति दोनों स्पष्ट है। भारतीय सामाजिक ताने-बाने के बीच अपनी जिंदगी संवारतीं महिलाओं के सशक्तिकरण की यह सहकारिता यात्रा भारत के बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। भारत की महिलाओं के बहुत से ऐतिहासिक उपलब्धियों की कहानियां प्रचलित हैं लेकिन विगत कुछेक वर्षों में सहकारिता से सशक्त स्त्री का इतिहास आने वाले समय में प्रेरणा का विषय बनने जा रहा है। भारत आज नेतृत्व, आर्थिक भागीदारी, सरकारी सहयोग, क्षेत्रीय सक्रियता, सामाजिक प्रभाव के अध्ययन व सशक्तिकरण की निति व नीतिगत बदलाव के लिए कार्य कर रहा है। इसमें अभिरुचि एवं अवसर दोनों बहुत मायने रखते हैं। यदि इनका समन्वय हो सका तो निःसंदेह आने वाला सहकारिता इतिहास स्त्रियों के नेतृत्व से परिपूर्ण दिखेगा और भारत तेजी से बदलता हुआ दिखेगा भी। आवश्यकता इस बात की है कि हम समय की पहचान करके सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाएं।

(लेखक केंद्रीय विवि पंजाब में वेयर प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

गौरैया दिवस

सुनील कुमार महला

चिरैया का संरक्षण मानवता के सुरक्षित भविष्य की गारंटी

प्रतिवर्ष 20 मार्च को 'विश्व गौरैया दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य गौरैया तथा अन्य छोटे पक्षियों के संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, उनकी निरंतर घटती संख्या के कारणों को समझाना, जैव-विविधता (बायो-डायवर्सिटी) के महत्व को रेखांकित करना तथा लोगों को पेड़-पौधे लगाने, कृत्रिम घोंसले बनाने और पक्षियों के लिए दाना-पानी उपलब्ध कराने जैसे व्यावहारिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2010 में भारत की संस्था नेचर फोरएवर सोसायटी द्वारा की गई थी। एक समय था जब घर-आंगन में गौरैया की चहचहाहट हमारे सामान्य जीवन का हिस्सा हुआ करती थी, किंतु बदलती जीवनशैली, पक्के मकानों के बढ़ते चलन और घटते हरित क्षेत्र के कारण आज इनकी संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है और इसका सीधा व प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र (इको सिस्टम) पर पड़ रहा है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज बढ़ती आबादी, तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण, कंक्रीट के जंगलों का विस्तार, ध्वनि, जल तथा वायु प्रदूषण, मोबाइल टावरों से निकलने वाला विकिरण, वनों की अंधाधुंध कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, कीटनाशकों और रसायनों का अत्यधिक उपयोग तथा कृषि में तकनीकी बदलाव जैसे अनेक कारण गौरैया के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। वास्तव में, छोटे पक्षी विशेष रूप से ध्वनि प्रदूषण को सहन नहीं कर पाते, वहीं टावरों से निकलने वाली तरंगें उनकी प्रजनन क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक ईंधनों में प्रयुक्त रसायन जैसे बेंजीन और मिथाइल तृतीयक ब्यूटाइल ईथर उन कीटों को नष्ट कर देते हैं, जिन पर गौरैया के बच्चे निर्भर रहते हैं। उद्यानों में कीटनाशकों और शाकनाशियों के अत्यधिक उपयोग से भी कीटों की संख्या में कमी आई है, जिससे इनके भोजन का संकट उत्पन्न हो गया है। शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक घोंसला स्थलों की कमी, कांच से बनी बंद इमारतों का बढ़ता प्रचलन तथा उपयुक्त भोजन की अनुपलब्धता इनके प्रजनन को लगातार प्रभावित कर रही है। बदलती वास्तुशैली और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने इनके आवास और खाद्य स्रोतों को लगभग समाप्त कर दिया है। बहरहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार भारत में घरेलू गौरैया की संख्या में लगभग 60 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है। पक्षियों के संरक्षण के लिए रॉयल सोसाइटी (रॉयल सोसाइटी फोर दि प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स) ने इसे अपनी रेड-लिस्ट में शामिल किया है। गौरतलब है कि विश्व में गौरैया की लगभग 26 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 5 भारत में मिलती हैं। यह बिहार का राज्य पक्षी है तथा वर्ष 2012 में इसे दिल्ली का राज्य पक्षी घोषित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के अनुसार आंध्र प्रदेश में इसकी संख्या में 80 प्रतिशत तक कमी आई है, जबकि केरल, गुजरात और राजस्थान में लगभग 20 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। 'स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स' रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी संख्या अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है, जबकि महानगरों में 70 से 80 प्रतिशत तक गिरावट देखी गई है। गौरैया पासेरीडे परिवार की एक सामाजिक और सर्वाहारी पक्षी है, जो झुंड में रहना पसंद करती है। यह मुख्यतः बीज, कीड़े, जामुन और फल खाती है। इसकी सामान्य उड़ान गति लगभग 24 मील प्रति घंटा होती है, जो खतरे की स्थिति में 31 मील प्रति घंटा (लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा) तक पहुंच सकती है। इसकी औसत आयु 4 से 5 वर्ष होती है। यह दीवारों, पेड़ों के कोटरों, झाड़ियों, पुराने घरों, रोशनदानों और खिड़कियों में घोंसला बनाती है। नर गौरैया अपने घोंसले की रक्षा आक्रामक रूप से करता है और यह पक्षी सामान्यतः जीवनभर एक ही साथी के साथ रहने की प्रवृत्ति रखता है, जो इसकी वफादारी को दर्शाता है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में गौरैया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अल्फा और कटवर्म जैसे हानिकारक कीटों को खाकर फसलों की रक्षा करती है, इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। अंततः, गौरैया संरक्षण के लिए किसी बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे प्रयास ही पर्याप्त सिद्ध हो सकते हैं-जैसे घरों में दाना-पानी रखना, मिट्टी के बर्तनों (परिंडे) का उपयोग करना, पौधे लगाना, कृत्रिम घोंसले बनाना तथा पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवनशैली का अभिन्न अंग बनाना। निष्कर्षतः, गौरैया केवल एक साधारण पक्षी नहीं, बल्कि पर्यावरण संतुलन की आधारशिला है; इसका संरक्षण मानवता के सुरक्षित और संतुलित भविष्य की गारंटी है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

साधना से ही मिलता है वास्तविक सुख

संकलित

दर्शन

अधिकांश व्यक्ति आज भौतिक मूल्यों के उपासक बन गए हैं। इस कारण जीवन के धर्म एवं मर्म को भुला बैठे हैं। उनकी इस उपासना ने दुनिया के बाह्य जगत को बड़ा सुहावना, लुभावना और आकर्षक बना दिया है। जबकि वास्तविक सुख आंतरिक सौंदर्य, अंतर्जगत की जागृति एवं अंतर्यात्रा से ही संभव है। भौतिक आकर्षण के पीछे मनुष्य दौड़ रहा है। यदि वह क्षण भर रुककर गंभीरता से सोचे तो उसे पता चलेगा कि यह सब भ्रम जाल है। जीवन वह नहीं, जिसे वह जी रहा है। संत एकनाथ ने कहा है कि धन जोड़कर भक्ति का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ऐसा करने से मन में वासना और भी बढ़ जाएगी और जिनका चित्त वासना में फंसा हुआ है, उन्हें अंतरात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं। वास्तविक सुख पाने के लिए व्यक्ति भक्ति यानी साधना की ओर प्रवृत्त होता है। स्थायी सुख की प्राप्ति भक्ति पर ही निर्भर है। भक्ति से मन को वश में करना है और मन को वश में करने का सरल उपाय है उसे परमात्मा के हेतु निरंतर भले कार्यों में लगाए रखना। महात्मा गांधी ने प्रेमा बहन के नाम लिखे पत्र में लिखा है-जो लोग कृष्ण-कृष्ण कहते हैं वे उसके पुजारी नहीं हैं। जो उनका काम करते हैं, वे ही पुजारी हैं। रोटी-रोटी कहने से पेट नहीं भरता, अपितु रोटी खाने से ही भरता है। मन को वश में लाने का अभ्यास अनेक प्रकार का होता है। इन अभ्यासों को ही भक्ति यानी साधना कहा गया है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को शांति-अशांति, मान-अपमान और सुख-दुख से निर्लिप्त बना लिया है, वही निर्विघ्न शांति में स्थित रह सकता है।

अच्छी बातें जीवन में उतारने पर ही लाभ मिलेगा

संकलित

प्रेरणा

द्वापर युग में द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह ने कौरव और पांडव राजकुमारों का गुरु बना दिया था। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को एक पाठ दिया और कहा कि कल इस पाठ को आत्मसात करके आना है। आत्मसात शब्द का अर्थ है जीवन में, अपने आचरण में उतारना। अगले दिन सभी राजकुमार गुरु के आश्रम में पहुंच गए। पढ़ाई शुरू हुई तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि कौन-कौन कल का पाठ याद करके आया है? युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी सभी राजकुमारों ने कह दिया कि हमने ये पाठ याद कर लिया है। गुरु ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने पाठ याद क्यों नहीं किया है? युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने अभी तक ये पाठ आत्मसात नहीं किया है। ये बात सुनकर द्रोणाचार्य हैरान थे। कुछ देर सोचकर गुरु ने कहा कि ठीक है कल याद करके आना। इसके बाद दस दिन बीत गए, लेकिन युधिष्ठिर को वो पाठ अब तक याद नहीं हुआ था। जबकि अन्य राजकुमार युधिष्ठिर से 10 पाठ आगे पहुंच गए थे। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर बात क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, जैसे मेरे भाइयों ने ये पाठ याद किया है, वैसे तो मुझे याद है, लेकिन आपने कहा था कि इस पाठ को आत्मसात करना है। आपने सत्य को जीवन में उतारने का पाठ दिया था और मैं सत्य को जीवन में उतार नहीं पा रहा हूं। जब तक मैं इसे आत्मसात नहीं कर लूंगा, जब तक मैं सत्य को जीवन में नहीं उतार लूंगा, तब तक मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा।

अंतर्मन

आज की पाती

वनों को काटने से रोका जाए

21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में इस उपलक्ष्य में प्रोग्राम आयोजित किए गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वनों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 28 नवंबर 2012 को हर वर्ष 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। वन हैं तो हम हैं। जो वृक्ष हमें फल नहीं देते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन, बिना किसी मूल्य के देते हैं। लेकिन बहुत अफसोस है कि वनों की संभाल के लिए लापरवाही बरती जा रही है।भारत में बहुत पहले से ही वनों और वृक्षों को काटने से रोकने के प्रयास सरकारों, सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा आरंभ कर दिए गए थे। फिर भी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। - महेश कुमार यदु, रायपुर

ट्रेंड

आत्मनिर्भर बने देश

भारत की रक्षा तैयारियों और सामरिक स्वायत्तता के लिए यह आवश्यक है कि देश ड्रोन निर्माण में पूरी तरह आत्मनिर्भर बने और आने वाले वर्षों में ड्रोन निर्माण का ग्लोबल हब बने।

- राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री

207 नई बसें रवाना

राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों के लिए यातायात सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और आधुनिक बनाने हेतु 207 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें न केवल शहरों और गांवों के बीच की दूरी को कम करेंगी, बल्कि प्रदेश के विकास को भी नई दिशा प्रदान करेंगी।

- भजनलाल, सीएम, राजस्थान

गहरी संवेदना

मध्य प्रदेश के इंदौर में शार्ट सर्किट से घर में लगी आग से बिहार के 6 लोगों की मृत्यु दुःखद। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।

- नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

चुनाव आयोग बना हथियार

बीजेपी ने बेईमानी से चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग को अपना हथियार बना लिया है। जो आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, यही दिल्ली के चुनाव में भी हुआ था। लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ायी गईं। आज ममता भी लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही हैं। इस संघर्ष में हम उनके साथ हैं।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

करंट अफेयर

तुलसी गबार्ड ने खोल दी ट्रंप के दावे की पोल?

अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के एक बयान ने वॉशिंगटन की सियासत में हलचल मचा दी है। उनके इस खुलासे के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर सवाल उठने लगे हैं, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर खतरे को जंग की बड़ी वजह बताया गया था। गाबार्ड ने सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने अपने लिखित बयान में कहा कि 2025 में अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने अपने परमाणु संवर्धन (न्यूक्लियर एनरिचमेंट) कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने की कोई कोशिश नहीं की है। तुलसी गबार्ड ने बताया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह तबाह हो गया था और तब से उसे फिर से खड़ा करने की कोई गतिविधि सामने नहीं आई। यह बयान सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन के उस तर्क को कमजोर करता है, जिसमें बार-बार कहा गया कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। ट्रंप और उनके अधिकारी लगातार यह कहते रहे हैं कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई जरूरी थी लेकिन गबार्ड के बयान के बाद बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर ईरान ने अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू ही नहीं किया, तो फिर जंग की जरूरत क्यों पड़ी?

ऑफ बीट

सप्ताह में 150 मिनट की शारीरिक गतिविधि जरूरी

व्यायाम आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और विशेष रूप से आपके हृदय के लिए अच्छा है। विशेषज्ञों की राय है कि हमें सप्ताह में 150 मिनट की मध्यम-से-जोरदार शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। शोधकर्ताओं ने पाया कि एक्सेलेरोमीटर मूल्यांकन के बाद छह वर्षों में, जो लोग नियमित रूप से मध्यम से जोरदार गतिविधि करते थे, उनमें गतिहीन लोगों की तुलना में स्ट्रोक, दिल का दौरा, दिल की विफलता और एट्रियल फाइब्रिलेशन कम था। इस अध्ययन का अनोखा निष्कर्ष यह था कि जिन लोगों ने अपनी आधी से अधिक गतिविधि सप्ताहांत में की, उनकी तुलना में उन लोगों के परिणामों में कोई अंतर नहीं था, जिन्होंने इसे पूरे सप्ताह में फैलाकर किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कब किया गया था, मध्यम-जोरदार शारीरिक गतिविधि बेहतर हृदय स्वास्थ्य से जुड़ी थी। अध्ययन में, लेखकों ने उन लोगों को 'सप्ताहांत योद्धा' कहा, जिन्होंने सप्ताह में 150 मिनट से अधिक की मध्यम-से-जोरदार गतिविधि की। यह लाइक्रा पहने पहाड़ी रास्तों पर साइकिल की सवारी करते हुए या मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को 90 मिनट की कठिन फुटबॉल खेलने जैसा है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

राजा वुंडरू को परिवहन विभाग,मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का एसीएस बनाया

हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 23 आईएएस अधिकारियों के तबादला एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा आदेशों के अनुसार डॉ. राजा शेखर वुंडरू को परिवहन विभाग तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। जी. अनुपमा को सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के साथ-साथ नागरिक उड्डयन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है।

अपूर्व कुमार सिंह को उच्चतर शिक्षा विभाग और लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) तथा वास्तुकला विभाग का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अनुराग अग्रवाल को नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी संपदा विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया है। विजयेंद्र कुमार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नियुक्तियां, कार्मिक विभाग तथासैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव

विजय सिंह दहिया पशुपालन एवं खेल विभाग के प्रधान सचिव नियुक्त

आशिमा बराड़ को ऊर्जा विभाग के आयुक्त एवं सचिव का दायित्व दिया गया

और प्रस्तावित हरियाणा आय संवर्धन बोर्ड अधिकारी का ओएसडी लगाया गया है। पंकज अग्रवाल को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग में प्रधान सचिव और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड में सलाहकार नियुक्त किया गया है।

विजय सिंह दहिया को स्कूल शिक्षा विभाग के साथ-साथ पशुपालन एवं खेल विभाग का प्रधान सचिव लगाया गया है। आशिमा बराड़ को आबकारी एवं कराधान तथा वित्त विभाग के साथ-साथ ऊर्जा विभाग के आयुक्त एवं सचिव का दायित्व भी दिया गया है। फूलचंद मीणा को मानव संसाधन विभाग, सामान्य प्रशासन के आयुक्त एवं सचिव तथा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ-साथ फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव साकेत कुमार को विकास एवं पंचायत विभाग और सहकारिता विभाग के आयुक्त एवं सचिव के साथ-साथ हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी सौंपा गया है। ए. मोना श्रीनिवास को रेजिडेंट कमिश्नर, हरियाणा भवन, नई दिल्ली तथा सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जे. गणेशन को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग का आयुक्त एवं सचिव, सभी के लिए आवास विभाग का महानिदेशक एवं सचिव लगाया गया है।

इसके अलावा उन्हें हरियाणा एआई विकास परियोजना और हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और अन्य बाहरी सहयता प्राप्त परियोजनाओं का सीईओ और हरट्रॉन का प्रबंध निदेशक लगाया गया है। अशोक कुमार मीणा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग का आयुक्त एवं सचिव तथा विदेशी सहयोग विभाग के महानिदेशक का कार्यभार दिया गया है। मनी राम शर्मा को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां नियुक्त किया गया है। मुकुल कुमार को निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन एवं राज्य शहरी विकास प्राधिकरण तथा निदेशक, हॉस्पिटैलिटी का कार्यभार सौंपा गया है। डॉ. आदित्य दहिया को प्रबंध निदेशक, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा निदेशक, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नियुक्त किया गया है।

विजय कुमार सिद्धप्पा भावीकट्टी को प्रबंध निदेशक, हैफेड तथा हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, गनौर का दायित्व दिया गया है। सुशील सारवन को प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम तथा हरियाणा वित्त निगम का कार्यभार सौंपा गया है। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक विक्रम को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक भी लगाया गया है। नेहा सिंह को उपायुक्त, सोनीपत नियुक्त किया गया है। सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक और विजिलेंस विभाग की अतिरिक्त सचिव वर्षा खांगवाल को राज्य परियोजना निदेशक, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। मनीता मलिक को निदेशक, मौलिक शिक्षा हरियाणा एवं अतिरिक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग नियुक्त किया गया है। वंदना दिसोदिया को कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हरियाणा का निदेशक तथा अतिरिक्त सचिव लगाया गया है।

बवाना में 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, बच्चे समेत तीन घायल

नई दिल्ली। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के बवाना थाना अंतर्गत गुरुवार शाम एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीबारी में बच्चे समेत तीन लोग घायल भी हुए है। मरने वाले व्यक्ति का नाम रवि भारद्वाज बताया गया है।

पुलिस के अनुसार शाम लगभग 5:26 बजे, बवाना के हरेवली गांव में गोलीबारी की घटना के संबंध में दो पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। कॉल करने वालों ने बताया कि कुछ बाइक सवारों ने उनके परिवार के सदस्य पर गोली चलाई और वे उसे पूठ खुर्द के अस्पताल ले जा रहे थे। पुलिस टीम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तुरंत घटनास्थल और अस्पताल पहुंची। प्रारंभिक जांच में पता चला कि तीन आरोपी मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने विशेष रूप से रवि भारद्वाज को निशाना बनाकर गोलीबारी की। घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद किए गए। लगभग 30 वर्षीय रवि भारद्वाज को पूठ खुर्द के एमवी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव को बीएसए अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया है। घायल तीन लोगों में अनिल भारद्वाज (55) पुत्र राम प्रसाद, राज कुमार (46) पुत्र देवी दयाल और एक नाबालिग लड़का उम्र लगभग 8 वर्ष शामिल है। पुलिस स्टेशन बवाना में शस्त्र अधिनियम की धारा 103(1), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।

दुलारचंद हत्याकांड में अनंत को मिली बेल

मोकामा। यहां के विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें चर्चित दुलारचंद यादव हत्या मामले में जमानत दे दी गई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह निर्णय सुनाया।

कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभावना है कि अनंत सिंह शुक्रवार या शनिवार तक जेल से रिहा हो सकते हैं। उनके समर्थकों में खुशी है।

कन्नूर सांसद ने कांग्रेस को दिया अल्टीमेटम

नई दिल्ली। असम से लेकर केरल तक चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। केरल के कन्नूर से लोकसभा सांसद के सुधाकरन ने पार्टी नेतृत्व को अल्टीमेटम दिया है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया तो भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सुधाकरन यहां चुनाव लड़ना चाह रहे हैं।

भाजपा ने असम की पहली सूची में 88 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा

अभयपुरी से भूपेन, बिजनी से अरूप, भवानीपुर सोरभोग से रंजीत कुमार दास को मिला टिकट

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बृहस्पतिवार को घोषित की। लिस्ट में 88 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगी थी और अब इसकी घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल थे। भाजपा ने जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतरा है, उनमें प्रमुख तौर पर अभयपुरी से भूपेन रॉय, बिजनी से अरूप कुमार डे, भवानीपुर-सोरभोग से रंजीत कुमार दास, मंडिया से बादल चंद्र आर्य, चमरिया से ज्योत्स्ना कलिता और बोको-चायगांव से राजू मेच का नाम शामिल है। गोलकगंज से अश्विनी राय सरकार, धुबरी से उत्तम प्रसाद, बिरसिंग जरूआ से माधवी दास, गोलपारा पश्चिम से पबित्र राभा और दुधनई से टंकेश्वर राभा को टिकट दिया है। पार्टी ने पलासबारी से हिमांशु शेखर बैश्य, रंगिया से भबेश कलिता, कमलपुर से दिगंत कलिता, दिसपुर से प्रद्युत बोरदोलोई, नई गुवाहाटी से दिप्लु रंजन सरमा, गुवाहाटी सेंट्रल से विजय कुमार गुप्ता और जालुकबारी से डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा को मौका दिया है। वहीं, बरखेत्री से नारायण डेका, नलबाड़ी से जयंत मल्ल बरुआ, तिहू से चंद्रमोहन पाटोवारी, तामुलपुर से बिस्वजीत देइमारी, गोरेस्वर से विक्टर कुमार दास, टांगला से बिकन चंद्र डेका, सिपाझार से डॉ. परमानंद राजबंशी को उम्मीदवार बनाया है।

पश्चिम बंगाल की दूसरी लिस्ट में 111 नाम, रूपा गांगुली और दिब्येंदु अधिकारी को टिकट

भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बृहस्पतिवार को 111 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी। भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के भाई दिब्येंदु अधिकारी को भी टिकट दिया है। रेखा पात्रा को हिंगलगंज, अभिनेत्री रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण, प्रियंका टिबरेवाल को एंटली और तपस रॉय को मानिकतला से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने दूसरी सूची में 111 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इससे पहले पार्टी 144 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी थी। अब तक कुल 255 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, जबकि 39 सीटों पर अभी भी फैसला बाकी है। सूची में निसिथ प्रमाणिक को मथाभांगा, शंकर अधिकारी को चोपड़ा, कौस्तव बागची को बैरकपुर और अरूप चौधरी को कामरहाटी से टिकट मिला है। इस सूची में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। हिरण चटर्जी को खड़गपुर सदर से हटाकर श्यामपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। पहले उनके टिकट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन पार्टी ने उन्हें नई सीट से मौका देकर चौंका दिया है। साथ ही, पहली सूची में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। बिष्णुपुर (एससी) विधानसभा सीट पर भाजपा ने बदलाव करते हुए अब बिस्वजीत खान को उतारा है। वहीं, जॉयपुर विधानसभा में बिस्वजीत महतो को भाजपा ने समर्थन दिया है। बता दें, कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही, चार मई को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे।

केरल में भाजपा ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की

केरल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आज 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा ने अब तक 86 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में भाजपा ने कुल छह महिलाओं को मैदान में उतारा है। दोनों लिस्ट को मिला दें तो अब तक भाजपा ने कुल 13 महिलाओं को टिकट दिया है। भाजपा ने पूर्व भाजपा अध्यक्ष और मिजोरम को पूर्व राज्यपाल कुम्मनम राजशेखरन को टिकट दिया है। राजशेखरन ने इससे पहले 2021 में नेमोम से चुनाव लड़ा था, जहाँ मौजूदा शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी विजयी हुए थे। वरिष्ठ भाजपा नेता बी. गोपालकृष्णन गुरुवायूर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने धर्मडोम से के. रंजीत को भी मैदान में उतारा है, जहाँ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने त्रिशूर में एससी आरक्षित सीट नट्टिका निर्वाचन क्षेत्र से भाकपा के पूर्व विधायक सी.सी. मुकुंदन को मैदान में उतारा है, मुकुंदन ने हाल ही में सीट न दिए जाने के कारण भाकपा छोड़ दी थी, क्योंकि पार्टी ने पूर्व विधायक गीता गोपी को प्राथमिकता दी थी। भाजपा ने इस बीर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी टिकट दिया है। इस लिस्ट में बिग बॉस के प्रतियोगी रहे रॉबिन राधाकृष्णन को कोल्लम के कुंदारा से मैदान में उतारा गया है।

पश्चिम बंगाल चुनावः भाजपा ने दूसरी सूची में 111 उम्मीदवारों का किया ऐलान

रूपा को सोनपुर दक्षिण, प्रमाणिक को माथाभांगा तो छेत्री को कलिम्पोंग से उतारा

निशीथ प्रमाणिक

रूपा गांगुली

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली/ कगोलकाता

भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें 19 महिलाओं का नाम है। इससे पहले पहली लिस्ट में 144 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। पूर्व सांसद रूपा गांगुली को सोनपुर दक्षिण विधानसभा सीट, पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक को माथाभांगा विधानसभा सीट, हॉकी के पूर्व खिलाड़ी भरत छेत्री को कलिम्पोंग विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा भाजपा ने दार्जिलिंग से नोमन राय को पार्टी ने से उम्मीदवार बनाया है। इसी सूची में पहली लिस्ट में घोषित किए गए बिष्णुपुर (एससी) सीट के प्रत्याशी में बदलाव की जानकारी भी दी है। अब बिष्णुपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने विस्वजीत खान को उतारा है। भाजपा ने जॉयपुर सीट पर बिस्वजीत महतो के नाम का ऐलान किया।

ममता ने अफसरों के तबादले को बताया राजनैतिक हस्तक्षेप

टीएमसी सुप्रीमो ने चुनाव आयोग के दखल को प्रशासन को पंगु बनाने का प्रयास बताया

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले ही शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों सहित 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को मनमाने ढंग से हटा दिया गया है। बनर्जी ने इस कदम को राजनीतिक हस्तक्षेप करार दिया और चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयां संस्थागत निष्पक्षता को कमजोर करती हैं और राज्य में चुनावों के संचालन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल को अनुचित रूप से निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है। बनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि सूचना एवं संचार ब्यूरो (आईबी), एसटीएफ और सीआईडी जैसी प्रमुख एजेंसियों को चुनिंदा तबादलों के जरिए कमजोर किया जा रहा है, जिसे उन्होंने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को पंगु बनाने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। उन्होंने पारदर्शिता को लेकर चिंता जताते हुए पूरक मतदाता सूचियों के प्रकाशन में देरी पर भी सवाल उठाए। स्थिति को "अघोषित आपातकाल" बताते हुए उन्होंने भाजपा पर संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि बंगाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगा।

पश्चिम बंगाल में चुनाव संचालन और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच आई हैं।

टीएमसी सरकार के असहयोग के कारण चुनाव तैयारियों में बाधा आईः भाजपा

भाजपा नेता पॉल ने टीएमसी और वामपंथियों पर तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया। उधर, भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के लिए डेटा प्रबंधन अधिकारियों की मांग की थी, लेकिन ममता सरकार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। इससे राज्य में चुनावी तैयारियों में बाधा उत्पन्न हुई। पॉल ने टीएमसी और वामपंथियों दोनों की आलोचना करते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन प्रयासों के बावजूद, अल्पसंख्यक समुदायों को कोई वास्तविक विकास नहीं मिला, बल्कि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये टिप्पणियां चुनावों से पहले पार्टियों के बीच बढ़ते जुबानी जंग को और हवा देती हैं।पॉल ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के लिए डेटा प्रबंधन अधिकारियों की मांग की थी, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इस कदम से राज्य में चुनावी तैयारियों में बाधा उत्पन्न हुई।

'ग्रेट निकोबार' का आदिवासी प्रमुखों ने किया विरोध, राहुल से की मुलाकात

आदिवासियों ने कहा- इससे आजीविका प्रभावित होगी

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

ग्रेट निकोबार द्वीप के आदिवासी प्रमुखों का एक प्रतिनिधिमंडल, आदिवासी कांग्रेस के नेताओं के साथ, आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित 'ग्रेट निकोबार परियोजना' का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह परियोजना उनके पारंपरिक जीवन, संस्कृति और द्वीप के नाजुक पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। आदिवासी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि परियोजना को मंजूरी देने की प्रक्रिया के दौरान उनकी सहमति सही तरीके से नहीं ली गई।

मुलाकात के दौरान आदिवासी प्रमुखों ने अपनी चिंताओं को विस्तार से रखते हुए कहा कि इस परियोजना से उनके आजीविका के साधनों पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ सकता है। इस पर राहुल गांधी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए उनकी आवाज को हर मंच पर उठाएगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

गुजरात में यूसीसी लागू होगा

हलाला से मिली आजादी... दूसरी शादी पर 7 साल जेल!

अहमदाबाद। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसूसू) लागू करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। राज्य कैबिनेट ने 'गुजरात समान नागरिक संहिता , 2026' के मसौदे को मंजूरी दे दी है और इसे विधानसभा सचिवालय भेज दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि मौजूदा बजट सत्र में ही इस विधेयक को पास करा लिया जाए। अब गुजरात देश का दूसरा राज्य बन जाएगा जहां सभी धर्मों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू होगा। मसौदे में हलाला प्रथा पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियम सभी समुदायों के लिए समान हो जाएंगे। अलग कानून खत्म हो जाएंगे।

सीडीएससीओ ने दिए नए दिशा-निर्देश

सुनिश्चित होगी गुणवत्ता

अब दवाओं के लाइसेंस के लिए डोजियर प्रणाली का पालन जरूरी

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने दवा निर्माण लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए दस्तावेज आधारित प्रणाली (डोजियर) लागू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। इसका मकसद देशभर में दवाओं की गुणवत्ता और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस दस्तावेज में दवा निर्माताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक व्यवस्थित सूची दी गई, जिसमें

प्रशासनिक और तकनीकी दोनों तरह की आवश्यकताएं शामिल हैं। यह नियम दवा बनाने वाली कंपनियों पर लागू होगा, लेकिन आयुष दवाओं, प्रसाधन सामग्री और चिकित्सा उपकरणों को इससे बाहर रखा गया है।

अब आवेदन का मूल्यांकन होगा

दस्तावेज-आधारित प्रक्रिया के तहत नियामक अब आवेदन का व्यापक और व्यवस्थित तरीके से मूल्यांकन कर सकेंगे, जिसमें परीक्षण रिपोर्ट, प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल होंगे, न कि अलग आधार पर जांच होगी। यह प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाती है और फैसले लेने में निष्पक्षता लाती है। डोजियर आधारित प्रणाली व्यक्तिगत मूल्यांकन की तुलना में ज्यादा प्रभावी है।

रेलवे की सुरक्षा मुहिम का असर, 10 वर्षों में हादसे 60 फीसदी घट गए

यात्रा बनी सुरक्षित, हादसों में भारी कमी, मौतों में भी आई गिरावट

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

भारतीय रेल में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के परिणाम अब साफ नजर आने लगे हैं। बीते एक दशक में रेल हादसों और उनसे होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता जानकारी देते हुए बताया कि 10 वर्षों में 60 फीसदी हादसे कम हुए हैं, जाहिर इससे असामयिक मौतों में 17 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार के लिए जहां ये राहत भरी खबर है वहीं रेल यात्रियों के लिए भी खुशी का पैगाम है।

परिणाम दिखे

आंकड़े साझा करते हुए आधिकारिक प्रवक्ता के बताया कि 2014-15 में जहां 135 ट्रेन हादसे हुए थे, वहीं 2025-26 (फरवरी तक) यह संख्या घटकर 14 रह गई, यानी करीब 90 फीसदी की कमी। वहीं, पिछले दशक (2014-15 से 2023-24) में, कुल 678 हादसे हुए। उसमें 748 लोगों की मौत हुई थी और 2 हजार 87 यात्री घायल हुए थे। वर्ष 2004-05 से 2013-14 के बीच कुल 1 हजार 711 रेल हादसे हुए उनमें मौतों की संख्या 904 दर्ज की गई थी। जबकि 3 हजार 155 यात्री घायल हुए थे। उक्त अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2024-25 में सुरक्षित रेल यात्रा के लिए रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा लगातार उठाए गए कदमों का परिणाम है कि रेल हादसों की संख्या 31 पर सिमट गई। जबकि केवल 18 मौतें दर्ज की गई और 92 यात्री घायल हुए। उन्होंने कहा, दुर्घटनाएं न हों। यात्री हताहत न हों इसकी लगातार कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा यही वजह है कि वर्ष 2025-26 (फरवरी तक) महज14 रेल हादसे हुए। उनमें 16 मौतें, 28 घायल के आंकड़े हैं।

रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा लगातार उठाए गए कदमों का परिणाम अब दिखने लगा

ऐसे हो रही है रेल सुरक्षा पर खर्च में लगातार बढ़ोतरी :

2013-14: 39,200 करोड़
2022-23: 87,336 करोड़
2023-24: 1,01,662 करोड़
2024-25: 1,14,022 करोड़
2025-26: 1,17,693 करोड़
2026-27: 1,20,389 करोड़

रेलवे ने इस संबंध में कई तकनीकी उपाय लागू किए हैं:

6,665 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम
10,153 लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर इंटरलॉकिंग
6,669 स्टेशनों पर ट्रैक सर्किटिंग

'कवच' प्रणाली का विस्तार

रेलवे ने स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम "कवच" को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया है। जुलाई 2020 में इसे लागू किया गया। 2024 में इसका उन्नत संस्करण 4.0 मंजूर हुआ। अब तक 1,452 रूट किलोमीटर पर इसे लागू किया जा चुका है। यह सिस्टम खासतौर पर हाई-डेंसिटी रूट पर लागू हुआ है। उनमें दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-हावड़ा जैसे रूट शामिल हैं। इससे कोशिश है कि ट्रेन टकराव जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सरकार का कहना है कि बढ़ते निवेश और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेलवे सुरक्षा में लगातार सुधार हो रहा है। आने वाले वर्षों में हादसों को और कम करने के लिए इन उपायों को और व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया

प्रोजेक्ट अजा को मिला द इकोनॉमिक टाइम्स गवटेक अवार्ड

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

जिला प्रशासन द्वारा संचालित अभिनव पहल प्रोजेक्ट अजा को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राष्ट्रीय समाचार पत्रिका द इकॉनमिक्स टाइम्स द्वारा इस पहल को प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स गवटेक अवार्ड 2026 में एग्रीटेक फॉर फार्मर एम्पावरमेंट श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान जिले में किसानों को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे नवाचारों और प्रभावी कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना का प्रतीक है। प्रोजेक्ट अजा के माध्यम से जिले में किसानों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत महिला समूह को बकरी पालन के लिए प्रेरित कर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

आर्थिक ईमानदारी

पश्चिम एशिया में युद्ध का तनाव बढ़ता जा रहा है और तमाम देशों में असर दिखने लगा है। भारत में भी कई आर्थिक मोर्चों पर बहुत दबाव दिख रहा है। शेयर बाजार का हाल इतना बुरा है और वहां जैसी गिरावट देखी जा रही है, वैसी कोविड-लॉकडाउन के समय देखी गई थी। विदेशी निवेशकों द्वारा मार्च के पहले पखवाड़े में 17 महीनों में सबसे तेज गति से शेयर बेचने के बाद, यह भारत के शेयर बाजार सूचकांक का सबसे खराब पखवाड़ा बनने की ओर अग्रसर है। गुरुवार, 19 मार्च, 2026 को बीएसई में 2000 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई। गौर करने की बात है, विदेशी निवेशकों ने पिछले दो सप्ताह में भारतीय बाजार से 52,704 करोड़ रुपये निकाले हैं। दुनिया में युद्ध का तनाव बढ़ा है, तो पैसा अपने सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहा है। दिसंबर में समाप्त हुई तिमाही में सुधार के संकेत साफ दिखे थे, लेकिन युद्ध ने इस चालू तिमाही में सुधार की उम्मीदों को धूल में मिला दिया है।

पहली बात तो यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक विदेशी तेल पर निर्भर है। कच्चे तेल का आयात प्रभावित हुआ है, तो जाहिर है, भारतीय उद्योगों में चिंता फैल गई है। ज्यादा दिन नहीं बीते, अमेरिकी टैरिफ संकट के बावजूद हमारा बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और उसमें ऐसी कोई गिरावट नहीं दिखी थी। इसकी एक वजह यह भी है कि टैरिफ संकट के समय भारत को कच्चे तेल की आसान आपूर्ति हो रही थी। अब जब आपूर्ति प्रभावित हुई है, तो हमारे विकास की रफ्तार पर असर होता दिख रहा है। वैसे, शेयर बाजार में गिरावट का अर्थव्यवस्था पर तत्काल असर नहीं पड़ता है, लेकिन यह एक पूर्व संकेत होता है। अभी भी अगर युद्ध थम जाए, तो शेयर बाजार भी संभल जाएगा और हमारी आर्थिक वृद्धि भी पटरी पर दौड़ती रहेगी। वैसे यह अच्छी सूचना है कि रूस और ऑस्ट्रेलिया से गैस मंगाकर आपूर्ति का इंतजाम किया जा रहा है। घबराहट में जमाखोरी न करने के लिए कहा गया है। वाकई, अगर जितनी जरूरत है, उतने ईंधन का इंतजाम हम करते हुए चलें, तो तात्कालिक अभाव को संकट में बदलने से रोक पाएंगे। हालांकि, एक संकेत है कि लोग रुपया अपने पास रखने लगे हैं। तभी गुरुवार को चांदी के भाव में भी गिरावट आई और सोना भी गिरा। हालांकि, इसके लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चूंकि खुद अमेरिका भी युद्ध से तनाव में है, तो वहां बैंक ने ब्याज दरों के साथ किसी भी छेड़छाड़ से परहेज किया है।

यह आपदा सुधार का अवसर बने। हम अपनी अर्थव्यवस्था में जमाखोरी और कालाबाजारी के अवगुण देख रहे हैं। इनके पुख्ता इलाज की जरूरत है।

बहरहाल, भारत संभलकर चले, तो अभाव से पार पा लेगा। यह आपदा सुधार का अवसर बने। हम अपनी अर्थव्यवस्था में जमाखोरी और कालाबाजारी के अवगुण देख रहे हैं। इनके पुख्ता इलाज की जरूरत है। अर्थव्यवस्था में ईमानदारी सुनिश्चित हो। लगे हाथ, एक सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या हमारे बैंक ढंग से काम कर रहे हैं? ध्यान रहे, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे से भी गुरुवार को तीखी प्रतिक्रिया दिखी है। देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाता बैंक की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। अतनु के शब्दों के सहारे कहें, तो पिछले दो वर्षों में उन्होंने बैंक के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं व प्रथाएं देखी हैं, जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों व नैतिकता के अनुरूप नहीं हैं। हो सकता है, अतनु की शिकायत में अतिरेक हो, पर देश के वित्त विशेषज्ञों को परखना चाहिए कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे भारत के वित्तीय संस्थान कितने नैतिक हैं? किसी भी आर्थिक संकट से जूझने के लिए वित्तीय संस्थानों का चाक-चौबंद होना अनिवार्य है।

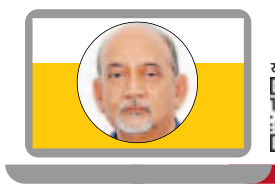

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 20 मार्च, 1951

काश्मीर का मामला

काश्मीर का प्रश्न जब भारत, पाकिस्तान और सुरक्षा परिषद के बीच उलझ रहा है, तब यह जानना रोचक और उपयोगी है कि स्वयं काश्मीर इस बारे में क्या सोच रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि जबसे बन्दर-न्याय की तरह आंग्ल-अमरीकी प्रस्ताव सामने आया है, तबसे भारत ही नहीं, स्वयं काश्मीर में भी इन हितैषियों की नीयत के बारे में सन्देह उत्पन्न हो गया है। हाल में काश्मीर से आए समाचार तथा शेर-ए-काश्मीर शेख अब्दुल्ला द्वारा अमृतसर के रोटरी क्लब में प्रकट किए गए विचार इसके सिवा और कुछ मानने की प्रेरणा नहीं करते। पीड़ित और रक्षक के बजाय उत्पीड़क और आक्रमणकारी की हिमायत ली जाने पर इसके सिवा सोचा भी क्या जा सकता है?

काश्मीर की खबरें बताती हैं कि वहां आंग्ल-अमरीकी प्रस्ताव के विरुद्ध रोष ही नहीं प्रकट किया जा रहा है, बल्कि सार्वजनिक प्रदर्शनों एवं सार्वजनिक घोषणाओं द्वारा उसको स्पष्ट रूप से ठुकराया जा रहा है। जलूस इन वाक्यों के साथ निकाले जा रहे हैं कि 'विदेशी फौजें यहां नहीं चाहिए' और 'अपने भविष्य के निर्णय में हम साम्राज्यवादी हस्तक्षेप नहीं चाहते।' और सभाओं के रुख का अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि एक में बख्शी गुलाममुहम्मद ने, जो शेख साहब के बाद काश्मीर के सर्वप्रमुख लोकनेता हैं, कहा है कि सुरक्षा परिषद के पिछले तीन साल के रवैये ने हमारा यह विश्वास पक्का कर दिया है कि उससे किसी इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक दूसरे प्रमुख लोकनेता मिर्जा अफजल बेग का यह कथन भी उपेक्षणीय नहीं, जो पंच के सुपुर्द मामला करने पर उन्होंने कहा, कि हम लाखों आदमियों का भाग्य किसी एक आदमी के हाथ में नहीं सौंप सकते।

और जहां तक भारत के साथ काश्मीर का संबंध है, बख्शीजी कहते हैं- काश्मीर की जनता ने, जिसमें अवश्य ही मुसलमान भी शामिल हैं, सन् 1947 में ही भारतीय संघ में मिलने का संकल्प प्रकट कर दिया था, जबकि भारत ने पाकिस्तान द्वारा काश्मीर पर किये गये आक्रमण से उसकी रक्षा की थी। कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान में शामिल होना चाहते तो- बख्शीजी का यह कथन ध्यान देने योग्य है- उसी समय न वे हमलावरों के साथ हो जाते? ऐसा उन्होंने नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान में शामिल होने को वे तैयार नहीं हैं।

खतरनाक मोड़ पर खाड़ी का तनाव

यहां स्कैन करें

दिनकर पी श्रीवास्तव | ईरान के पूर्व भारतीय राजदूत

होर्मुज की बाधा खत्म करने का एकमात्र तरीका है- ईरान के खिलाफ बमबारी रोकना। यह व्यावहारिक सोच नहीं है कि एक पक्ष युद्ध जारी रखे, जबकि दूसरा संयम बरते।

बीती 18 मार्च को ईरान के अस्सलुयेह स्थित पेट्रोकेमिकल केंद्र और साउथ पार्स के गैस फील्ड पर इजरायल ने हमला करके मध्य-पूर्व के युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया है। इन हमलों से तेल और गैस प्रतिष्ठानों को निशाना न बनाए जाने की अलिखित सहमति टूट गई है, जबकि ये प्रतिष्ठान यहां की आर्थिक जीवन-रेखा हैं। यह बमबारी इजरायली हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की मौत के तुरंत बाद की गई। इजरायल के हवाई हमले में ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब भी मारे गए हैं।

साउथ पार्स काफी संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि इस गैस फील्ड में कतर की भी हिस्सेदारी है। इस हमले के बाद ईरान ने भी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के तेल व गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ' पर लिखा है कि न ही अमेरिका, और न कतर को इस हमले की जानकारी थी। उन्होंने यह भी कहा है कि इजरायल साउथ पार्स पर दोबारा हमला नहीं करेगा। जाहिर है, लारीजानी की हत्या से युद्ध खत्म नहीं होने वाला। अलबत्ता, इसने पूरे क्षेत्र में संघर्ष को और भी बदतर बना दिया है। ईरान विकेंद्रीकृत सत्ता-व्यवस्था वाला देश है। वहां किसी एक नेता की हत्या से युद्ध की दिशा पर कोई असर नहीं पड़ता।

गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर चल रही बातचीत के बीच 28 फरवरी को तेल अवीव और वाशिंगटन ने मिलकर तेहरान पर धावा बोला था। 26 फरवरी को जिनेवा में तीसरे दौर की वार्ता के खत्म होने के बाद, ओमान के विदेश मंत्री अल-बुसैदी ने *सीबीएस* को दिए साक्षात्कार में कहा था कि शांति समझौता महज चंद कदम दूर है। ईरान संवर्धित यूरेनियम भंडार न रखने पर सहमत हो गया था। वह संवर्धित यूरेनियम के मौजूदा भंडार को कम करके उसे ईंधन में बदलने पर भी राजी था।

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि ईरान की मिसाइल क्षमता सीमित है और वह अमेरिका को आंख नहीं दिखा सकता। पिछले साल के युद्ध के बाद कमजोर हुए ईरान से इजरायल के 'अस्तित्व पर कोई खतरा' न था और न ही अमेरिका पर किसी 'आसन्न संकट' की बात सही थी।

अब तो अमेरिकी आतंकवाद-विरोधी केंद्र के प्रमुख जो केंट ने भी यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि ईरान से अमेरिका को 'कोई आसन्न खतरा' नहीं था। उन्होंने आगे कहा है कि 'इजरायल और उसकी ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव में ट्रंप प्रशासन ने यह जंग शुरू' की है। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने भी अमेरिकी कांग्रेस (संसद) को दिए लिखित बयान में कहा है कि पिछले साल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी हमले में 'ईरान का परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो गया है'। उन्होंने यह भी लिखा है कि 'तब से ईरान ने संवर्धन क्षमता फिर से बनाने का कोई प्रयास नहीं किया है'। ऐसे में, क्या इस युद्ध को शुरू करने का कोई औचित्य था, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को इस कदर नुकसान पहुंचा रहा है?

फिलहाल, ब्रेंट तेल के दाम, जो एक अंतरराष्ट्रीय मानक है, बढ़कर 112.83 डॉलर प्रति बैरल हो गए हैं। भारतीय कच्चे तेल बास्केट की कीमत भी 146.09 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। एशियाई बाजारों में एलएनजी की कीमत हमला शुरू होने से पहले ही दोगुनी हो गई थी। केप्लर के आंकड़ों के आधार पर तैयार *रॉयटर्स* की रिपोर्ट कहती है कि युद्ध शुरू होने से पहले इस क्षेत्र से तेल और ईंधन का निर्यात प्रतिदिन 25.13 मिलियन बैरल था, जो घटकर रोजाना 9.71 मिलियन बैरल रह गया है, यानी पहले के स्तर में करीब दो तिहाई की कमी आ गई है। इतनी भारी कमी की भरपाई किसी अन्य स्रोत से नहीं की जा सकती, जिसका मतलब है कि तेल व ईंधन की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है। कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर की वृद्धि होने से भारत के सालाना तेल आयात बिल में 14,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है।

ऐसे में, होर्मुज जलमार्ग से निर्बाध परिवहन भारत के लिए बेहद अहम है। अब तक भारतीय झंडे लगे तीन जहाज यहां से गुजरे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को अभी तक 'पूरी मंजूरी' नहीं मिली है, जिसका मतलब है कि हर जहाज के लिए अलग से अनुमति लेनी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, नाटो देशों, जापान, दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलिया से नौसैनिक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जो अमेरिकी फौज के साथ मिलकर फारस की खाड़ी को अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए सुरक्षित बनाते। मगर किसी भी देश ने सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।

इसमें चीन का रुख तटस्थ है। उसे पहले से ही ईरान से कच्चा तेल मिल रहा है। वह तो यही देखना चाहेगा कि अमेरिका कमजोर पड़े। उधर, जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह 'हमारा युद्ध नहीं है'। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो के प्रति अपनी निराशा जाहिर की है। यदि वह इस जलमार्ग में जल्द स्वतंत्र आवाजाही बहाल करना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र तरीका है- ईरान के खिलाफ बमबारी रोकना। यह व्यावहारिक सोच नहीं है कि एक पक्ष युद्ध जारी रखे, जबकि दूसरा संयम बरते।

यह गौर करने की बात है कि होर्मुज सिर्फ ईरान की सैन्य कार्रवाइयों के कारण नहीं, बल्कि दुनिया की सात बीमा कंपनियों द्वारा फारस की खाड़ी के लिए युद्ध जोखिम कवरेज बंद कर देने के कारण भी बाधित है। यह दो साल पहले लाल सागर में जहाजों पर हुए हुती हमलों से भी बदतर स्थिति है। उस समय बीमा दरें जरूर बढ़ गई थीं, पर बीमा उपलब्ध था।

साफ है, मौजूदा युद्ध खत्म होने के बाद भी स्थिति के सामान्य होने में लंबा समय लगेगा। जरूरी यही है कि ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के हमले तत्काल रोके जाने चाहिए, खाड़ी देशों पर हमले बंद होने चाहिए और फारस की खाड़ी को खोला जाना चाहिए। अमेरिका को ईरान के साथ बातचीत की मेज पर फिर से आना होगा, हालांकि गहरे अविश्वास की वजह से ईरान शायद द्विपक्षीय की जगह बहुपक्षीय वार्ता पसंद करे। अगर यह जंग जारी रही, तो विश्व विनाशकारी परिणाम भुगत सकता है। इस क्षेत्र में भारत के भी गहरे हित हैं। तेल और गैस आयात ही नहीं, खाड़ी के देश 90 लाख से अधिक भारतीयों के 'घर' भी हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सबसे पहले अपनी खेती को एआई से सुधारे भारत

यहां स्कैन करें

राहुल मथान | साइबर विशेषज्ञ

कनाडा के ओंटारियो प्रांत के वुडस्टॉक शहर स्थित टोयोटा की फैक्टरी जल्द ही अपने यहां 'डिजिट' नामक रोबोट तैनात करेगी। यह इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट है, जिसे एजिलिटी रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। यह दो पैरों वाला रोबोट गोदामों से आने वाली गाड़ियों से ऑटो पार्ट्स उतारकर प्रोडक्शन लाइन की तरफ ले जाएगा। यह वह काम है, जिसे अब तक इंसान करते रहे हैं।

टोयोटा अकेली ऐसी कंपनी नहीं है, जो रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। इंट्यूटिव सर्जिकल कंपनी के 'दा विंची' रोबोट दुनिया भर के अस्पतालों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये अब तक लाखों ऑपरेशन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पूरी तरह स्वचालित वेमो गाड़ी हर हफ्ते 1,50,000 से ज्यादा ट्रिप पूरी करती है। इसे अल्फाबेट ने बनाया है, जो गूगल की मूल कंपनी है। इसी तरह टेस्ला की ऑप्टिमस श्रेणी के ह्यूमनॉइड (इंसान जैसा) रोबोट का उत्पादन जोर-शोर से चल रहा है। अनुमान है कि इस दशक के अंत तक इनका विस्तार बड़े पैमाने पर होने लगेगा।

लेबर इकोनॉमिक्स में हाल ही में छपे एक शोध-पत्र में यह तर्क दिया गया है कि इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं और रोजगार पर इसका प्रभाव संभालना कठिन हो सकता है। भारत में इस समय 35 साल से कम उम्र के लगभग 80 करोड़ युवा तैयार हैं, जो मानव इतिहास में सबसे बड़ा 'डेमोग्राफिक बल्ज (युवा आबादी की भारी बढ़त)' है। अगर एम्बेडेड एआई (रोबोट का भौतिक रूप) ही इंसान की जगह तेजी से काम करने लगेगा, तो हमारा यह 'जनसांख्यिकीय लाभांश' तेजी से 'जनसांख्यिकीय आपदा' बन जाएगा।

भारत के सामने मौजूद कई चुनौतियों में से कृषि उत्पादकता एक मुख्य चुनौती है। खेती की जमीन का औसत आकार लगभग एक हेक्टेयर होने के कारण, भारत में कृषि न केवल अलाभकारी है, बल्कि यह एक ऐसी 'गरीबी की जाल' बन गई है, जिससे 12.5 करोड़ छोटे किसान परिवार केवल गुजारा करने को मजबूर हैं। ऐसे में, हमें इस विकास संबंधी संकट से तत्काल बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। ऐतिहासिक रूप से, हर सफल औद्योगिक अर्थव्यवस्था इसी बदलाव के दौर से गुजरी है। यानी, सबसे पहले श्रम खेतों से निकलकर कारखानों में जाता है और फिर वहां से सेवा क्षेत्र में चला जाता है। हालांकि, भारत को खेतों से कारखानों की ओर होने वाले इस संक्रमण में काफी संघर्ष करना पड़ा है।

ऐसे में, हमें खेती में ऑटोमेशन के इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था का औद्योगिक उत्पादन की ओर बदलाव तेजी से हो सके। चूंकि हमें एम्बेडेड एआई के लिए घरेलू बाजार भी विकसित करने की जरूरत है, इसलिए उन कंपनियों को बढ़ावा देना होगा, जो खेती के कामों के लिए बनाई गई मशीनों में आधुनिक एआई तकनीक को शामिल करती हैं। अगर भारत खेती से जुड़े रोबोटों के लिए दुनिया की प्रयोगशाला बन सकता है, तो वह इन मशीनों का दुनिया भर में आपूर्तिकर्ता भी बन सकता है।

हमें खेती में ऑटोमेशन के इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था औद्योगिक उत्पादन की ओर तेजी से बढ़ सके।

बेंगलुरु के एक स्टार्टअप निको रोबोटिक्स ने पहले ही एक एआई संचालित सटीक स्प्रेयर (खर-पतवार नाशक रोबोट) विकसित कर लिया है, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अलग-अलग पौधों की पहचान करता है और मिलीमीटर के स्तर तक जाकर सटीकता के साथ उन पर दवाओं का छिड़काव करता है। यह एआई से ट्रैक्टरों को उन्नत बनाकर उसको छोटी जोत के लिए भी उपयोगी बनाता है। इससे खेती में लागत और पर्यावरण को होने वाला नुकसान कम हो सकता है।

यह इस बात का सिर्फ एक उदाहरण है कि भारत कैसे खेती की मशीनों में एआई का इस्तेमाल करके उनकी कार्यक्षमता को बेहतर बना सकता है। हम कपास, मिर्च, टमाटर और प्याज जैसी फसलों के लिए डिजाइन किए गए रोबोट को देख सकते हैं। खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम ऑटोमेटेड सॉइल-सेंसिंग (मिट्टी के गुणों को मापने वाला) उपकरणों को लगाने पर विचार कर सकते हैं, जो किसानों को उनकी जमीन के बारे में लगातार और जरूरी जानकारी दे सकें। एआई-एम्बेडेड सॉइल मॉइस्चर सेंसर (मिट्टी की नमी को रोकने वाली मशीन) की मदद से खेतों में पानी और कीटनाशकों के इस्तेमाल में काफी कमी लाना संभव हो सकेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अहंकार को नष्ट करो

परमेश्वर के साथ एकात्मता ही अहंकार के नाश का दूसरा नाम है। क्या अहंकार कभी स्वयं को नष्ट करने के लिए तैयार हो सकता है? यह प्रश्न अहंकार को नष्ट करने के बजाय उसका सम्मान करने का निश्चित तरीका है। यदि आप अहंकार को खोजेंगे, तो पाएंगे कि उसका अस्तित्व नहीं है। यही उसे नष्ट करने का तरीका है।

अपने भीतर झांको, तो दिखावटी अहंकार और अज्ञान अपने आप दूर हो जाएंगे। यह 'मैं' कहां से उत्पन्न होता है? इसे अपने भीतर खोजो; तब यह विलीन हो जाता है। यही ज्ञान की खोज है। यदि प्रथम पुरुष, 'मैं' विद्यमान है, तो द्वितीय और तृतीय पुरुष, 'तुम' और 'वह' भी विद्यमान होंगे। 'मैं' के स्वरूप की खोज करने से 'मैं' का नाश हो जाता है। इसके साथ ही, 'तुम' और 'वह' का भी नाश हो जाता है। परिणामस्वरूप जो अवस्था परम सत्ता के रूप में प्रकाशमान होती है, वही हमारी स्वाभाविक अवस्था, आत्मा है।

अहम वृत्ति (मैं का विचार) टूट जाता है, जबकि अहम स्फुरण (मैं का प्रकाश) अटूट और निरंतर बना रहता है। विचारों के शांत होने के बाद प्रकाश चमकता है।

'मैं' के स्वरूप वाली व्यक्तिगत आत्मा ही अहंकार है। बुद्धि (चित्त) के स्वरूप वाले आत्म में 'मैं' का बोध नहीं होता। न ही अचेतन शरीर में 'मैं' का बोध होता है। बुद्धिमान और अचेतन के बीच प्रकट होने वाला भ्रामक अहंकार ही इन सभी समस्याओं का मूल कारण है। किसी भी प्रकार से इसका नाश होने पर, जो वास्तव में विद्यमान है, वह अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। इसे ही मोक्ष कहते हैं। जैसे कूड़ा फेंकने वाले को उसका विश्लेषण करने या यह देखने की आवश्यकता नहीं होती कि वह क्या है, वैसे ही आत्मा को जानने वाले को श्रेणियों की संख्या गिनने या उनके गुणों की जांच करने की आवश्यकता नहीं होती; उसे केवल उन श्रेणियों को पूरी तरह से त्याग देना होता है, जो आत्मा को छिपाती हैं। संसार को एक सपने के समान समझना चाहिए।

प्रथम कारक (जो कर्ता कारक है) प्रकट हो या न हो, जिन वाक्यों में अन्य कारक प्रकट होते हैं, उनका आधार प्रथम कारक ही होता है; इसी प्रकार, हृदय में उत्पन्न होने वाले सभी विचार, प्रथम मानसिक गुण 'मैं' (अहंकार) और 'मैं शरीर हूं' (मैं शरीर हूं) के बोध पर आधारित होते हैं; अतः अहंकार का उदय अन्य विचारों के उदय का कारण व स्रोत है; इसलिए यदि संसार (जन्म के बंधन) के मायावी वृक्ष की जड़, अहंकार रूप के आत्म-अभिमान का नाश हो जाए, तो अन्य सभी विचार उखड़े हुए वृक्ष की तरह पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे।

'मैं' के स्वरूप की खोज करने से 'मैं' का नाश हो जाता है। 'तुम' और 'वह' का भी नाश हो जाता है। तब जो चीज परम सत्ता के रूप में प्रकाशमान होती है, वही हमारी स्वाभाविक अवस्था, आत्मा है।

हमें केवल उस शाश्वत सत्य की खोज करनी चाहिए, जो बाधाओं के कारण अज्ञात है। अज्ञान ही बाधा है। इसे दूर करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।

रमण महर्षि

उर्सुला वॉन डेर लेयेन | अध्यक्ष, ईयू आयोग

मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध के परिणाम वैश्विक हैं और कूटनीतिक समाधान खोजने की दिशा में काम करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, जहां बहुपक्षीय सहयोग हो।

कृषि प्रधान देश में गौरैयों की यह दशा

गौरैया, वह छोटी सी चिड़िया जो कभी हमारी छतों, आंगनों और खेतों की सच्ची सखी थी, आज लुप्त होने के कगार पर खड़ी है। 20 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व गौरैया दिवस हमें इस छोटे से जीव के प्रति हमारी उदासीनता का आईना दिखाता है। यह मात्र एक पक्षी नहीं, बल्कि हमारी स्मृतियों का जीवंत प्रतीक है। आज जब हम आधुनिकता की चकाचौंध में डूबे हैं, गौरैया की कमी हमें भावनात्मक शून्यता का एहसास कराती है।

गौरैया का साहित्यिक चित्रण भारतीय साहित्य में इतना गहरा है कि वह कविता, कहानी और लोकगीतों की आत्मा बन गई है। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास ने अपनी पदावलियों में गौरैया को कृष्ण की लीलाओं का साक्षी बनाया है। 'गौरैया चुके ना कान्हा के गुन' जैसी पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि कैसे यह चिड़िया भगवान के प्रेम में लीन होकर चहचहाती थी। कबीरदास ने भी दोहे में गौरैया को सादगी और भक्ति का प्रतीक बताया- गौरैया गुनी चुगै बीज, कागा खाए सब खेत। आधुनिक साहित्य में महादेवी वर्मा की कविताओं में गौरैया प्रकृति के संगीत का माध्यम बनी है। उनके 'नीहार' काव्य-संग्रह में गौरैया की चहचहाहट वर्षा की पूर्वसूचना देती है, जो मानवीय भावनाओं से जुड़ती है। लोकगीतों में तो गौरैया प्रेमिका का रूप धारण कर लेती है। 'गौरैया री आजा रे, मोर, संग बसे रे' जैसे गीत खेतों में गूंजते थे, जहां यह चिड़िया विवाह के मंगल गान का हिस्सा होती थी। इस लिहाज से देखें, तो गौरैया की विलुप्ति आपदा जैसी है, जो मानवीय लापरवाही का परिणाम है।

बर्डलाइफ इंटरनेशनल के अनुसार, भारत में गौरैया की संख्या 1960 के दशक से 60-70 प्रतिशत घटी है। हरियाणा जैसे कृषि-प्रधान राज्य में यह कमी और चिंताजनक है। एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली-एनसीआर में इसकी आबादी 90 प्रतिशत तक कम हो गई है। इसके कुछ कारण हैं। पहला- कीटनाशकों का अंधाधुंध छिड़काव। गौरैया मुख्यतः कीड़े-मकोड़ों पर निर्भर है। खेतों में धान व अन्य फसलों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक गौरैया के घोंसलों तक पहुंच जाते हैं, जिससे उसके अंडे और चूजे मर जाते हैं। दूसरा, मोबाइल टावरों की विकिरण। अध्ययनों की मानें, तो रेडिएशन से गौरैया के नेविगेशन सिस्टम बिगड़ जाते हैं। तीसरा है- शहरीकरण, और चौथा कारण है- जलवायु परिवर्तन। लिहाजा, आज जब हम गौरैया दिवस मना रहे हैं, तो यह महज एक औपचारिक आयोजन नहीं होना चाहिए। अलबत्ता, यह दिन हमें याद दिलाता है कि यदि हम अभी भी नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियां शायद गौरैया को केवल किताबों और तस्वीरों में ही देख पाएंगी।

जयदेव राठी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

विश्व गौरैया दिवस

गांवों में आज भी खूब दिखती यह चिरैया

बड़े अच्छे से याद है, बचपन में जब गौरैया घर के आंगन में आती थीं, तो जतन करके उन्हें पकड़ लेते थे और रूह वाला गुलाबी/ हरा रंग घोलकर उन पर लगा देते थे। फिर अपनी-अपनी चिड़िया की पहचान कर उन्हें छोड़ देते थे। थोड़ी देर तो वह डरी-सहमी सी मुंडेर पर बैठी रहतीं, फिर सब कुछ भूलकर चुग्गा चुगने लगतीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह गर्मी की छुट्टियों का हमारा प्रिय शगल हुआ करता। गौरैया को रंगना और फिर अगले दिन कौन सी वापस आई, कौन नहीं, इसकी गणना करना।

फिर हम बड़े हो गए और गौरैया यादों में रह गई बस। कुछ सालों पहले कहीं पढ़ा कि गौरैया विलुप्ति के कगार पर है। यह हमारे लिए एक अविश्वसनीय खबर थी। हर घर की मुंडेर पर, हर खेत-खलिहान की रौनक गौरैया विलुप्त कैसे हो सकती है? हो सकता है, लेख लिखने वाले ने शहरों के आधार पर लिख दिया होगा, वह ग्रामीण जीवन से अनभिज्ञ होंगे, जहां गौरैया घर के सदस्य की तरह रहती हैं? हालांकि, अब हमने गौर करना शुरू किया कि क्या सच में ऐसा है? ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। मैं जहां रह रही थी, वहां गौरैया नियमित दिख रही थीं, लेकिन अब मैंने उनके लिए नियमित रूप से दाना-पानी रखना शुरू किया। यह उस खबर का ही असर था।

मैं दिन में तीन बार यह काम करती और गौरैया को जैसे समय याद हो गया हो, वह नियत समय पर प्रतिदिन आ जातीं। छुट्टी वाले दिन मैं देर तक सोती, तो चिरैया बरामदे में लगे तार तक आ जातीं और तब तक शोर करतीं, जब तक कि उनके नियत स्थान पर मैं दाना डाल नहीं देती। मुझे उन चिड़ियों से इतना लगाव था कि जब मैं छुट्टियों में घर आती, तो चावल का डिब्बा रखकर और भाभी की ड्यूटी लगाकर आती। वह भी तीनों समय ऐसा ही करतीं। यह समय खूब लंबा चला और गौरैया व मेरी दोस्ती भी, लेकिन एक दिन अचानक ट्रांसफर लेकर मैं यहां शहर में आ गई और यहां गौरैया सच में कम दिखती हैं। हालांकि, गांव में आज भी गौरैया खूब हैं और विलुप्त जैसा कुछ मुझे नहीं लगता है।

फिर भी, हमें इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि जो हैं, उनके लिए दाना-पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, उनके लिए घोंसले बनाने चाहिए, खासकर शहरों के मकानों में, क्योंकि यहां इन्हें प्राकृतिक वास और दाना उपलब्ध नहीं है। इसलिए, ये सब उपलब्ध कराने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति का संरक्षण करना है, तो उसके हर घटक का ध्यान हमें रखना ही होगा।

पूनम, टिप्पणीकार

कब और क्यों पिएं अल्कलाइन पानी

अभी तक सेहत के लिए खूब पानी पीना जरूरी था। अब अधिक पीएच वाले अल्कलाइन वॉटर की सलाह दी जा रही है। सेलेब्रिटीज से लेकर युवाओं और फिटनेस प्रेमियों में इसका चलन तेजी से बढ़ा है। क्या वाकई हर किसी को इस खास पानी की जरूरत है? इस बारे में शरीर का पीएच विज्ञान क्या कहता है? अल्कलाइन वॉटर की जरूरत के बारे में बता रही हैं, आहार व पोषण विशेषज्ञ कविता देवगन

आजकल हमारी डाइट मुख्य रूप से 'एसिडिक' (अम्लीय) हो गई है। अत्यधिक प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद खाने की चीजों के सेवन से शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं, जो सूजन और विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। जब हम जंक फूड खाते हैं, तो शरीर उस कचरे से निपटने के लिए बहुत अधिक एसिड बनाता है, जिससे पेट का पीएच (पोटैंशियल ऑफ हाइड्रोजन) संतुलन बिगड़ता है। इसी से निपटने के लिए इन दिनों अल्कलाइन (क्षारीय प्रकृति) की अधिकता वाली खाने-पीने की चीजों का चलन बढ़ रहा है। अल्कलाइन वॉटर इसी में से एक है।

पहले जानें पीएच का गणित

हमारे शरीर का पीएच स्तर 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें 7 को 'न्यूट्रल' माना जाता है। सात से ऊपर का स्तर शरीर के अल्कलाइन (क्षारीय) होने का संकेत है। वहीं पीएच 7 से कम होना 'एसिडिक' होने का संकेत है। हमारे शरीर का पीएच जब अल्कलाइन होता है, तो शरीर कुशलता से काम करता है, जबकि एसिडिक शरीर रोगों का घर बन जाता है। पीएच स्तर कम होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, दिमागी धुंध, पाचन समस्याएं (जलन और गैस) और वजन बढ़ने जैसे लक्षण दिखते हैं। कभी-कभी यह अनिद्रा, किडनी की समस्या और ब्लड शुगर के असंतुलन जैसे गंभीर मुद्दों का कारण भी बन सकता है। यही कारण है कि ताजे फल, हरी सब्जियां और जूस जैसी अल्कलाइन डाइट लेना महत्वपूर्ण है।

क्या अल्कलाइन वॉटर वाकई असरदार

अल्कलाइन वॉटर का विचार सुनने में बहुत वैज्ञानिक लगता है कि उच्च पीएच वाला पानी पीने से शरीर अल्कलाइन हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि हमारा शरीर अपने पीएच स्तर को खुद ही बहुत कड़ाई से नियंत्रित करता है। आप जो पानी पीते हैं, उसका इस संतुलन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। हालांकि, कुछ शोध बताते हैं कि यह एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों में राहत देने में मदद कर सकता है। अगर आपको अल्कलाइन पानी पसंद है, तो आप पिएं। सामान्य तौर पर यह सुरक्षित है। पर यह विषैले तत्वों को बाहर करना, वजन कम करना या रोगों से बचाने वाला कोई जादुई पानी नहीं है।

ध्यान रखें: बहुत ज्यादा नीबू डालना रिफ्लक्स बढ़ा सकता है। लंबे समय तक बेकिंग सोडा वाला पानी शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है। इसी तरह सेब का सिरका भी अम्लीय प्रकृति का होता है।

क्या खाएं और क्या नहीं?

नीबू का कमाल

नीबू का पीएच स्तर 2 से 2.8 होने के कारण इसे एसिडिक श्रेणी में रखा जाता है। पर, नीबू अम्लीय होते हैं, लेकिन शरीर में जाने के बाद ये क्षारीय प्रभाव डालते हैं। गर्म पानी के साथ नींबू लेना शरीर को डिटॉक्स करने और सेल्युलाइट (त्वचा के नीचे जमा जिद्दी चर्बी) कम करने में मदद कर सकता है। ऐसे में सुबह उठते ही गुनगुने नीबू पानी का सेवन करें। नीबू में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स, खासकर विटामिन सी, लिवर को पाचक एंजाइम बनाने में मदद करता है। इससे पाचन तंत्र बेहतर ढंग से काम करता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो डिहाइड्रेशन से बचाते हैं।

खूब खाएं ये फल-सब्जियां

- सेब, केला, बेरीज, अंगूर, तरबूज, नीबू व नाशपाती खाएं।
- पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा, करेला व बैंगन खाएं।
- जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां खाएं।

इनसे बचें

- डिब्बाबंद और जंक फूड से दूर रहें। कृत्रिम रूप से पकाए गए फल-सब्जियां न खाएं, जैसे कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू अम्लीय हो जाते हैं। ताजे फल-सब्जियां खाएं।
- बहुत मसालेदार खाने और सॉफ्ट ड्रिंक्स से बचें। इनका पीएच लगभग 3.4 होता है, जो बहुत अम्लीय होता है
- खाने के साथ या खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स न लें। हमारे शरीर के पाचक एंजाइम्स 37 डिग्री तापमान पर बेहतर काम करते हैं। ठंडे पेय पदार्थों से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है। भोजन सही से नहीं पचता।
- बहुत ज्यादा कॉफी से बचें।
- धूम्रपान छोड़ दें। निकोटीन और कैफीन दोनों अम्लता बढ़ाते हैं।

होड़ में न फंसें, शरीर की जरूरत समझें

अल्कलाइन के नाम पर फैली गलत धारणाओं में न आएं। हर समय बहुत अधिक पीएच (10 से ऊपर) वाला पानी पीना या पूरी तरह से उस पर निर्भर रहना पाचन तंत्र बिगाड़ सकता है या खनिजों के अवशोषण में बाधा डाल सकता है। कुछ मामलों में झुनझनी, जी मिचलाना या ऐंठन की समस्याएं हो सकती हैं। त्वचा व किडनी रोग विशेषज्ञ की सलाह से ऐसा करें। अगर क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स है या एक खिलाड़ी हैं, जिन्हें तुरंत हाइड्रेशन व ताजगी चाहिए, तब आप इसे पिएं। अन्य मामालों में आप साफ सामान्य पानी पिएं। पूरी तरह इस पर ही निर्भर न रहें। विज्ञान को समझें। सेहत की बेहतरी के लिए जरूरी है, आप आहार की गुणवत्ता पर ध्यान दें, खूब पानी पिएं, अच्छे पाचन और साबुत अनाज से मिलने वाले खनिज पर ध्यान दें।

स्पिरुलिना और जौ की घास

क्लोरोफिल से भरपूर स्पिरुलिना और हरी जौ के रस का सेवन करना फायदेमंद है। इससे शरीर की क्षारीय प्रकृति संतुलित रखने में मदद मिलती है। मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। इन्हें पानी में मिलाकर पिएं।

आंवला
आंवला भी शरीर की क्षारीय प्रकृति को संतुलित रखता है। रोज एक चम्मच आंवला पाउडर पानी में मिलाकर लें।

खमीर युक्त चीजें
रोजाना के आहार में प्रोबायोटिक और खमीर युक्त चीजें शामिल करें। दही, इडली, डोसा, छाछ, ढोकला, कांजी, अचार, किम्ची व कोम्बूचा आदि खाएं।

घर पर तैयार करें अल्कलाइन वॉटर

खीरा-पुदीना पानी (ठंडा और आराम दायक)

विधि: 1 लीटर पानी में 5–6 खीरे के टुकड़े और कुछ-कुछ पुदीने की पत्तियां डाल कर रख दें। दिनभर इस पानी को पिएं।
लाभ: शरीर को नमी देता है। पेट में भारीपन और अफारे में आराम आता है। एसिडिटी में आरामदायक और शरीर को ठंडक देता है।

अदरक वाला पानी (सूजन रोधी)

विधि: ताजा अदरक के कुछ टुकड़े, एक लीटर पानी में उबाल लें। इस पानी को गुनगुना पिएं।
लाभ: इससे पाचन में मदद मिलती है और एसिड रिफ्लक्स में राहत। हालांकि, इसे कम मात्रा में ही पिएं।

सौंफ का पानी (पाचन के लिए बेहतरीन)

विधि: 1 चम्मच सौंफ को 1 लीटर गुनगुने पानी में रात भर भिगो लें। सुबह इस पानी को हल्का उबालकर ठंडा करके पिएं।
लाभ: एसिडिटी, गैस और जलन में राहत मिलती है।

जीरा पानी (बढ़ाए पाचन क्षमता)

विधि: 1 चम्मच जीरा, 1 लीटर पानी उबालें, ठंडा करें। थोड़ा-थोड़ा पिएं।
लाभ: पाचन में मदद। पेट का भारीपन कम होता है।

नारियल पानी और सादा पानी मिक्स (इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन)

विधि: आधा कप नारियल पानी में आधा कप सादा पानी मिलाकर पिएं।
लाभ: पोटैशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है। शरीर हाइड्रेट रखता है

तुलसी का पानी (सूजन रोधी)

विधि: 5–6 तुलसी की पत्तियां, 1 लीटर पानी में कुछ घंटों के लिए भिगोएं। इस पानी को पिएं।
लाभ: सूजन कम करने में सहायक। पेट और गले के लिए आरामदायक।

चिया पानी (आंतों के लिए फायदेमंद)

विधि: 1 चम्मच चिया सीड्स, 1 गिलास पानी में, 15–20 मिनट भिगोएं, फिर बीज समेत पिएं।
लाभ: फाइबर से भरपूर ये पानी आंतों की सेहत बेहतर बनता है। पेट भरा हुआ महसूस होता है।

उम्र के हर दौर में कीजिए दांतों की देखभाल

दांतों और मसूड़ों की लंबे समय तक सलामती बनी रहे, इसके लिए हमें इलाज से ज्यादा बचाव और अच्छी आदतों पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि उम्र के हर दौर में अपने मुंह की देखभाल कैसे करें–

कैविटी (कीड़ा लगना) और संक्रमण जैसी मुख की समस्याएं हृदय और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं। दंत चिकित्सक डॉ. मिलिंद करमरकर के अनुसार, 'दांतों की देखभाल कोई एक दिन की साफ-सफाई का काम नहीं है। यह जीवनभर की अच्छी आदतों का परिणाम है।

उम्र के अनुसार करें ये बदलाव

बच्चे (शिशु से 12 वर्ष तक)

नवजात बच्चों के मसूड़ों को दूध पिलाने के बाद मुलायम गीले कपड़े से साफ करें। एक साल का होने पर डेंटिस्ट को दिखाएं। थोड़ा बड़े होने पर उन्हें सही तरीके से ब्रश करना सिखाएं। उन्हें चीनी कम खिलाएं। सब्जियां, फल व पनीर आदि खिलाएं।

किशोर (13-19 वर्ष)

फ्लोराइड टूथपेस्ट से दिन में दो बार ब्रश करना जरूरी। इसके अलावा समय-समय पर फ्लोराइड माउथवॉश का इस्तेमाल कैविटी से सुरक्षा देता है और सांसों को ताजा रखता है। अगर दांत टेढ़े-मेढ़े हैं, तो इस उम्र में विशेषज्ञ की सलाह लेना सही रहता है।

वयस्क (20-64 वर्ष)

हर छह महीने में डेंटल क्लीनिक जाएं, ताकि समस्याओं का शुरुआती स्तर पर पता चल सके।

संवेदनशील दांतों के लिए विशेष फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग करें, जो मसूड़ों को भी सुरक्षा दे। हर रोज सुबह और रात को ब्रश जरूर करें। अम्लीय पेय और अत्यधिक मीठे से परहेज करें।

बुजुर्ग (65 वर्ष और अधिक)

उम्र बढ़ने या विभिन्न दवाओं के कारण मुंह सूखने की समस्या हो सकती है। इसके समाधान के लिए डेंटिस्ट से बात करें। नरम ब्रिसल्स वाले ब्रश का उपयोग करें, ताकि मसूड़ों को नुकसान न पहुंचे।

उम्र से जुड़ी दांतों और मुख की समस्याओं पर नजर रखने के लिए नियमित चेकअप करवाते रहें।

क्यों जरूरी है ओरल हेल्थ?

गंभीर बीमारियों से बचाव: अच्छी साफ-सफाई से दांतों व मसूड़ों पर प्लाक नहीं जमता, जिससे दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारियां दूर रहती हैं।

दांत गिरने से रोकना: एक शोध के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के 3 में से 1 वयस्क अपने छह या उससे अधिक दांत खो चुके होते हैं। नियमित सफाई इस जोखिम को कम करती है।

बेहतर पाचन: स्वस्थ दांतों से भोजन ढंग से चबा पाते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है।

खराब ओरल हाइजीन के कारण बैक्टीरियल निमोनिया, हृदय रोग, गर्भावस्था की जटिलताएं और सेप्सिस जैसी गंभीर स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं।

सवाल-जवाब

सिर दर्द के कई कारण, सही जांच जरूरी

डॉ. पुलिन गुप्ता
डायरेक्टर व प्रोफेसर (मेडिसिन) राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली

■ **सवाल : मेरे पिता जी की उम्र 60 साल है। उन्हें कभी-कभी हल्का सिर दर्द और चक्कर जैसा लगता है। शरीर में कमजोरी रहती है। बाकी समय वह सही रहते हैं। उनका बीपी भी सही है। हमें क्या करना चाहिए?**

जवाब: अगर किसी को सिर में हल्का दर्द रहता है और उनकी उम्र 60 साल है, तो सबसे पहले आंखों के डॉक्टर को दिखाएं। वे फंडस जांच करवा सकते हैं। कई बार दिमाग में गांठ होती है, तो दिमाग के पानी का दबाव बढ़ जाता है। फंडस जांच में आंखों के डॉक्टर देखते हैं कि यह पैपिलीएडेमा है या नहीं।

इसके अलावा, वह यह देख सकते हैं कि मरीज की आंख का नंबर ठीक है या नहीं। रिफ्रैक्टिव एरर माथे के आगे के हिस्से में दर्द का सबसे आम कारण होता है। इस उम्र में काला मोतिया की समस्या भी हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर आंख का प्रेशर जांच करेंगे कि सिर दर्द की वजह आंख का प्रेशर बढ़ना तो नहीं है। अगर ये सब ठीक है, तो इसके अलावा हमें यह देखना होगा कि उनकी नींद का पैटर्न कैसा है? उन्हें नींद कैसी आती है? कहीं मन विचलित तो नहीं या वे ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं हैं? यह भी सिरदर्द का कारण हो सकता है। इसके अलावा बीपी की जांच जरूरी है। बीपी बढ़ने पर भी ऐसा होता है। अगर यह सब ठीक है तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। कभी-कभी रंगीन एक्स-रे की जरूरत पड़ती है। सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस में चक्कर आ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सिर में दर्द नहीं होता। जहां तक कमजोरी की बात है, बीपी, शुगर और विटामिन B12 की जांच कराएं। संतुलित आहार लें। खूब पानी पिएं। फल खाएं। व्यस्त रहें और खूब नींद लें।

■ **सवाल : मेरी उम्र 50 साल है। गाउट और यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है। वजन बहुत ज्यादा है और रोजे चल रहे हैं। बीते पांच दिनों से टखने में तेज दर्द व सूजन है। खासतौर पर शाम के समय लाली बढ़ जाती है। रोजे के दौरान भी सामान्य चावल व कद्दू की डाइट ले रहा हूं। इफ्तार और सहरी के बीच पानी भी खूब पी रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए?**

सबसे पहले यह समझें कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण गाउट होता है। कई बार गाउट क्रॉनिक स्तर पर होता है, जिसमें मरीज दवा लेता है और वह ठीक रहता है। पर कभी-कभी गाउट का 'अटैक' पड़ता है,

तो यूरिक एसिड जोड़ों में जमा हो जाता है। इस कारण जोड़ों में अत्यधिक दर्द, लालिमा और सूजन आ जाती है। यहां तक कि हवा लगने पर भी तेज दर्द महसूस होता है। कुछ गाउट की दवाएं आती हैं, जो पेशाब के जरिये यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल देती हैं। पर, अगर गाउट अटैक के समय में तुरंत यह दवाएं दी जाती हैं तो यूरिक एसिड जोड़ों से निकलकर किडनी में फंस सकता है, जिससे किडनी में पथरी होने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे मामले में मरीज को पहले कुछ दिन दर्द निवारक दवाएं, स्टेरॉएड या अन्य सहायक दवाएं दी जाती हैं, जिससे अटैक को कंट्रोल किया जाता है। जब 10 से 15 दिन बाद अटैक शांत हो जाए, तब यूरिक एसिड कम करने की दवा शुरू की जाती है। यह दवाएं आमतौर पर जीवन भर लेनी पड़ती हैं, इन्हें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए।

लोगों में यह भ्रांति है कि गाउट में दालें बंद कर देनी चाहिए। वैज्ञानिक रूप से, वनस्पति जन्य प्रोटीन के स्त्रोतों जैसे कि दालें आदि से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, इसलिए दालें खाना बंद न करें। पशु जन्य प्रोटीन के स्त्रोतों से परहेज रखना चाहिए, ये अवश्य यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। नशीली चीजें जैसे अल्कोहल, व्हिस्की और बियर का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक कैफीन युक्त चीजें जैसे कॉफी और चॉकलेट कम खाएं। खूब पानी पिएं और अपनी दवाएं समय पर लें। अगर तकलीफ ज्यादा है, तो अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं।

भेजें अपने सवाल

सेहत से जुड़े सवाल **tanmanhindustan@gmail.com** पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं–

तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष: परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। रहन-सहन कष्टमय होगा।

वृष: कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से लाभ में वृद्धि होगी। भागदौड़ बढ़ेगी।

मिथुन: मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में भागदौड़ बढ़ सकती है। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कर्क: मन प्रसन्न रहेगा। बातचीत में संतुलित रहें। पिता व संतान की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। भागदौड़ अधिक रहेगी।

सिंह: मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ में वृद्धि भी होगी।

कन्या: आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। सेहत का ध्यान भी रखें। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। मित्रों से सहयोग मिलेगा।

तुला: आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी हो सकता है। संयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। धर्म-कर्म में व्यस्तता बढ़ सकती है। यात्रा पर भी जा सकते हैं।

वृश्चिक: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से संपत्ति में वृद्धि के योग बन रहे हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी। खर्च बढ़ सकते हैं।

धनु: शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं। तरक्की के योग हैं।

मकर: मन परेशान हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आय के साधन भी बन सकते हैं।

कुंभ: संतान सुख में में वृद्धि होगी। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। वस्त्र उपहार में मिल सकते हैं। पिता का साथ मिलेगा।

मीन: मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। किसी पैतृक संपत्ति के लिए पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। सचेत रहें। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

20 मार्च शुक्रवार, **शक संवत्** : 29 फाल्गुन (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग** : 07 चैत्र मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम** : 30 रमजान, 1447, **विक्रमी संवत्** : चैत्र शुक्ल द्वितीया तिथि रात्रि 02.31 बजे तक पश्चात तृतीया तिथि, रेवती नक्षत्र रात्रि 02.28 बजे तक पश्चात अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में रात्रि 02.28 तक उपरांत मेष राशि में। **सूर्य उत्तरायण।** सूर्य उत्तर गोल। वसंत ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। चंद्रदर्शन। पंचक समाप्त रात्रि 02.28 मिनट। उत्तर गोल प्रारंभ। गंडमूल विचार।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

मेरा बहुत समय फालतू की बातों में जाता है। मैं सोशल मीडिया पर बहुत समय बर्बाद करता हूं। समय का सदुपयोग नहीं कर पाता। –अमित कुमार, रेवाड़ी

- आप अपने घर या ऑफिस की दक्षिण पश्चिम दिशा चेक करें। आमतौर पर जिनकी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में दोष होता है, उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
- ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं और उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब हो जाता है। इसके अलावा उनका समय अनावश्यक बातों और कार्यों में बर्बाद हो जाता है। आप इस दिशा में लिंगम रख सकते हैं। यहां एक ऐसा चित्र लगाएं, जिसमें पत्थर के ऊपर पत्थर रखे होते हैं।

वर्ग पहेली : 8273

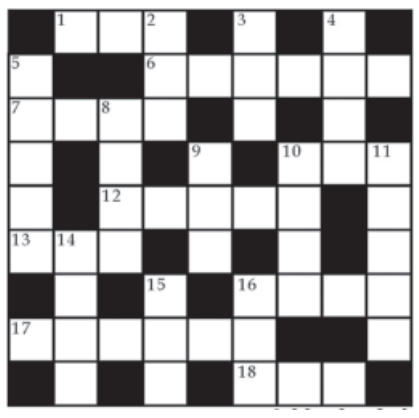

बाएं से दाएं
1. सहज मिलने वाला; सुगमतापूर्वक उपलब्ध (3)
6. जलदाता; जल प्रदान करने वाला (6)
7. निकाला जाना; छोड़ देना; धन देकर देनदारी से पाई गई मुक्ति; बंधन से मुक्ति (4)
10. तह; पपड़ी; सतह; स्तर (3)
12. निशुल्क सेवा करने वाला; निःस्वार्थ भाव से कार्य करने वाला (5)
13. आंच से गरम होना; तप्त होना; तपस्या करना (3)
16. अप्रतिष्ठा; अपमान; तिरस्कार (4)
17. अक्षम करना; असहाय करना; साधनहीन करना (3,3)
18. शिथिल करना; पस्त करना (3)

ऊपर से नीचे
2. आराध्य की स्तुति हेतु रचित पद; आराधना; (3)
3. कुरीति; गलत रिवाज; बुरी प्रथा (3)
4. कर जो दिया जाना है; कर देयता (2,2)
5. अपूर्ण; अप्रस्फुटित; अवर्धित; जिसका विकास न हुआ हो (5)
8. उंगलियां फोड़ना; अलग करना; दूर करना; तोड़ना; भंजित करना (4)
9. जलसेना (3)
10. रंधवाना; तैयार करवाना; परिपक्व कराना (4)
11. आर्द्र करना; गीला करना; सिंचित करना; ठंडक पैदा करना; स्निग्ध करना (2,3)
14. परख; परिचय (4)
15. भारी वस्तु से आघात करना; पीटना; मारना (3)
16. असहाय; आश्रयहीन; लावारिस (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8272

1 म	न	2 च	ल	3 ना	■	4 घु	■	5 जा
तां	■	ह	■	6 प	ल	ट	जा	ना
7 त	र	ल	ता	■	■	घु	■	मा
र	■	प	■	8 वि	9 क	ट	■	ना
■	10 श	ह	11 द	■	12 न	क	ली	■
13 ब	■	14 ल	ल	ना	■	र	■	15 अ
ह	■	र	■	■	16 आ	म	ज	न
17 क	ल	ह	का	18 र	■	र	■	म
ना	■	ना	■	19 से	या	ना	हो	ना

सुडोकू : 8255

* आसान

		7				9		
2			7		9			8
	3	5	4		1	2	7	
5			3		8			2
1			2		4			7
	6	3	9		2	5	4	
7			1		6			3
		2				7		

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8254

3	7	2	6	4	1	9	5	8
4	1	5	8	7	9	2	3	6
6	9	8	2	5	3	4	7	1
8	6	9	7	2	4	5	1	3
1	3	7	5	9	6	8	2	4
5	2	4	3	1	8	7	6	9
9	5	1	4	6	2	3	8	7
2	4	3	1	8	7	6	9	5
7	8	6	9	3	5	1	4	2

Machine Translated by Google

आग और रोष

ईरान में डोनाल्ड ट्रंप के गलत अंदाज़े से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है । नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में मौत और तबाही ला दी है।

बी एशिया और पूरे एशिया में आर्थिक तबाही

28 फरवरी को ईरान पर एक गलत सोच वाला, गैर-कानूनी युद्ध शुरू करके दुनिया को चौंका दिया। बीस दिन बाद भी, ईरान इज़राइल और पड़ोसी फारस की खाड़ी के देशों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहा है, जहाँ US बेस हैं। ईरान के होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने और खाड़ी देशों में तेल और गैस की जगहों पर जवाबी हमलों से एनर्जी की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे ग्लोबल इकॉनमी को खतरा है। विडंबना यह है: मिस्टर ट्रंप, जिन्होंने दो बार प्रेसिडेंट का पद जीता, अमेरिका के "हमेशा के लिए युद्धों" का विरोध करके कैंपेन चलाया, अब इज़राइल के कहने पर US को एक और खतरनाक लड़ाई में धकेल दिया है। सरकार बदलने का शुरुआती मौका खत्म होने के बाद, मिस्टर ट्रंप ने अमेरिका को एक और खतरनाक लड़ाई में धकेल दिया है।

ट्रंप ने मिले-जुले सिग्नल भेजे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बातचीत की इजाज़त दी है; जब ईरान ने मना कर दिया, तो उन्होंने देश के मुख्य एनर्जी एक्स-पोर्ट टर्मिनल, खार्ग आइलैंड पर हमले का ऑर्डर दिया। फिर इज़राइल ने अली लारीजानी की हत्या करके झगड़े को और बढ़ा दिया, जो ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी और युद्ध की कोशिशों को लीड कर रहे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच एक अहम कड़ी थे, साथ ही ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर और बासिज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर भी थे। बुधवार को, इज़राइल ने ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड पर हमला करके एक और रेड लाइन पार कर ली, जिससे कतर, UAE और सऊदी अरब में एनर्जी साइट्स पर ईरानी हमले शुरू हो गए।

युद्ध शुरू होने से पहले ही कई लोगों ने चेतावनी दी थी कि ईरान पर बड़ा हमला करने से इलाके में संकट पैदा हो सकता है। मिस्टर ट्रंप, जो हाल तक नोबेल शांति पुरस्कार चाहते थे, बिना किसी परवाह के आगे बढ़ गए। एक दर्जन से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए, सौ से ज़्यादा घायल हुए, US बेस पर हमला हुआ, और तेल, गैस और फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ गईं, अब उन्हें अपने देश में बढ़ते राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 17 मार्च को, जो केंट ने नेशनल काउंटररेरिज्म सेंटर के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया, यह दावा करते हुए कि US "इज़राइल और उसकी ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव के कारण" युद्ध में शामिल हुआ। अब यह साफ है कि मिस्टर ट्रंप को इतनी लंबी लड़ाई की उम्मीद नहीं थी। भले ही मिस्टर ट्रंप जीत की घोषणा करना चाहें और बमबारी खत्म करना चाहें, उनके सामने दो मुश्किलें हैं: ईरान खाड़ी और इज़राइल में टारगेट पर हमला करना जारी रख सकता है; और होर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद रहेगा। अगर मिस्टर ट्रंप और ज़्यादा तनाव बढ़ाना चाहते हैं, तो वे ईरान में ज़मीनी सैनिक भेज सकते हैं, जो बहुत जोखिम भरा जुआ है, या वे इस इलाके के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक लड़ाई बढ़ा सकते हैं, जिससे ग्लोबल इकॉनमी कमज़ोर हो सकती है। एकमात्र सही ऑप्शन डिप्लोमेसी है। मिस्टर ट्रंप को ईरान से एक मीडिएटर के ज़रिए जुड़ना चाहिए, जिसकी सभी पक्षों तक पहुँच हो और एक ऐसा डील करना चाहिए जो दोनों के लिए काम कर सके। तेहरान को ग्लोबल इकॉनमी को बंधक बनाना बंद करना चाहिए और सीज़ेयर के हिस्से के तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना चाहिए। अगर US भविष्य में अमेरिकी या इज़राइली हमले के खिलाफ भरोसेमंद गारंटी देता है, तो डील अभी भी मुमकिन हो सकती है।

रास्ता भटक जाना

इसरो को अगली दूसरी पीढ़ी के सैटेलाइट लॉन्च करने से पहले x मुद्दे सुलझाने होंगे

मैं एसआरओ का नाविक समूह, जिसके लिए उसने 2013 से 11 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, परिचालन संबंधी संकट में है। केवल तीन उपग्रह ही स्थिति, नेविगेशन और समय (पीएनटी) सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बचे हैं, जिससे समूह भारतीय उपमहाद्वीप पर अमेरिका के जीपीएस सिस्टम की जगह लेने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ है। एक पीएनटी समूह के लिए कम से कम चार पीएनटी-सक्षम उपग्रहों की आवश्यकता होती है, और भारत के पास केवल चार थे जब तक कि इसरो ने नहीं कहा कि आईआरएनएसएस-1एफ उपग्रह पर लगी परमाणु घड़ी 13 मार्च को विफल हो गई। समूह के पहली पीढ़ी के उपग्रह स्विस कंपनी स्पेक्ट्राटाइम द्वारा बनाई गई रुबिडियम परमाणु घड़ियों का उपयोग करते हैं, और जो विफलता से ग्रस्त रही हैं। दूसरी पीढ़ी के उपग्रह एनवीएस-02 को प्रक्षेपित करने का इसरो का नवीनतम प्रयास तब विफल हो गया जब मशीन गलत कक्षा में छोड़ दी गई आठ दूसरे सैटेलाइट या तो डीकमीशन हो गए हैं, ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाए हैं या उनकी क्लॉक खराब हैं। 2018 में, ISRO ने ISRO-स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा डेवलप की गई देसी रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करना शुरू किया। मई 2023 में लॉन्च किया गया NVS-01, इस डिवाइस को ले जाने वाला पहला सैटेलाइट था; सभी सेकंड-जेनरेशन NVS सीरीज़ सैटेलाइट भी ऐसा ही करेंगे।

NavIC की शुरुआत का एक हिस्सा 1999 की लड़ाई के दौरान कारगिल पर GPS डेटा शेयर करने से US का मना करना था, और यह अब भी ज़्यादातर ISRO द्वारा मैनेज किए जाने वाले एक डिफेंस प्रोग्राम के तौर पर काम कर रहा है। हालाँकि, 2020 में स्पेस सेक्टर में सुधारों ने R&D के लिए IS-RO और कमर्शियलाइज़ेशन के लिए NewSpace India को मौका दिया, लेकिन नेशनल स्पेस कानून न होने की वजह से ISRO को Nav-IC का डिज़ाइनर और ऑपरेटर दोनों के तौर पर काम करना पड़ रहा है, जिससे एजेंसी पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। इसी तरह, भारत के पास GPS डायरेक्टरेट या EUSPA जैसा कोई दूसरा ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है, जो एक के बाद एक GPS और गैलीलियो कॉन्स्टेलेशन को मैनेज करते हैं। रू-बिडियम घड़ियों की नई जेनरेशन को भी खरीदने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ISRO ने हर सैटेलाइट को पिछली तीन के बजाय पाँच एटॉमिक घड़ियों से लैस करने का प्रस्ताव दिया है। ISRO के खराब लॉन्च रेट की वजह से कॉन्स्टेलेशन जितनी तेज़ी से खराब हो रहा है, उसकी भरपाई उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रही है। यह समस्या कई वजहों से पैदा हुई है, जिसमें PSLV से जुड़ी दिक्कतें, PNT तारामंडल को बनाए रखने के लिए कम बजट, आने वाला ह्यूमन स्पेस मिशन प्रोग्राम, कई अर्थ-ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट और नए रॉकेट के लिए R&D शामिल हैं। ISRO उन स्टार्ट-अप्स की भी मदद कर रहा है जिन्हें अभी तक लो-अर्थ ऑर्बिट में रॉकेट लॉन्च करने का तरीका नहीं पता है। इस बीच, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वालों को GPS के साथ बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी के लिए NVS सीरीज़ के L1 बैंड को सपोर्ट करने के लिए बढ़ावा दिया है, जबकि सेना भी इसके इस्तेमाल की उम्मीद कर रही है। इन सभी वजहों से, 2026 में तीन और सेकंड-जेनरेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की ISRO की योजना पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता।

नई GDP सीरीज़, आगे का रास्ता दिखाती है

जीसी मन्ना

संस्थान में प्रोफेसर हैं

मानव विकास,
नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स में वरिष्ठ सलाहकार

रिसर्च (एनसीएईआर), और सलाहकार समिति के

सदस्य
राष्ट्रीय समिति

खाता सांख्यिकी

ए बहुप्रतीक्षित नई जीडीपी श्रृंखला के साथ बेस ईयर 2022-23 अब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। 27 फरवरी, 2026 को, मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए GDP अनुमानों और उनसे जुड़े एग्रीगेट्स की एक नई सीरीज़ पर एक प्रेस नोट जारी किया। यह बेस ईयर को अपडेट करके भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार की ज़्यादा सटीक और रियलिस्टिक तस्वीर की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। यह पहले के अनुमानों की कमियों को दूर करता है, जो पुराने 2011-12 बेस ईयर पर निर्भर थे।

नई सीरीज़ के अनुसार, GDP के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था का कुल आकार मौजूदा कीमतों पर (लाख करोड़ रुपये में) क्रमशः 261.18 (वित्त वर्ष 2022-23), 289.84 (वित्त वर्ष 2023-24) और 318.07 (2024-25) होने का अनुमान है (पहला संशोधित अनुमान)। ये कुल आंकड़े पिछली सीरीज़ के आधार पर पहले जारी किए गए आंकड़ों से थोड़े (3% और 4% के बीच) कम हैं। 2024-25 के दौरान मौजूदा कीमतों पर कुल ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का रिलेटिव हिस्सा क्रमशः 21.4%, 25.8% और 52.9% रहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दोनों सालों के लिए रियल GVA में हाई ग्रोथ रेट (9% से ज़्यादा) दिखाया है: 2023-24 में 12.7% और 2024-25 में 9.3%। खर्च के अनुमान के हिसाब से, GDP में प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्शन खर्च का हिस्सा, साल 2023-24 और 2024-25 के दौरान मौजूदा और स्थिर कीमतों पर, लगभग 56% है।

नई सीरीज़ में बड़े बदलाव

नई सीरीज़ में अपनाए गए मेथड में कुछ सबसे ज़रूरी बदलाव ये हैं: पहला, नॉन-फ़ैनेंशियल प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े मल्टी-एक्टिविटी एंटरप्राइज़ की एक्टिविटी को अलग करना, जिसमें एंटरप्राइज़ के कुल GVA को उसकी बिज़नेस एक्टिविटी में कंपनी की संबंधित रेवेन्यू शेयर जानकारी का इस्तेमाल करके बांटा जाता है, जो MGT 7/7A डेटा के रूप में उपलब्ध है (जबकि 2011-12 सीरीज़ में पूरा GVA एंटरप्राइज़ की मुख्य एक्टिविटी को दिया जाता था); दूसरा, पेड-अप कैपिटल के आधार पर इंडस्ट्री x साइज़ क्लास लेवल पर एक अलग ब्लोन अप फ़ैक्टर का इस्तेमाल, ताकि रिपोर्ट की गई एक्टिव कंपनियों के GVA को बढ़ाया जा सके, ताकि उन एक्टिव कंपनियों के योगदान को ध्यान में रखा जा सके जिन्होंने रिटर्न नहीं दिया; तीसरा, का पूरा कवरेज।

ASI सैंपलिंग फ्रेम को अपडेट करना और ASUSE को नया बनाना

सर्वेक्षण पद्धति को और बेहतर बनाया जा सकता है

जीडीपी की सटीकता और विश्वसनीयता और जीएसडीपी अनुमान

सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) का उपयोग करना मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट एयर्स (MCA) का डेटा; और चौथा, सालाना रिपोर्ट के अनुसार GVA प्रति वर्कर (GVAPW) पर हाई-फ्रीक्वेंसी (सालाना) डेटा का इस्तेमाल।

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का सर्वेक्षण (ASUSE) ने पीरियोडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे (PLFS) से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके वर्कर्स की संख्या के अनुमान के साथ मिलकर हाउसहोल्ड सेक्टर के GVA कंट्रीब्यूशन का अनुमान लगाया है। इस संदर्भ में, यह बताना ज़रूरी है कि 2011-12 सीरीज़ में, बेस ईयर (2011-12) के लिए हाउसहोल्ड सेक्टर के एक्टिविटी लेवल पर GVA अनुमानों को बाद के सालों के लिए GVA निकालने के लिए सही इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके निकाला गया था।

नई सीरीज़ 'डबल डिडक्शन' और 'वॉल्यूम एक्सट्रपलेशन' तरीकों के बड़े इस्तेमाल से असली GVA के अनुमान में भी काफ़ी सुधार लाती है, जिससे अनुमान इंटरनेशनल गाइडलाइंस के ज़्यादा करीब आ जाते हैं। इसके अलावा, 2022–23 के प्राइवेट कुल खपत खर्च (PFCE) के लिए बेंचमार्क अनुमान अब घरेलू खपत खर्च सर्वे (HCES 2022–23) के डेटा का इस्तेमाल करके ज़्यादा सीधे निकाले जाते हैं, खासकर उन चीज़ों के लिए जो सभी घरेलू ग्रुप में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं और जिनमें कम इनकम इलास्टिसिटी दिखती है।

आगे की चुनौतियाँ चार इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, यानी जनरल गवर्नमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन और हाउसहोल्ड, जिनके लिए GVA एस्टीमेट अलग-अलग कैलकुलेट किए जाते हैं और फिर उन्हें एग्रीगेट किया जाता है, उनमें से पहले दो सेक्टर का डेटाबेस काफी मजबूत है। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, खासकर प्राइवेट नॉन-फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सेगमेंट की बात करें, जिसके लिए GVA को MCA डेटाबेस का इस्तेमाल करके कम्पाइल किया जाता है — एक अहम मुद्दा राज्यों में कंपनियों के नेशनल लेवल के टोटल GVA को एलोकेट करने में है, ताकि उससे जुड़ा ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड (GSVA) निकाला जा सके, यह देखते हुए कि प्राइमरी डेटा सिर्फ एंटरप्राइज लेवल पर ही अवेलेबल है।

2011-12 सीरीज़ में, नेशनल लेवल पर टोटल मैन्युफैक्चरिंग GVA को एनुअल सर्वे ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ (ASI) के अनुसार GVA में राज्यों के हिस्से का इस्तेमाल करके अनुपात में बांटा गया था। नई सीरीज़ में, ASI डेटा (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए) के अलावा, इस मकसद के लिए GST डेटा भी उपलब्ध है। ASI डेटा की एक बड़ी कमी ASI फ्रेम का काफ़ी न होना है।

उदाहरण के लिए, 15 दिसंबर 2014 तक, 2011-12 में MCA डेटाबेस के अनुसार 'मैन्युफैक्चरिंग' के तहत क्लासिफाइड कंपनियों की संख्या 135,802 थी (सोर्स: नेशनल अकाउंट्स की नई सीरीज़ में मेथडोलॉजी और डेटा सोर्स में बदलाव, बेस ईयर 2011-12, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, 2015) जबकि ASI, 2011-12 में कॉर्पोरेट सेक्टर के तहत सिर्फ़ 67,649 फैक्ट्रियां कवर की गई थीं।

(तालिका 7, एएसआई 2011-2012 (संशोधित) में संगठन के प्रकार के अनुसार प्रमुख विशेषताएं)
इसलिए, ASI से मिले कुल GVA में अलग-अलग राज्यों का अनुपातिक हिस्सा, एक छोटे फ्रेम के आधार पर, असलियत को नहीं दिखा सकता है और इसलिए राज्य के GDP के आंकड़े पर असर डाल सकता है। MCA और GST डेटाबेस का इस्तेमाल करके ASI के सैंपलिंग फ्रेम को बेहतर बनाने के उपाय सही दिशा में एक कदम हो सकते हैं। इसके साथ ही, एक्टिव कंपनियों का एक ठीक से डिज़ाइन किया गया सैंपल सर्वे, कंपनियों द्वारा कुल GVA में अलग-अलग राज्यों के प्रतिशत हिस्से का पता लगाने के लिए काम आ सकता है।

उतार-चढ़ाव को दूर करना। जहां तक हाउसहोल्ड सेक्टर की बात है, नई सीरीज़ में एक्टिविटी, यानी 'कंपाइलेशन कैटेगरी' लेवल पर इसका GVA, ASUSE के अनुसार GVAPW और पीरियोडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे (PLFS) के आधार पर वर्कर्स की संख्या के प्रोडक्ट के तौर पर निकाला जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि सर्वे से मिले अनुमान काफी भरोसेमंद हों। हालांकि, ASUSE के उपलब्ध नतीजे कुछ इंडस्ट्रीज़ और राज्यों के लिए पिछले कुछ सालों में अनुमानों में कुछ उतार-चढ़ाव दिखाते हैं।

उदाहरण के लिए, अखिल भारतीय वार्षिक अनुमान ASUSE के अनुसार (जिसमें घरेलू सेक्टर और 'क्वासी-कॉर्पोरेट' यूनिट दोनों शामिल हैं) साल 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए GVAPW (ग्रामीण और शहरी मिलाकर) 'रबर और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर' के लिए क्रमशः ₹163,078; ₹255,447; और ₹201,930 पाया गया, जो GDP कैलकुलेशन में एक अलग कम्पाइलेशन कैटेगरी है।

इसी तरह, बिहार के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े GVAPW के सालाना अनुमान तीन सालों के लिए क्रमशः ₹89,638; ₹117,021; और ₹100,101 पाए गए। इस समस्या को हल करने के लिए, नई सीरीज़ में मेथडोलॉजी बेस ईयर को छोड़कर, जहाँ भी ज़रूरी हो, तीन साल के मूविंग एवरेज के इस्तेमाल की सलाह देती है। हालाँकि, GVAPW के सालाना अनुमानों में इस तरह के उतार-चढ़ाव की समस्या को हल करने के लिए, यह पता लगाना फायदेमंद हो सकता है कि क्या ASUSE में रोटेटिंग पैनल डिज़ाइन, जिसमें किन्हीं दो लगातार सालों के बीच सैंपल में काफी ओवरलैप हो — PLFS में अपनाए गए प्रोसेस की तरह — बेहतर अनुमान दे सकता है।

आखिर में, यह कहना है कि ASI फ्रेम को अपडेट करना और ASUSE के सर्वे के तरीके में बदलाव करना, GDP और GSDP के अनुमानों में और सुधार करने में असरदार हो सकता है।

व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं

भारत में AI-पावर्ड टैक्स गवर्नेंस और इसकी चुनौतियाँ

स्थानु आर. नायर

भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान में अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति पढ़ाते हैं

प्रबंधन (आईआईएम) कोझिकोड, केरल

रंजीत गुंडाबोइना

कृत्रिम पर काम करता है खुफिया अनुप्रयोगों

वित्तीय सेवाएँ और एक सहायक था

राज्य में प्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया,
क्रेडिट पोर्टफोलियो और रिस्क असेसमेंट मैनेज करता है

कृत्रिम भारत के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इंटेलिजेंस से नतीजे बेहतर हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा उपायों की ज़रूरत है

ए भारत के सामने मुख्य कर नीति चुनौती कम कर-सकल घरेलू उत्पाद रही है (GDP) रेश्यो और टैक्स चोरी का हाई लेवल। औसतन, 2001-22 के दौरान, भारत का टैक्स-GDP रेश्यो (16.36%) उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम था। टैक्स चोरी के कारण भारत को हर साल लगभग 4.3% टैक्स रेवेन्यू का नुकसान होता है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट (फरवरी 2026) में, दुनिया भर के नेताओं और टेक दिग्गजों ने असल दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ताकत का इस्तेमाल करने में भारत की तरक्की की तारीफ़ की।

एक समस्या क्षेत्र जहां AI का अनुप्रयोग टैक्स रेवेन्यू जुटाने और टैक्स गवर्नेंस की जांच करने लायक है। इस संदर्भ में, भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (ITD) की प्रोजेक्ट इनसाइट (PI) पहल — जिसका मकसद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू जुटाने को मजबूत करने के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का फायदा उठाना है — की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।

2017 में लॉन्च हुई और 2019 में पूरी तरह चालू हुई PI का मकसद अपनी मर्ज़ी से टैक्स कम्प्लायंस को बढ़ावा देना, संभावित टैक्स चोरी के ज़्यादा जोखिम वाले मामलों को कम करना, टैक्स लागू करने को ज़्यादा सही और बराबर बनाना, और टैक्स लागू करने में भेदभाव को कम करना है।

PI के तीन हिस्से हैं। इनकम टैक्स ट्रांज़ैक्शन एनालिसिस सेंटर (INTRAC) एक एनालिटिकल इंजन है जो AI और एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन, क्रेडिट कार्ड और GST पेमेंट, और हाई-वैल्यू खरीदारी सहित कई सोर्स से फाइनेंशियल डेटा को प्रोसेस करता है, ताकि 360-डिग्री टैक्सपेयर फाइनेंशियल प्रोफ़ाइल बनाई जा सके।

ऐसी जानकारी ITD को टैक्सपेयर्स की बताई गई इनकम और उनकी असल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बीच अंतर का पता लगाने में मदद करती है।

कंप्लायंस मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, INTRAC से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके बिहेवियरल कंप्लायंस पक्का करता है। यह उन टैक्सपेयर्स को, जिन्होंने गलत टैक्स रिटर्न भरा है, नॉन-इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल (NUDGE) स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके सही रिटर्न भरने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें उस व्यक्ति को SMS या ईमेल रिमाइंडर भेजना शामिल है जो उनकी असल आर्थिक गतिविधियों से मेल खाने वाले टैक्स का पेमेंट करता है। टैक्सपेयर्स या तो रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न जमा कर सकते हैं या शुरुआती रिटर्न पर ही टिके रह सकते हैं।

उन्होंने लीड किया। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में AI इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं। पहला, यह टैक्स एजेंसियों को टैक्सपेयर्स के रिस्क प्रोफाइल का सही अंदाज़ा लगाने और टैक्स चोरी की पहचान करने में मदद कर सकता है। दूसरा, यह टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को टैक्स चोरी के मामलों को, चोरी के साइज़ और सोफिस्टिकेशन के आधार पर प्रायोरिटी देने में मदद करता है।

तीसरा, AI रूटीन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के कामों को ऑटोमेट कर सकता है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर उन कामों पर फोकस कर सकते हैं जिनमें ज़्यादा इंसानी फैसले की ज़रूरत होती है। चौथा, AI टैक्सपेयर्स को सही टैक्स रिटर्न भरने, स्मार्ट चैटबॉट के ज़रिए सवालों के जवाब देने और टैक्स स्कैम को रोकने में मदद करके टैक्सपेयर की सर्विस को बेहतर बना सकता है।

PI पहल का नतीजा, चिंताएं और जोखिम PI के नतीजे दिखने लगे हैं। इशारा मिलने के बाद, कई टैक्सपेयर्स ने अपने ओरिजिनल टैक्स रिटर्न में अपनी मर्ज़ी से बदलाव करने के लिए ITD के अपडेटेड-रिटर्न फ़ीचर का इस्तेमाल किया। 2020-21 से, एक करोड़ से ज़्यादा रिवाइज़्ड रिटर्न किए गए हैं, जिससे टैक्स में ₹11,000 करोड़ और बढ़े हैं। टारगेटेड फॉरेन इनकम और एसेट्स NUDGE कैंपेन के तहत ITD ने जिन 19,501 टैक्सपेयर्स से संपर्क किया, उनमें से 62% ने अपने टैक्स रिटर्न में ओरिजिनली दी गई जानकारी को ठीक किया। साथ ही, 30,161 टैक्सपेयर्स ने कुल ₹29,208 करोड़ के ओवरसीज़ एसेट्स और क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से ₹1,089 करोड़ की फॉरेन इनकम बताई।

6.25 लाख टैक्सपेयर्स को कवर करने वाले NUDGE कैंपेन के नतीजे में पॉलिटिकल डोनेशन के लिए ₹963 करोड़ के इनकम-टैक्स डिडक्शन के झूठे क्लेम को ठीक किया गया, और ₹410 करोड़ के एडिशनल टैक्स का पेमेंट किया गया। टैक्स रिफंड प्रोसेस करने में लगने वाला एवरेज टाइम 93 से घटकर 17 दिन हो गया है। हाल ही में, बिग डेटा एनालिसिस और AI टूल्स का इस्तेमाल करके, ITD ने पाया कि पूरे भारत में रेस्टोरेंट्स ने 2019-20 से ₹70,000 करोड़ के सेल्स टर्नओवर को छिपाया था, इसके लिए कैश इनवॉइस को चुनिंदा तरीके से डिलीट करना, बिलिंग के बाद बदलाव करना, सेल्स डेटा को मिटाना और बिल वैल्यू में हेरफेर जैसे एडवांस्ड तरीके इस्तेमाल किए गए थे।

ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कई एडवांस्ड देशों ने PI पर आधारित AI-इनेबल्ड प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक लागू किया है और एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी कमाया है।

जैसे-जैसे भारत एल्गोरिद्मिक टैक्स की ओर बढ़ रहा है गवर्नेंस के लिए, कई ऑपरेशनल, नैतिक और कानूनी मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है।

पहला डेटा प्रोवेंस और क्वालिटी के बारे में है। PI जैसे AI सिस्टम उतने ही अच्छे होते हैं, जितना अच्छा डेटा उन्हें ट्रेन किया जाता है। वे आउटलायर्स की पहचान कर सकते हैं, लेकिन हमेशा चोरी और सही मुश्किल में फर्क नहीं कर सकते। पहले की बचत, क्लर्क की गलतियों, या जॉइंट फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने वाले वेरिएबल-इनकम प्रोफेशनल्स का डेटा गलत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। बिना किसी आसान इंसानी रिव्यू के, टैक्सपेयर्स को गलत पैटर्न की लेजिटिमेसी साबित करनी होगी।

दूसरा एल्गोरिदमिक बायस पर है। पुराने एनफोर्समेंट डेटा पर ट्रेन किए गए AI मॉडल अनजाने में मौजूदा सोशियो-इकोनॉमिक या ज्योग्राफिक बायस की नकल कर सकते हैं, जिससे कुछ टैक्सपेयर या ज्योग्राफिक एरिया में दूसरों की तुलना में टैक्स फ्रॉड की पहचान ज़्यादा होती है, जैसा कि डच चाइल्डकेयर बेनेट स्कैंडल से पता चला है।

तीसरा मुद्दा समझाने की क्षमता और सही प्रोसेस। AI-बेस्ड टैक्स कम्प्लायंस सिस्टम के सही होने के लिए, टैक्सपेयर्स को यह जानना ज़रूरी है कि उनकी पहचान क्यों की गई, उनकी जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सिस्टम अपने फैसले कैसे लेता है, और फैसलों को चैलेंज करने का एक साफ़ और आसान तरीका होना चाहिए।

टैक्सपेयर्स के लिए गंभीर नतीजों वाले किसी भी फैसले का ह्यूमन-इन-द-लूप इवैल्यूएशन होना चाहिए।

चौथा डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की चिंताओं के बारे में है। टैक्सपेयर्स की सेंसिटिव फाइनेंशियल और पर्सनल जानकारी तक पहुंचने से संभावित एक्सप्लॉइटेशन के लिए एक बड़ा अटैक सरफेस बन जाता है।

आखिर में, भारत में विवादित फैसलों को रिव्यू करने के लिए AI लोकपाल की कमी है , एल्गोरिदमिक असर के आकलन और गलत-पॉजिटिव और अपील-सक्सेस रेट की पब्लिक रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, और रिस्क-स्कोरिंग मॉडल के बाहरी ऑडिट की ज़रूरत है।

ऊपर बताए गए ऐसे मज़बूत AI गवर्नेंस गार्डरेल के बिना, PI एक छिपे हुए सर्विलांस सिस्टम में बदल सकता है जो अकाउंटेबिलिटी और टैक्स सिस्टम की फेयरनेस से कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जिससे टैक्सपेयर्स कम भरोसेमंद और ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं। भारत को एक साफ़ चॉइस चुननी होगी: एक मॉडर्न टैक्स इंटेलिजेंस सिस्टम को अपनाना जो एथिकल और इफेक्टिव दोनों हो।

व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं

सेमी वाईके

Machine Translated by Google

सरकारों को AI का इस्तेमाल किस हद तक करना चाहिए?

ईशा सूरी

इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र में अनुसंधान प्रमुख

समाज

रमन जीत सिंह चीमा

एशिया प्रशांत

नीति निदेशक और वरिष्ठ

अंतरराष्ट्रीय पर परामर्श

एक्सेस नाउ, डिजिटल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध

एक नॉन-प्रॉफिट संस्था

बातचीत

लोक प्रशासन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उपकरण

जैसे ही सरकारें तैनाती शुरू करती हैं सिक्योरिटी और पॉलिसी बनाने के मामले में, इसके सुरक्षित इस्तेमाल और जवाबदेही को लेकर सवाल सेंटर-स्टेज पर आ गए हैं। यह मुद्दा US में तब फोकस में आया जब रिपोर्ट्स में पेंटागन और AI कंपनी एंथ्रोपिक के बीच विवाद का पता चला, जिसने बड़े पैमाने पर निगरानी और ऑटोनॉमस हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए मौजूद सेफगार्ड्स को हटाने से मना कर दिया था। इस घटना ने AI सिस्टम्स को डिप्लॉय करने की कोशिश कर रही सरकारों और उन्हें कंट्रोल करने वाली कंपनियों के बीच गहरे तनाव को दिखाया। जैसे-जैसे देश AI कंपनियों के साथ और करीब से कोलेबोरेट कर रहे हैं, आखिर उन सिस्टम्स को कौन कंट्रोल करता है जो हमें कंट्रोल करते हैं? ईशा सूरी और रमन जीत सिंह चीमा ने अरीना अरोड़ा द्वारा मॉडरेट की गई बातचीत में इस सवाल पर चर्चा की। एडिटेड अंश:

AI असल में किस तरह की सरकारी क्षमता को मज़बूत कर सकता है? और सरकारों को इस पर भरोसा करने में कहाँ सावधानी बरतनी चाहिए?

रमन जीत सिंह चीमा: यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है और वह किसके साथ डील कर रही है। AI के कभी-कभी ट्रांसफॉर्मेटिव असर हो सकते हैं, जैसे डेटा तक एक्सेस को बेहतर बनाना या बेहतर एनालिसिस को इनेबल करना, लेकिन इसे अक्सर प्रॉब्लम, अवेलेबल डेटा या इसमें शामिल कॉस्ट के बारे में क्लैरिटी के बिना डिप्लॉय किया जाता है। फेशियल रिकग्निशन, सर्विलांस और कुछ हेल्थ एप्लिकेशन जैसे हाई-रिस्क एरिया भी हैं, जहां गलत इस्तेमाल से काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे मामलों में, 'कोई नुकसान न पहुंचाएं' का प्रिंसिपल लागू होना चाहिए, और कुछ मामलों में, पूरी तरह से रोक लगाना सही हो सकता है।

ईशा सूरी: AI सिस्टम आमतौर पर सही इस्तेमाल वाले मामलों में सबसे अच्छा काम करते हैं। उदाहरण के लिए, COVID-19 महामारी के दौरान, इमेज-प्रोसेसिंग टूल अलग-अलग तरह के फेफड़ों के इन्फेक्शन में फर्क कर सकते थे क्योंकि समस्या साफ तौर पर बताई गई थी और पैरामीटर पता थे।

सरकारों को AI इस्तेमाल करने का मकसद तय करके शुरुआत करनी चाहिए। यह साफ़ जानकारी अक्सर नहीं होती। कोई भी सिस्टम अपनाने से पहले, उन्हें पूछना चाहिए कि क्या AI ज़रूरी है, क्या कम दखल देने वाले विकल्प मौजूद हैं, और इसके क्या रिस्क हैं। ज़रूरत और प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। AI को सिर्फ़ इसलिए नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि वह मौजूद है।

अगर AI सिस्टम के साथ ज़्यादा डेटा शेयर करने से सरकारी सर्विस ज़्यादा तेज़ और बेहतर हो जाती हैं, तो लोगों को प्राइवेसी की चिंता क्यों करनी चाहिए? इसमें क्या नुकसान हैं?

IS: हमें यह सवाल करने की ज़रूरत है कि 'eciency' का क्या मतलब है

खतरनाक मिक्स: US डिपार्टमेंट ऑफ़ वॉर और एंथ्रोपिक के लोगो। रॉयटर्स

और किसके लिए। प्रोडक्टिविटी में फ़ायदे के सबूत अभी भी कमज़ोर हैं। कई मामलों में, एफिशिएंसी के दावे लेबर सब्स्टीट्यूशन में बदल जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है। एक मकसद के लिए इकट्ठा किया गया डेटा कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है। वेलफेयर डेटा का इस्तेमाल पुलिसिंग या फ़ायदों को मना करने के लिए किया जा सकता है।

यह सोच कि नागरिक डेटा शेयर करने से ठीक हैं, यह मान लेता है कि उन्होंने जानकारी देकर सहमति दे दी है, जो अक्सर सच नहीं होता। बहुत से लोग पूरी तरह से नहीं समझते कि उनके डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। भारत जैसे देशों में, जिसे अक्सर कम प्राइवेसी के साथ कल्चरल कम्फर्ट माना जाता है, वह असल में कम डिजिटल लिटरेसी का नतीजा है।

इसलिए, लोग पूरी जानकारी के बिना फ़ैसले ले सकते हैं, जबकि लंबे समय के नतीजे सामने आ रहे होते हैं। इसीलिए सरकार को नुकसान का अंदाज़ा लगाना चाहिए और डिज़ाइन स्टेज पर ही सुरक्षा के उपाय बनाने चाहिए, न कि डिप्लॉयमेंट के बाद।

RC: यह आइडिया कि बेहतर AI के लिए ज़्यादा पर्सनल डेटा की ज़रूरत होती है, हैरान करने वाला है। इससे कुछ कमर्शियल लोगों को फ़ायदा होता है लेकिन यह टेक्निकली ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा डेटा हमेशा बेहतर नहीं होता। यह बेकार, रिस्की और खासकर उन कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो बड़े पैमाने पर डेटा निकालने और कंप्यूट-हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं।

इसके विकल्प भी हैं। उदाहरण के लिए, छोटे मॉडल कम डेटा का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा साफ़ आउटपुट दे सकते हैं। ऐसे ऑन-डिवाइस AI सिस्टम भी हैं जिन्हें बड़े डेटा सेंटर में लगातार डेटा ट्रांसफर की ज़रूरत नहीं होती। हमें इस सोच को चुनौती देनी चाहिए कि डेटा देना बेहतर सर्विस की कीमत है।

AI कंपनियों का कहना है कि बेहतर सिस्टम बनाने के लिए उन्हें बड़े पब्लिक डेटासेट तक पहुंच की ज़रूरत है।
क्या सरकारों को इन डेटासेट को स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट मानना चाहिए, या डेवलपमेंट में तेज़ी लाने के लिए इन्हें प्राइवेट कंपनियों के साथ शेयर किया जा सकता है?

आर.सी.: हमें इस बात से बहुत सावधान रहना चाहिए कि डेटा

> अगर घरेलू सिस्टम बड़ी ग्लोबल कंपनियों के कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर या पार्टनरशिप पर बने हैं, तो हम असल में स्वदेशी क्षमता नहीं बना रहे हैं। हम बस मौजूदा निर्भरता के ऊपर लेयरिंग कर रहे हैं।
>
> ईशा सूरी

यह ऐसी चीज़ है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। प्राइवेट लोगों के लिए डेटा खोलना प्राइवेसी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए रिस्क पैदा करता है। यह पिछली गलतियों को भी दोहराता है जब पब्लिक सिस्टम को बिना सही सेफ़्टी के सौंप दिया गया था।

IS: डेटा को एक नेशनल या इकोनॉमिक एसेट के तौर पर देखना प्रॉब्लम वाला है, क्योंकि इससे प्राइवेसी से जुड़े फंडामेंटल राइट के नेचर से ध्यान हट जाता है। कंसेंट के भी इश्यू हैं।

नागरिक एक मकसद के लिए डेटा दे सकते हैं, लेकिन कमर्शियल पार्टनरशिप में इसके इस्तेमाल के लिए नहीं। हमें यह भी पूछना होगा कि बड़े डेटासेट तक एक्सेस की मांग कौन बढ़ा रहा है। अक्सर, यह प्राइवेट कंपनियां होती हैं जिनके पास साफ आर्थिक फायदे होते हैं।

आखिरकार, हम जिस स्थिति का जोखिम उठाते हैं, वह ऐसी स्थिति है
पब्लिक डेटा और पब्लिक पैसा, लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी के साथ प्राइवेट वैल्यू निकालने में मदद करते हैं।
इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि सरकारें पीछे हटें और देखें कि ऐसे इंतज़ामों से किसे फ़ायदा होता है और क्या वे लोगों के फ़ायदे के हिसाब से हैं।

सरकारें हमेशा प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करती रही हैं। क्या हमें उस पार्टनरशिप में AI को अलग तरह से देखना चाहिए या उससे डरना चाहिए?

आर.सी.: हमें पिछले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से सीखना चाहिए। सिस्टम को पहले डिप्लॉय करके बाद में रेगुलेट नहीं करना चाहिए। इसमें यह भी रिस्क है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में एक मकसद बन जाए।

सरकारें सिस्टम को इसलिए नहीं बढ़ा सकतीं कि इससे नतीजे बेहतर होंगे, बल्कि इसलिए बढ़ा सकती हैं ताकि पहले किए गए इन्वेस्टमेंट को सही ठहराया जा सके। बड़ी पार्टनरशिप सरकारों को महंगे और कभी न टूटने वाले इंतज़ामों में भी फंसा सकती हैं।

IS: आधार और डिजीयात्रा जैसे प्रोजेक्ट्स को चेतावनी देने वाले उदाहरण के तौर पर देखा जाना चाहिए। वेलफेयर डिलीवरी में ट्रेड-ओस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। छोटी एक्सक्लूजन रेट के भी गंभीर नतीजे हो सकते हैं। जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हाइब्रिड या प्राइवेट एंटिटीज़ के ज़रिए चलाया जाता है, तो अकाउंटेबिलिटी में भी गैप होते हैं।

अगर दूसरी सरकारें AI को अपनाना शुरू कर दें और यह दुनिया भर में ज़रूरी हो जाए, तो क्या भारत को भी इसे अपनाना चाहिए?

आर.सी.: सरकारों को आँख बंद करके ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। AI का इस्तेमाल सिर्फ़ वहीं होना चाहिए जहाँ यह जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाता है।
पॉलिसी बनाने वालों को डेटा प्रोटेक्शन, प्रोक्योरमेंट और मार्केट कंसंट्रेशन जैसी प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान देना चाहिए।

IS: यह ज़रूरी है, इस विचार को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है और अक्सर यह इंडस्ट्री की कहानियों से चलता है।
सरकारों को कुछ छूट जाने के डर से रिएक्ट करने के बजाय अपने लक्ष्य खुद तय करने चाहिए।

अगर दूसरी सरकारें AI को ज़्यादा तेज़ी से अपनाती हैं, तो क्या भारत के पीछे रहने का खतरा है?

RC: अगर हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में चिंतित हैं, तो फोकस बेसिक साइंटिफिक कैपेसिटी बनाने पर होना चाहिए।

मौजूदा इंडस्ट्री की कहानी बताती है कि बड़ी AI कंपनियों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना ही वहां तक पहुंचने का तरीका है। असल में यह असली काबिलियत बनाने से ध्यान भटकाने वाला हो सकता है। अगर आप भारत का अतीत देखें, तो कोर साइंस में निवेश से स्पेस और न्यूक्लियर डेवलपमेंट में बड़े प्रोग्राम शुरू हुए।

अगर हमें सॉवरेन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी चाहिए, तो यहां भी ऐसा ही अप्रोच ज़रूरी है।

IS: हमें यह भी सवाल करना होगा कि “पीछे रह जाने” का क्या मतलब है।
AI सिर्फ़ एक एप्लीकेशन नहीं है, यह एक फुल स्टैक है, जिसमें कंप्यूट, डेटा और मॉडल शामिल हैं।
अगर घरेलू सिस्टम बड़ी ग्लोबल कंपनियों के कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर या पार्टनरशिप पर बने हैं, तो हम असल में स्वदेशी क्षमता नहीं बना रहे हैं। हम बस मौजूदा निर्भरता के ऊपर लेयर बना रहे हैं। इससे विदेशी टेक्नोलॉजी मोनोपॉली पर लॉक-इन और लंबे समय तक निर्भरता का खतरा पैदा होता है। यह सॉवरेनिटी और कंट्रोल को लेकर भी चिंताएं पैदा करता है। साथ ही, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और सुपरइंटेलिजेंस को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप आज के नुकसानों से ध्यान भटका सकती है, जिसमें लेबर पर असर, एनवायरनमेंटल कॉस्ट और पावर का कंसंट्रेशन शामिल है।

तो वह हमें कहां छोड़ता है?

RC: सरकार में AI का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया जाता है, इस बारे में सावधान रहें। साफ़ इस्तेमाल के मामलों पर ध्यान दें, बड़े प्राइवेट प्लेयर्स पर बेवजह निर्भरता से बचें, और पब्लिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दें।

IS: सरकारों को कोई भी टेक्नोलॉजी अपनाने से पहले अपने मकसद साफ़-साफ़ बताने चाहिए। पूछें कि क्या AI ज़रूरी है, और क्या इसके रिस्क, फायदे के हिसाब से हैं।

नोटबुक

इंटरव्यू को न्यूज़ लायक बनाने के लिए टकराव वाला होना ज़रूरी नहीं है

समय पर इंटरव्यू क्यों ज़रूरी हैं और यह पढ़ने वालों को राजनीतिक घटनाक्रम से आगे रहने में कैसे मदद कर सकता है

विजेता सिंह

सी 170 दिनों तक राजस्थान के जोधपुर में कैद रहने के बाद, 14 मार्च को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया। गृह मंत्रालय (MHA) की प्रेस रिलीज़ के ज़रिए दी गई इस खबर ने कई लोगों को हैरान कर दिया। हालाँकि, द हिंदू के पाठकों को इसका अंदाज़ा हो गया होगा।

रिलीज़ से एक हफ़्ते पहले, मिस्टर वांग-चुक की पत्नी और हिमा-लायन इंस्टीट्यूट ऑफ़ अल्टरनेटिव लर्निंग की को-फ़ाउंडर, गी-तंजलि जे. अंगमो से इस अख़बार ने इंटरव्यू के लिए संपर्क किया था।

मैं 2020 से लद्दाख मुद्दे को कवर कर रहा हूँ, जब नए बने केंद्र शासित प्रदेश (UT) में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए कैंपेन शुरू किया था। 24 सितंबर, 2025 को लेह शहर में जो हुआ, उसे लेकर हमेशा से गहरी जिज्ञासा और हैरानी रही है। राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन – जिससे इस क्षेत्र को आदिवासी का दर्जा मिलेगा, और स्थानीय लोगों को यह तय करने में ज़्यादा आज़ादी मिलेगी कि वे अपनी ज़मीन किसे बेच सकते हैं – हिंसक हो गया, जिसमें चार लोग मारे गए।

शांतिपूर्ण आंदोलन और साइलेंट मार्च के लिए जानी जाने वाली जगह से ऐसी हिंसा परेशान करने वाली थी। इसलिए, ऐसी घटनाओं पर रेगुलर नज़र रखकर पढ़ने वालों को जानकारी देना ज़रूरी था। घटना के दो दिन बाद, 26 सितंबर को, पुलिस की एक टीम ने मिस्टर के घर जाने वाली सड़कें ब्लॉक कर दीं।

वांगचुक को लेह से 70 किलोमीटर दूर उलेतोक-पो गांव में उनके घर ले जाया गया और बाद में, उनके ही शब्दों में, उन्हें “बांधकर” लगभग 1,400 किलोमीटर दूर जोधपुर जेल ले जाया गया।

सुश्री अंगमो, जो काम पर थीं, को एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उन्हें राजस्थान ले जाया जा रहा है। एक हफ़्ते तक पुलिस की तरफ़ से कोई और जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद सुश्री अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हेराफेरी पिटीशन दायर की।

इस बीच, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि मिस्टर वांगचुक पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत केस दर्ज किया गया है, यह एक ऐसा नियम है जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के एक साल के लिए जेल में रखा जा सकता है।

एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर।

पिछले पाँच महीनों से, मिस एंग्मो एक सूटकेस में रह रही हैं, दिल्ली और जोधपुर के बीच समय बांट रही हैं, कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो रही हैं और मिस्टर को जानकारी दे रही हैं।

वांगचुक ने ज्यूडिशियल प्रोग्रेस के बारे में बताया। जब वह इंटरव्यू के लिए राज़ी हुईं, तो आइडिया यह था कि उनके संघर्ष को सामने लाया जाए और पढ़ने वालों को दिल्ली में कानूनी उलझनों से गुज़रने के उनके सफ़र और सिस्टम का सामना करने में लगने वाले इमोशनल असर के बारे में बताया जाए।

जब उनसे एक खास सवाल पूछा गया कि अगर टॉप कोर्ट ने मिस्टर वांगचुक को रिहा करने का ऑर्डर दिया तो क्या वे प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, तो मिस एंगमो ने कहा कि वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के बजाय बातचीत के ज़रिए अपनी मांगों का फिर से हल निकालना चाहेंगे। स्टोरी पब्लिश होने के बाद, सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स में यह डर फैल गया कि वे आंदोलन छोड़ रहे हैं। 12 मार्च को, उनके X अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा गया कि वे एक्टिविज़्म से दूर नहीं हुए हैं, लेकिन इसके लिए “क्लैरिटी, यूनिटी और सच्ची बातचीत” की ज़रूरत होगी। 17 मार्च को, रिहाई के बाद अपनी पहली बात में, उन्होंने दोहराया कि वे प्रोटेस्ट को आगे का रास्ता नहीं मानते और इसके बजाय बातचीत को प्रायोरिटी देंगे। उन्होंने कहा, “बातचीत एक लेन-देन का प्रोसेस है, दोनों पक्षों को लचीला और विचारशील होना चाहिए,” और कहा कि बातचीत को बेवजह लंबा खींचने से मतलब वाली बातचीत में रुकावट आएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी और उम्मीद थी कि जल्द ही फैसला सुनाएगा। हालांकि उन्हें NSA ऑर्डर को चुनौती देने वाली पिटीशन पर सुनवाई से पहले और लेह और कारगिल में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के बुलाए गए प्रोटेस्ट से दो दिन पहले रिहा कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी रिहाई पर सेंटर ने कोई शर्त नहीं लगाई है। दूसरी ओर, लद्दाखियों ने अपनी मांगों पर ज़ोर देने के लिए 16 मार्च को प्रोटेस्ट किया।

पाठक और उनके फ़ॉलोअर मिस्टर के बारे में अपने नतीजे निकाल सकते हैं।
वांगचुक की पॉलिटिक्स और उनके आगे के प्लान के बारे में तो पता चला, लेकिन इस एपिसोड ने समय पर इंटरव्यू की अहमियत को दिखाया। इंटरव्यू को न्यूज़ लायक बनाने के लिए टकराव वाला होना ज़रूरी नहीं है।

vijaita.singh@thehindu.co.in

सप्ताह की तस्वीर

नीचे लंबा रास्ता

X

लगातार सैर: एक बड़ा नर नीलगिरी ताहर 14 मार्च को तमिलनाडु के कोयंबटूर में पोलाची-वलपराई रोड के घाट सेक्शन के पास अनामलाई टाइगर रिज़र्व में एक खड़ी चट्टानी ज़मीन से नीचे उतर रहा है। गर्मी शुरू होते ही घास और झाड़ियाँ मुरझा जाती हैं, ऐसे में नीलगिरी ताहर हरे चारे की तलाश में इन बड़े इलाकों में घूमते हैं। पेरियासामी एम.

मूलपाठ& प्रसंग

0

संख्याओं में समाचार

ईरान के बाद अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज़ युद्ध

39 इंच $ ट्रिलियन. देश का कर्ज़ रिकॉर्ड $39 ट्रिलियन को पार कर गया, यह एक ऐसा माइलस्टोन है जो ईरान में US-इज़राइल युद्ध के कुछ ही हफ़्तों बाद आया है। यह अभूतपूर्व आंकड़ा प्रशासन की प्राथमिकताओं को दिखाता है, जिसमें टैक्स कानून पास करना और रक्षा खर्च और इमिग्रेशन लागू करना बढ़ाना और कर्ज़ को कम करना शामिल है। AP

मौजूदा RS का हिस्सा जिन सांसदों ने आपराधिक मामले घोषित किए

32 प्रतिशत। लगभग 32% मौजूदा राज्यसभा सांसदों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 14% लोग खुद के खिलाफ हैं, जबकि 14% अरबपति हैं।

यह रिपोर्ट 233 राज्यसभा सदस्यों में से 229 के हलफनामों के विश्लेषण पर आधारित है।

सांसद. पीटीआई

री-रिलेटेड कॉल्स में प्रतिशत में गिरावट इस साल दिल्ली

19 प्रतिशत। दिल्ली के अनुसार फायर सर्विसेज (DFS) के डेटा के मुताबिक, 2,716 फायर कॉल मिलीं।

1 जनवरी और 15 मार्च को यह संख्या 2025 की इसी अवधि के 3,352 से कम है।

इसके बावजूद, मौतों की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है, पिछले साल इसी समय के दौरान 13 मौतें और 111 घायलों की रिपोर्ट है, जबकि पिछले साल इसी समय के दौरान 18 मौतें और 109 घायल हुए थे। PTI

कोमोरोस में डूबने वाले अफ़्रीकी प्रवासियों की संख्या

17कम से कम 17 अफ़्रीकी प्रवासी जो फ्रांसीसी लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे हिंद महासागर का मायोट द्वीप

सरकार ने कहा कि कोमोरोस के पास 100 से ज़्यादा लोग डूब गए हैं। एक सरकारी मंत्री ने कहा कि जब ग्रुप राजधानी मोरोनी से करीब 40 किलोमीटर दूर तटीय शहर मित्सामियोली के पास पहुंचा, तो करीब 30 लोग ज़िंदा पाए गए। AFP

कोलंबिया में 2016-25 के बीच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या

2016 और 2019 के बीच 1,000" 2025,

UNHCR ने एक बयान में कहा, "यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की 972 हत्याएं दर्ज कीं," यानी हर साल औसतन लगभग 100 मौतें। AFP

द हिंदू डेटा टीम द्वारा संकलित

हमारे पर का पालन करें facebook.com/thehindu X.com/the_hindu instagram.com/the_hindu

तेल, बिजली और व्यवधान की राजनीति

होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से ग्लोबल इकॉनमी का एक ज़रूरी हिस्सा रुक जाता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं और एनर्जी मार्केट में उथल-पुथल मच जाती है; जैसे-जैसे सप्लाई में झटके एनर्जी की जियोपॉलिटिक्स को बदल रहे हैं, भारत, US और रूस जैसे देश बदलते तेल के फ्लो और बढ़ती निर्भरता के बीच अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं।

आर्थिक नोट्स

जयन जोस थॉमस

टी जलडमरूमध्य का नीला पानी होर्मुज, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, ग्लोबल इकॉनमी का एक ज़रूरी हिस्सा है। इस पतले गेटवे से – जो कुछ जगहों पर सिर्फ़ 33 km तक फैला है – दुनिया भर में होने वाले तेल का लगभग पांचवां हिस्सा ले जाने वाले जहाज़ गुज़रते हैं। 28 फरवरी को जब US और इज़राइल ने ईरान के खिलाफ़ मिलिट्री कैंपेन शुरू किया, तो ईरान ने स्ट्रेट से गुज़रने वाले जहाज़ों को रोक दिया, जिससे कीमतें बढ़ गईं और एनर्जी मार्केट में उथल-पुथल मच गई।

ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में तेल और नैचुरल गैस का हिस्सा आधे से थोड़ा ज़्यादा है (IEA के 2024 के डेटा के मुताबिक, बाकी कोयला, रिन्यूएबल और दूसरे सोर्स से आता है)। ये ट्रकों से लेकर हवाई जहाज़ों तक को फ्यूल देते हैं, बिजली और कुकिंग गैस बनाते हैं, और इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी कच्चा माल देते हैं।

फारस की खाड़ी के आस-पास के पश्चिम एशियाई देश, खासकर सऊदी अरब, UAE और ईरान, कच्चे तेल और नैचुरल गैस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से हैं। वहीं, कुछ सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर ईस्ट और साउथ एशिया में हैं, खासकर चीन, इंडिया और जापान। फिर भी, इन देशों के पास अपनी बढ़ती इकॉनमी को पावर देने के लिए लिमिटेड डोमेस्टिक ऑयल रिज़र्व हैं (हालांकि चीन एक बड़ा नैचुरल गैस प्रोड्यूसर है) (चार्ट 1)। वे पश्चिम एशिया से कच्चे तेल और नैचुरल गैस के इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, जिसका ज़्यादातर हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुज़रता है।

अमेरिका और पश्चिम एशिया

कुछ इलाकों में एनर्जी रिज़र्व, खासकर तेल, का जमा होना, दुनिया की ताकतों के बीच लंबे समय से चले आ रहे और कड़े मुकाबलों की मुख्य वजह रहा है। फारस की खाड़ी के देशों के अलावा, सिर्फ़ कुछ ही देशों – US, रूस, वेनेज़ुएला और कनाडा – के पास बड़े तेल और नैचुरल गैस रिज़र्व हैं।

अमेरिका इसमें एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है एनर्जी की जियोपॉलिटिक्स, एक बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों। गैस की ज़्यादा खपत करने वाले सेक्टर्स को देखते हुए, जो इसकी इकॉनमी को चला रहे हैं, US में हर व्यक्ति के लिए एवरेज एनर्जी सप्लाई भारत से 10 गुना और चीन से 2.4 गुना ज़्यादा है। ज़्यादा एनर्जी की तलाश US की इंटरनेशनल पॉलिसीज़ का एक मुख्य मकसद रहा है।

1950 के दशक से वेस्ट एशिया में तेल पर कंट्रोल बड़ी अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों से हटकर सरकारी नेशनल तेल कंपनियों के पास चला गया। 1970 के दशक में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं, जिसमें अरब सदस्यों ने ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा असर डाला। US का जवाब दोहरा रहा: उसने ज़्यादा शेल ऑयल की ड्रिलिंग करके घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाया, खासकर 2000 के दशक के बीच से, जिससे वह दुनिया का सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर बन गया, और उसने गल्फ़ वॉर (1990-91), इराक वॉर (2003-11), वेनेज़ुएला में हालिया कार्रवाई (2026), और ईरान के साथ चल रहे US-इज़राइल युद्ध सहित स्ट्रेटेजिक दखल के ज़रिए तेल की जियोपॉलिटिक्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश की।

हालांकि मौजूदा प्रोडक्शन लेवल मामूली, वेनेज़ुएला और ईरान मिलकर दुनिया के साबित तेल भंडार का 39% हिस्सा हैं। भविष्य में तेल मिलने का वादा ही इन देशों को स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है, खासकर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रोट प्रोजेक्शन में। हालांकि, होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से, कम से कम शॉर्ट टर्म में, मिस्टर ट्रंप के कैलकुलेशन गड़बड़ा गए हैं और रूस एनर्जी की उथल-पुथल का अनचाहा फायदा उठाने वाला बन गया है।

When routes run tight

The closure of the Strait of Hormuz has disrupted a vital artery of the global economy, pushing up oil prices and unsettling energy markets

Source: Statistical Review of World Energy 2025, The Energy Institute

Table 1: Oil trade in 2024, in million barrels per day

	Crude & product imports	Crude exports	Product exports	Net Exports
Saudi Arabia	0.4	6.4	1.2	7.2
Russia	0.0	4.9	2.2	7.0
UAE	0.8	3.7	2.0	4.9
Canada	1.0	4.4	0.7	4.2
Iraq	0.1	3.6	0.5	4.0
U.S.	8.4	4.0	5.9	1.4
India	**6.0**	**0.0**	**1.9**	**-4.1**
China	13.4	0.0	1.2	-12.2
World	**69.4**	**43.2**	**26.2**	**0.0**

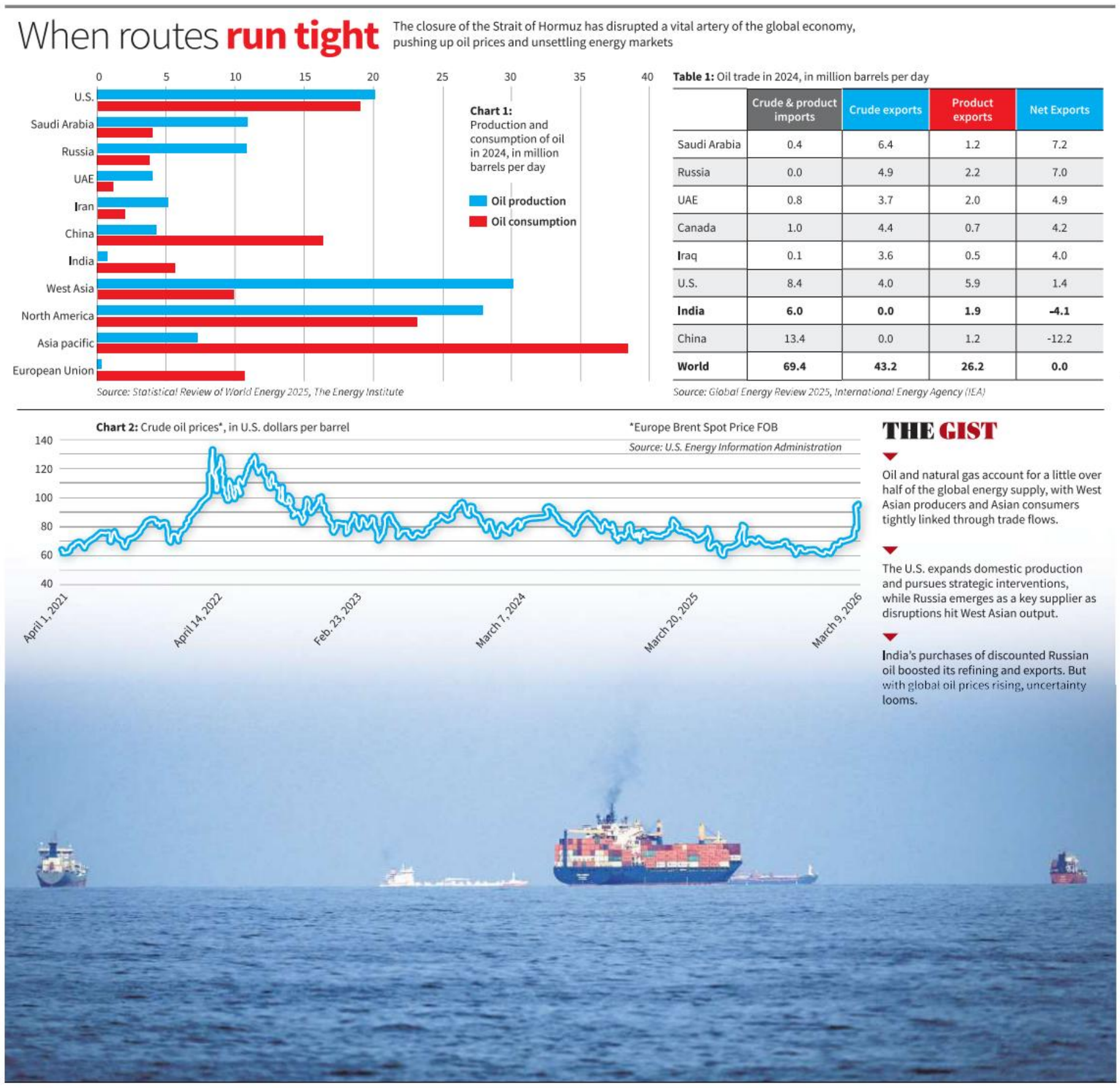

Source: Global Energy Review 2025, International Energy Agency (IEA)

*Europe Brent Spot Price FOB

Source: U.S. Energy Information Administration

THE GIST

- Oil and natural gas account for a little over half of the global energy supply, with West Asian producers and Asian consumers tightly linked through trade flows.
- The U.S. expands domestic production and pursues strategic interventions, while Russia emerges as a key supplier as disruptions hit West Asian output.
- India's purchases of discounted Russian oil boosted its refining and exports. But with global oil prices rising, uncertainty looms.

2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद, रूस पश्चिम, खासकर यूरोप में एक अलग-थलग देश बन गया, और ट्रेड सेंक्शन ने लंबे समय तक उसके तेल के व्यापार को रोक दिया था। लेकिन अचानक, जैसे ही पश्चिम एशिया में तेल उत्पादन की क्षमता पर असर पड़ा, रूस का तेल एनर्जी की कीमतों को स्थिर करने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। पश्चिम एशिया के बाहर, रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास बड़ा ट्रेडेबल तेल सरप्लस है (टेबल 1)।

रूसी तेल और भारत तेल बाज़ार आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। बाज़ार के किसी कोने में उठी एक लहर भी एक बड़ी लहर बन सकती है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर और तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। सप्लाई में रुकावट की वजह से भारत में ज़रूरी सामान और सर्विस की कीमतें बढ़ जाती हैं। साथ ही, ऑयल मार्केट में भारत के कामों का ग्लोबल ऑयल की कीमतों पर काफी असर पड़ता है।

यूरोपियन देश, जिनके पास घरेलू तेल और नैचुरल गैस का सीमित भंडार है, पारंपरिक रूप से एनर्जी पर निर्भर रहे हैं।

आज, होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने और तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल को पार करने के साथ, US प्रतिबंधित रूसी तेल की ज़्यादा खरीद देखने के लिए बेताब है।

कड़ाके की ठंड झेलने के लिए यूरोप को ज़्यादातर रूस से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन 2022 से रूसी प्रोडक्ट्स पर बैन लगने के बाद, यूरोप को एनर्जी के नए सोर्स ढूंढने पड़े हैं, खासकर वेस्ट एशिया में।

इस संदर्भ में, भारत ने डिस्काउंटेड कीमतों पर रूसी तेल। भारत की तेल खरीद में रूसी इंपोर्ट का हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है — 2021 में 2.5% से बढ़कर 2023 में 39.0% हो गया। ध्यान दें कि कच्चे तेल को रीनेरीज़ में प्रोसेस करके पेट्रोल, डीज़ल, LPG और पेट्रोकेमिकल्स जैसे कई प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। इंपोर्टेड कच्चे तेल पर निर्भर रहते हुए, चीन और भारत ने बड़ी रीनेमिंग कैपेसिटी बनाई है और अपने रीनेम्ड तेल प्रोडक्ट्स का एक हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं।

कुछ भारतीय व्यापारियों ने डिस्काउंटेड क्रूड से प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके बड़ा प्रॉफिट कमाया है।

उनके विरोध के बावजूद, पश्चिमी नेताओं ने चुपचाप तेल की कीमतों में स्थिरता का स्वागत किया, जो तब हुई जब 2022 से भारत की मांग कुछ हद तक प्रतिबंधित रूसी तेल की ओर मोड़ दी गई (चार्ट 2)।

आज, जब होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है और तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल को पार कर गई हैं, तो US बाज़ारों को शांत करने के लिए रूस से बैन किए गए तेल की ज़्यादा खरीद चाहता है, जो लंबे समय से समुद्र में फंसा हुआ है ।

सच में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक हफ़्ता बहुत लंबा समय हो सकता है। जैसे-जैसे वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ता है, ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर बदल सकता है।

(जयान जोस थॉमस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं)

Machine Translated by Google

पूरा संदर्भ

नमक से पहले पानी था: महाड क्यों? सत्याग्रह अपनी शताब्दी का हकदार है

गणतंत्र को महाड सत्याग्रह की सौवीं सालगिरह को उतनी ही गंभीरता से मनाना चाहिए जितनी वह हकदार है; इसके लिए ईमानदारी से एक साल का हिसाब-किताब करने की ज़रूरत है ताकि यह पूछा जा सके कि क्या सम्मान और छुआछूत से आज़ादी का संवैधानिक वादा सभी के लिए एक जीती-जागती सच्चाई बन गया है।

संजय हेगड़े

टी स्कूल में एक बच्चे के बारे में सोचिए। उसे प्यास लगी है। क्लासरूम में पानी है। लेकिन वह पी नहीं पा रहा है।

यह. इसलिए नहीं कि पानी है गंदा। इसलिए नहीं कि क्लास में शराब पीने का कोई नियम है। वह इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि जो चपरासी उसके हाथों में पानी डालने वाला होता है, ऊंचाई से, ताकि उसके छूने से बर्तन गंदा न हो, वह उस दिन गायब रहता है।

न चपरासी, न पानी। भीमराव रामजी अंबेडकर का बचपन इसी नियम के तहत बीता।

उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल एस्से 'वेटिंग फॉर ए वीज़ा' और 'नो पीन, नो वॉटर' नाम के हिस्से में इस बारे में बहुत शांत और सटीक तरीके से लिखा है। वह और उनके भाई-बहन, अपने पिता से मिलने जा रहे थे, और प्यास से तड़पते हुए एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। किसी ने उन्हें पानी नहीं दिया।

वे महार थे। वे "अछूत" थे। पब्लिक नल उनके लिए नहीं था।

उस इमेज को कुछ समय तक अपने साथ रहने दें पल: छोटे बच्चे, प्यासे, पानी से घिरे हुए, पी नहीं पा रहे।

रेगिस्तान में नहीं, बल्कि स्कूल में। अकाल के समय में नहीं, बल्कि बहुतायत के समय में।

वह लड़का बड़ा हुआ। वह कोलंबिया गया। वह लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स गया। उसने ग्रेज़ इन में कानून की पढ़ाई की।

और फिर वह घर आया और पानी की टंकी के पास गया।

महाड में क्या हुआ था? 20 मार्च, 1927 को, अंबेडकर ने बॉम्बे प्रेसीडेंसी में कोंकण के एक छोटे से शहर महाड की सड़कों पर हज़ारों लोगों के जुलूस को लीड किया। उनकी मंज़िल चावदार तले थी, जो एक पब्लिक पानी की टंकी थी। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1923 में बोले रेज़ोल्यूशन पास किया, और महाड म्युनिसिपैलिटी ने 1924 में दबे-कुचले लोगों के लिए टंकी खोल दी।

लेकिन कागज़ पर प्रस्ताव और गले में पानी दो अलग-अलग चीज़ें हैं। ऊँची जातियों ने यह पक्का किया कि प्रस्ताव एक मरा हुआ पत्र ही रहे।

अंबेडकर टैंक के पास गए। वह नीचे झुके। उन्होंने पानी पिया।

हज़ारों लोग उनके पीछे चले - मर्द, औरतें, बच्चे। उन्होंने पानी पिया। शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार, उन्होंने किसी पब्लिक सोर्स से पानी अधिकार के तौर पर पिया, न कि चोरी-छिपे या दान के तौर पर।

और फिर हिंसा शुरू हो गई। अफवाहें यह बात फैल गई कि सत्याग्रही वीरेश्वर मंदिर में घुसना चाहते हैं। लौट रहे प्रतिनिधियों पर सड़कों पर, उनकी बैलगाड़ियों में, उनके गांवों में हमला किया गया। तालाब को गाय के गोबर और मूत्र से "शुद्ध" किया गया, मानो इंसानी इज़्ज़त कोई ऐसी गंदगी हो जिसे धोया जा सकता है।

जब अंबेडकर 1922 में महाड लौटे दिसंबर 1927 में दूसरी कॉन्फ्रेंस के लिए, वे अपने साथ न सिर्फ़ दोबारा पानी पीने का संकल्प लेकर आए, बल्कि एक गहरा सांकेतिक इरादा भी लेकर आए। 25 दिसंबर, 1927 को कॉन्फ्रेंस ने सबके सामने मनुस्मृति की एक कॉपी जलाई। वह सिर्फ़ एक इशारा नहीं था। यह एक घोषणा थी कि भविष्य का गणतंत्र, अगर उसका कोई मतलब है, तो अधिकारों पर टिका होगा, न कि पुरानी किताबों में लिखी गई भेदभाव वाली सोच पर।

अदालत में दस साल सत्याग्रह के बाद जो हुआ वह उतना ही शिक्षाप्रद था जितना कि सत्याग्रह खुद।

महाड की ऊंची जातियों ने सिर्फ हिंसा का सहारा ही नहीं लिया, बल्कि वे कोर्ट भी गए।

20 मार्च, 1927 को अंबेडकर ने महाड की सड़कों पर हज़ारों लोगों के जुलूस का नेतृत्व किया। फ़ाइल फ़ोटो

12 दिसंबर, 1927 को, दूसरी कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही, हिंदू लोगों ने कोलाबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सिविल केस किया, जिसमें दबे-कुचले लोगों को चावदार टैंक इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कुछ समय के लिए रोक लगाने की मांग की गई थी। 14 दिसंबर, 1927 को रोक लगा दी गई।

संवैधानिक तरीकों में अपने विश्वास के अनुसार, अंबेडकर ने अपनी कॉन्फ्रेंस जारी रखते हुए कोर्ट के आदेश का सम्मान किया। उन्होंने सभा को संबोधित किया।

उन्होंने मनुस्मृति जलाई, लेकिन वे टैंक पर नहीं गए।

यह केस एक दशक तक चला। यह महाड के ट्रायल कोर्ट और फिर थाने के असिस्टेंट जज के कोर्ट से गुज़रा। हर स्टेज पर, कोर्ट ने माना कि शिकायत करने वाला कोई भी पुराना रिवाज साबित करने में नाकाम रहा है, जिससे सवर्ण हिंदुओं को अछूतों को तालाब से बाहर रखने का हक मिलता हो।

मामला आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में 17 मार्च, 1937 को जस्टिस ब्रूमेल और एन.जे. वाडिया ने नरहरी दामोदर वैद्य बनाम दिल्ली हाई कोर्ट में यह फैसला सुनाया था।

भीमराव रामजी अंबेडकर। जस्टिस ब्रूमेल्ड ने एक बात जो याद रखने लायक है, उसमें कहा कि अपील करने वालों ने वह पुराना रिवाज शुरू नहीं किया था जिसका उन्होंने आरोप लगाया था। तालाब नगर पालिका का था। यह पब्लिक प्रॉपर्टी थी। अछूतों को इसका इस्तेमाल करने का पूरा हक था।

एक आदमी ने पानी पीने के लिए जुलूस निकाला 1927 में एक सार्वजनिक टैंक से। 1937 तक अदालतों को यह पुष्टि करने में समय लगा कि वह ऐसा करने का हकदार था।

कानून ने अंबेडकर को सही साबित किया। लेकिन यह बात कि सही साबित होने में एक दशक लग गया, यह अपने आप में बताता है कि उन्हें कितना विरोध झेलना पड़ा।

नमक बनाम पानी महाड़ के तीन साल बाद, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के लिए निकले ।

नमक सत्याग्रह पॉलिटिकल लामबंदी का एक मास्टरस्ट्रोक था। इसने कॉलोनियल सरकार के आर्थिक सिस्टम को चुनौती दी और दुनिया भर के प्रेस का ध्यान खींचा। देश की खबरों में इसकी जगह पक्की है, और सही भी है। लेकिन सोचिए कि हर सत्याग्रह असल में क्या मांग कर रहा था, और किससे।

नमक मार्च ने अंग्रेजों से आज़ादी की मांग की। महाड सत्याग्रह ने साथी भारतीयों से आज़ादी की मांग की।

दांडी ने एक बाहरी ज़ालिम को पहचाना और उसे जाने के लिए कहा। महाद ने एक अंदरूनी बीमारी को पहचाना और एक सभ्यता से खुद को ठीक करने के लिए कहा। एक के लिए एक विदेशी शासक के खिलाफ़ हिम्मत की ज़रूरत थी। दूसरे के लिए कुछ और मुश्किल चाहिए था: अपने पड़ोसियों, अपने ही धर्म के लोगों, अपने ही देश के लोगों की आँखों में आँखें डालकर यह कहने की इच्छा, "आपने हमारे साथ इंसानों से कम बर्ताव किया है, और हम इसे अब और नहीं मानेंगे।"

नमक मार्च का कोई अपमान नहीं है यह कहते हुए। लेकिन एक ऐतिहासिक असंतुलन है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है।

नमक टैक्स एक साम्राज्य का लगाया हुआ टैक्स था। एक बार साम्राज्य चला गया, तो कानून बनाकर टैक्स खत्म किया जा सकता था। इसके उलट, छुआछूत न तो अंग्रेजों के साथ आई और न ही उनके साथ गई। यह हज़ारों सालों से भारतीय जीवन के सामाजिक ताने-बाने में शामिल थी। इसके लिए सरकार बदलने की नहीं, बल्कि दिल बदलने की, रीति-रिवाज बदलने की, और यह सोचने की ज़रूरत थी कि इंसान कौन है।

यह कोई संयोग नहीं है कि चावदार में पानी पीने वाला आदमी आगे चलकर ड्राफ्ट बन गया संविधान के भाग III की बनावट में महाड का वॉटरमार्क है।

आर्टिकल 15, जो जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है और खास तौर पर कुओं, तालाबों, नहाने के घाटों और पब्लिक जगहों तक पहुंच के बारे में बताता है, ऐसा लगता है जैसे अंबेडकर की आंखों के सामने चावदार तालाब था।

आर्टिकल 17, जो छुआछूत को खत्म करता है और इसे सज़ा का हक़दार बनाता है, महाड सत्याग्रह का कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट है।

दांडी मार्च ने भारत को स्वराज की चाहत दी। महाड ने भारत को बराबरी का ग्रामर दिया। स्वराज कई हाथों से लिखा जा सकता था। बराबरी का ग्रामर सिर्फ़ वही लिख सकता था जिसे बचपन में पानी नहीं मिला हो।

शताब्दी मनाने की बात महाड सत्याग्रह की 100वीं सालगिरह 20 मार्च, 2027 को है। अब हम 99वें साल में हैं। अगर इस रिपब्लिक को अपनी शुरुआत का ज़रा भी एहसास है, उन संघर्षों की कोई सच्ची याद है जिनसे इसे संविधान मिला, तो इसे इस शताब्दी को उस गंभीरता और शान के साथ मनाना चाहिए जिसका यह हकदार है।

मैं 20 मार्च, 2026 से शुरू होकर 20 मार्च, 2027 को चावदार तालाब पर एक बड़ी सभा के साथ एक साल तक चलने वाले जश्न का प्रस्ताव रखता हूँ। हर जाति, धर्म और वर्ग के नागरिक महाड आएं और साथ में पिएं। इसे एक संवैधानिक बपतिस्मा बनने दें: इस बुनियादी वादे में फिर से डूब जाना कि किसी भी भारतीय का जन्म के इत्तेफ़ाक से कोई नुकसान नहीं होगा।

लेकिन हमें सिर्फ़ रस्मों तक ही नहीं रुकना चाहिए।

शताब्दी वर्ष को ईमानदारी से हिसाब-किताब का साल बनने दें। आइए हम पूछें कि क्या आज ग्रामीण भारत के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, दलित लड़का, आदिवासी लड़की, सफ़ाई कर्मचारी की बेटी, सच में "चपरासी नहीं, तो पानी नहीं" वाले नियम से आज़ाद है, या उस नियम को सिर्फ़ नई शब्दावली मिल गई है और उसका ज़हर अभी भी बना हुआ है।

आइए हम पूछें कि क्या हमारे सीवर को नंगे हाथों से साफ करने वाले मैला ढोने वाले की स्थिति, चावदार तालाब से रोके गए महारों से बिल्कुल अलग है। आइए हम पूछें कि क्या संविधान की किताब गणतंत्र की सच्चाई बन गई है।

यह शताब्दी सभी के लिए, सबसे पीछे, सबसे कमज़ोर और खोए हुए लोगों के लिए सच्ची बराबरी की मांग होनी चाहिए। हर उस भारतीय के लिए जिसे जन्म की लॉटरी अभी भी कम नागरिकता, अनदेखी मेहनत, सामाजिक तकलीफ़ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करती है, जो अब अन्याय के तौर पर भी दर्ज नहीं होती। चावदार तालाब का पानी फिर से बहना चाहिए, ऐतिहासिक याद के तौर पर नहीं बल्कि एक ज़िंदा कमिटमेंट के तौर पर।

अंबेडकर ने सिर्फ़ एक संविधान का ड्राफ़्ट नहीं बनाया था। उन्हें सबसे पहले एक छोटे से शहर में एक तालाब तक चलकर और उससे पानी पीकर यह साबित करना था कि जिनके लिए वह एक दिन वह संविधान लिखेंगे, वे पीने लायक इंसान हैं। वह काम, जो बहुत ही क्रांतिकारी, सरल और ज़बरदस्त था, भारतीय संविधानवाद का बुनियादी पल बना हुआ है। यह दांडी से पहले हुआ था। इसने जो मांग की, और जिनसे मांग की, उसमें यह दांडी से भी ज़्यादा गहरा था।

और अधूरे काम में भारतीय समानता, अभी भी अपनी पूरी मुक्ति का इंतज़ार कर रही है। सौ साल पूरे होने वाले हैं। गणतंत्र को याद रखना चाहिए, कहीं वह भूल न जाए।

(संजय हेगड़े सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले सीनियर एडवोकेट हैं)

अभिलेखागार से

अपने को जानो अंग्रेज़ी

एस. उपेंद्रन

26 दिसंबर को "बॉक्सिंग डे" क्यों कहा जाता है? (जे. शंकर, त्रिवेंद्रम)

इंग्लैंड में 15वीं और 16वीं सदी में चर्चों में खास बक्से रखे जाते थे, जो पूरे साल बंद रहते थे। लोग, जो आम तौर पर अमीर होते थे, साल भर उनमें पैसे डालते रहते थे।

26 दिसंबर को ये बक्से खोले गए और उनमें रखे पैसे गरीबों में बांट दिए गए।

क्योंकि बॉक्स 26 दिसंबर को खोले गए थे, इसलिए उस खास दिन को बॉक्सिंग डे कहा जाने लगा। ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पर इस दिन टेस्ट मैच शुरू होता है।

इस दिन यह प्रथा भी थी प्रशिक्षु हाथ में एक डिब्बा लेकर अपने मालिक के ग्राहकों से मिलने जाते थे। ग्राहक उन्हें उपहार दिखाते थे और कुछ लोग डिब्बे में पैसे डाल देते थे।

ये बॉक्स जो लड़के ले जाते थे, अक्सर सुअर के आकार के होते थे। ये पहले "पिगी बैंक" थे।

"कैकोफनी" शब्द का क्या मतलब है? इस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है? (वाई.के. कुमार चौधरी, नई दिल्ली)

क्या आपका कभी कोई ऐसा पड़ोसी रहा है जिसके बच्चों ने अभी-अभी म्यूज़िक सीखना शुरू किया हो? ऐसे बच्चे जो अभी-अभी गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना शुरू कर रहे हों, खासकर वायलिन। अगर आपका कोई ऐसा पड़ोसी है, तो आप जानते हैं कि शोर-शराबा क्या होता है।

"कैकोफनी" एक फॉर्मल शब्द है जिसका मतलब है तेज़, बुरा शोर। कैकोफनी में, आमतौर पर कई बुरी आवाज़ें होती हैं।

पहले सिलेबल में "a" और "pho" में "o" का उच्चारण "china", "about", और "amount" में "a" की तरह होता है। दूसरे सिलेबल "co" में "o" का उच्चारण "pot", "hot", और "got" जैसे शब्दों के "o" जैसा होता है।

कुछ लोग इसे "harm", "arm", और "farm" में इस्तेमाल होने वाले "ar" की तरह बोलते हैं। "o" को चाहे जैसे भी बोला जाए, ज़ोर दूसरे सिलेबल पर ही पड़ता है।

मेरा एक दोस्त है जो हर दिन इंटरनेट सर्फ करने के लिए मजबूर महसूस करता है। क्या ऐसे व्यक्ति के लिए कोई शब्द है? (पी. माला, मैसूर)

मुझे यकीन है कि इंटरनेट एडिक्ट के लिए कई शब्द हैं। एक शब्द, जो मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, वह है "इंटरनेट-डिपेंडेंट"। जैसे कुछ लोग ड्रग्स पर डिपेंडेंट होते हैं, वैसे ही इंटरनेट-डिपेंडेंट व्यक्ति अपनी "किक्स" के लिए इंटरनेट पर डिपेंडेंट रहता है।

इंटरनेट की रेगुलर डोज़ के बिना, वह परेशान, पैरानॉइड वगैरह हो जाता है।

जो व्यक्ति कंप्यूटर के सामने बैठकर लंबे समय तक काम करता है, उसे "माउस पोटैटो" कहा जाता है। वह "इंटरनेट-डिपेंडेंट" हो भी सकता है और नहीं भी।

क्या यह ठीक है कि आप अपने से छोटे किसी व्यक्ति को पत्र लिखते समय "विथ रिगार्ड्स" कहकर पत्र खत्म करें? (आर. रामा सुब्रमण्यम, कोयंबटूर)

भारत में, कुछ लोग अपने से छोटे किसी व्यक्ति को पत्र लिखते समय "सादर" का प्रयोग नहीं करना पसंद करते हैं।

इसके बजाय वे "शुभकामनाएं" का प्रयोग करना पसंद करते हैं। जब वे अपने से बड़े किसी व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, तो वे पत्र को या तो "सादर" या "आदर सहित" के साथ समाप्त करते हैं।

इंग्लिश बोलने वाला अपने से छोटे और बड़े लोगों के साथ "रिगार्ड्स" का इस्तेमाल करता है। उनके खतों में "विद काइंड रिगार्ड्स", "विद वार्म रिगार्ड्स", और "विद बेस्ट रिगार्ड्स" देखना आम बात है। कुछ डिक्शनरी में लिखा है कि यह

लेटर खत्म करने का एक दोस्ताना लेकिन फॉर्मल तरीका।

28 दिसंबर, 1999 को द हिंदू में प्रकाशित

Word of the day

Haywire: erratic; out of control

Synonyms: chaotic, faulty, confused

Usage: *Everything went haywire after the storm.*

Pronunciation: newsth.live/haywire

International Phonetic Alphabet: /heɪwaɪə/

दैनिक प्रश्नोत्तरी

कृपया अपने जवाब dailyquiz@thehindu.co.in पर भेजें।

अमेरिका ने 2003 में आज ही के दिन इराक युद्ध शुरू किया था। यह 2011 तक चला और इसमें लगभग 1.5 लाख से 10 लाख लोग मारे गए।

राधिका संथानम

X

प्रश्न 1 इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को दिसंबर 2003 में अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया था। इस ऑपरेशन का नाम एक अमेरिकी फिल्म के नाम पर रखा गया था, जो तीसरे विश्व युद्ध के दौरान की काल्पनिक कहानी पर आधारित थी। उस फिल्म का नाम क्या था?

द फ़िल्म?

X

सवाल 2 2007 में, एक प्राइवेट मिलिट्री फर्म के सदस्यों ने, जिसे US सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, बगदाद के निसौर स्क्वायर में 17 इराकी नागरिकों को मार डाला। फर्म के चार कर्मचारियों पर बाद में US फेडरल कोर्ट में मुकदमा चला और उन्हें दोषी ठहराया गया।

उस समय फर्म का नाम क्या था (उसने तब से अपना नाम बदल लिया है)? और किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने चारों को माफ़ किया था?

कर्मचारी?

X

प्रश्न 3 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने ज़ोर देकर कहा था कि इराक एक "बढ़ता हुआ खतरा" है जिसका सामना करना होगा।

क्या उन्होंने कहा कि इराक पर कब्ज़ा है?

एक्स

प्रश्न 4 इस यूरोपीय देश ने इराक पर राष्ट्रपति बुश की नीति का विरोध किया।

इसके जवाब से निराश होकर, US ने ऑर्डर दिया कि US के रेस्टोरेंट में उन खाने की चीज़ों के नाम बदल दिए जाएं जिनमें देश का नाम आता है।

कैपिटल. यह कौन सा देश था?

एक्स

प्रश्न 5 श्री बुश ने बुराई की धुरी का उल्लेख किया -

उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकारें आतंकवाद को स्पॉन्सर करती हैं। वे जिन तीन देशों की बात कर रहे थे, उनके नाम बताइए।

X

विज़ुअल सवाल: इस पेंटिंग की एक टेपेस्ट्री कॉपी यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में मिल सकती है। इसे 2003 में UN में कवर किया गया था क्योंकि यह एक एंटी-वॉर पेंटिंग है और US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट कॉलिन पॉवेल UN में इराक के साथ युद्ध के लिए अमेरिका का केस पेश कर रहे थे।

पिकासो की पेंटिंग को क्या कहते हैं?

पिछले दिन के डेली क्विज़ के सवाल और जवाब: 1. डार्विन के फिंच के ऑब्ज़र्वेशन, पैसिफिक आइलैंड के किस ग्रुप में एडैप्टिव रेडिएशन की चर्चा का सेंटर बने?

उत्तर: गैलापागोस द्वीप समूह 2. 1925 का प्रसिद्ध अमेरिकी मुकदमा स्कूलों में इवोल्यूशन की पढ़ाई किस नाम से जानी जाती है? जवाब: स्कोप्स ट्रायल 3. 1861 में खोजे गए किस फॉसिल पक्षी ने डायनासोर और पक्षियों को जोड़ने वाले शुरुआती सबूत दिए? जवाब: आर्कियोप्टेरिक्स 4. कौन सा शब्द 20वीं सदी के इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क को बताता है जिसने डार्विनियन इवोल्यूशन को मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ जोड़ा?

उत्तर: मॉडर्न सिंथेसिस 5. कौन सी बायोलॉजिकल यूनिट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हेरेडिटरी जानकारी ले जाती है?

जवाब: जीन विज़ुअल: इस इमेज को पहचानें। जवाब: चार्ल्स डार्विन का पहला इवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम अर्ली बर्ड्स: सुचित नरोत्तम | अक्षांश ठाकुर | प्रेम नाथ तिवारी | केएन विश्वनाथन

दैनिक जागरण
आचरण व्यक्तित्व का दर्पण है

वैश्विक हितों पर हमले

इजरायल की ओर से अपने गैस फील्ड साउथ पार्स को निशाना बनाए जाने के जवाब में ईरान ने जिस तरह सऊदी अरब, कतर और कुवैत की रिफाइनरियों पर हमले किए, उसके बाद कच्चे तेल के दाम बढ़ने ही थे। समस्या केवल यह नहीं कि तेल के दाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि खाड़ी के देशों से उसकी आपूर्ति में भी कठिनाई आ रही है। तेल के साथ गैस की आपूर्ति में भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। साफ है कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध ऊर्जा संकट को गंभीर बनाने का काम कर रहा है। ईरान ने अपने यहां के ऊर्जा स्रोतों पर हमले के जवाब में पड़ोसी देशों के ऐसे ही स्रोतों को निशाना बनाने की जो रणनीति अपनाई है, उससे अमेरिका के साथ खाड़ी के देश ही नहीं, पूरी दुनिया परेशान है। यह साफ है कि अमेरिका ने यह सोचा ही नहीं था कि ईरान इस तरह ऊर्जा संकट गहराने की रणनीति अपना सकता है, लेकिन वह इसी रणनीति पर चल रहा है। पहले उसने खाड़ी देशों से तेल और गैस की आपूर्ति के समुद्री मार्ग होर्मुज को बाधित किया, फिर उसने इन देशों के ऊर्जा स्रोतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने खाड़ी देशों के कुछ ऊर्जा स्रोतों को तो इस तरह निशाना बनाया कि उनसे तेल और गैस का उत्पादन ही ठप हो गया है।

चूंकि तेल और गैस के उत्पादन में कमी के साथ उसकी आपूर्ति भी बाधित हो गई है, इसलिए पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट की तपिश झेलनी पड़ रही है। कई देशों को तेल और गैस के दाम बढ़ाने पड़े हैं। कुछ देशों में गैस की किल्लत होने से घरों में खाना बनाने के साथ-साथ छोटे-बड़े उद्योग चलाना भी कठिन हो गया है। तेल एवं गैस के दाम बढ़ने और उनकी आपूर्ति प्रभावित होने से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट भी देखी जा रही है। एक तरह से ईरान पर हो रहे अमेरिका एवं इजरायल के हमले और उनके जवाब में ईरान की कार्रवाई वैश्विक हितों पर तगड़ी चोट पहुंचाने का काम कर रही है। वैश्विक हितों के लिए यह जो गंभीर खतरा पैदा हो गया है, उसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका जिम्मेदार है। यदि वह ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं होता तो इजरायल शायद ही अपने दम पर ऐसा करने के लिए आगे आता। अब तो ऐसा लगता है कि इन दोनों में रणनीतिक तालमेल का भी अभाव है। इसका संकेत इजरायल की ओर से ईरान के गैस फील्ड को निशाना बनाए जाने पर अमेरिका की असहमति से मिलता है। इस असहमति मात्र से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान भी संयम बरतने को तैयार नहीं दिख रहा है। अब जब पश्चिम एशिया का संकट विश्व का संकट बन गया है, तब भारत समेत विश्व के सभी समर्थ देशों को इस युद्ध को बंद कराने के लिए सक्रिय होना चाहिए और इसके लिए अमेरिका पर दबाव बढ़ाना चाहिए।

परिधान संहिता का पक्ष

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बुधवार को जारी आदेशों में तय कर दिया है कि उनसे कैसा परिधान पहनना अपेक्षित है। पत्र का दूसरा भाग उन सरोकारों को संबोधित कर रहा है जो इंटरनेट मीडिया पर सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की बहुमुखी उपस्थिति से जुड़े हैं। अधिकारी हों या कर्मचारी, वे कार्यस्थल पर सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में उनसे गरिमापूर्ण परिधान की अपेक्षा कोई अपराध नहीं है। इस आदेश की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि कतिपय अधिकारी अपने काम के लिए कितने जाने जाते हैं, यह जानकारी नहीं किंतु इंटरनेट मीडिया पर अन्यान्य कारणों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। बीते कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई थी कि उससे सामाजिक संस्कृति का पता नहीं, कार्यसंस्कृति अवश्य रगड़ खाने लगी थी। सरकार ने केवल ड्रेस कोड तय किया है, वर्दी नहीं सुझाई है। संभव है, कई व्यक्तियों को यह निर्णय सहजता से न पचे किंतु यह मानना ही होगा कि जब कोई किसी व्यवस्था का भाग होता है तो उसके लिए आवश्यक होता है कि वैयक्तिक अपेक्षाएं नेपथ्य में रखे। प्रदेश में यह विमर्श 2017 से आरंभ हुआ था जब एक सरकारी कर्मचारी उच्च न्यायालय में जींस-टाप पहन कर सुनवाई के लिए चली गई थी। उसके बाद शासन को परामर्शिका जारी करनी पड़ी थी। परामर्श में दंड का तत्व नहीं होता इसलिए उससे भी आगे के दृश्य प्रदेश में दिखाई पड़े। ये उदाहरण आम हो गए थे, इसलिए, परामर्श का स्थान आदेश ने ले लिया। अब दृष्टि क्रियान्वयन पर रहेगी।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कार्यस्थल पर गरिमापूर्ण परिधान की अपेक्षा कोई अपराध नहीं है

अविश्वास का खतरनाक विस्तार

राज कुमार सिंह

पहले लोकसभा अध्यक्ष और अब मुख्य चुनाव आयुक्त पर विपक्ष का अविश्वास लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं

राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़, फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध महाभियोग का नोटिस सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास के खतरनाक विस्तार का ही संकेत है। चुनाव केंद्रित संसदीय राजनीति में दलगत विरोध अप्रत्याशित नहीं हैं। अतीत में भी कई बार किसी मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष में टकराव के चलते कई-कई दिन संसद नहीं चल पाई। पूरा सत्र ही गतिरोध की भेंट चढ़ जाने के उदाहरण भी हैं, लेकिन 2014 के बाद राजनीतिक टकराव परंपराएं और लक्ष्मण रेखाएं लांघता दिख रहा है। 2024 के अंत में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियागत और तकनीकी त्रुटियों के चलते नोटिस से आगे नहीं बढ़ पाया था। उपसभापति हरिवंश ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नियमानुसार 14 दिन पहले न देने के आधार पर खारिज करते हुए बताया था कि जगदीप धनखड़ के नाम की स्पेलिंग भी गलत लिखी गई थी।

अतीत में भी तीन बार लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया और हर बार गिरा भी, क्योंकि उनका चयन ही बहुमत से होता है। अल्पमत विपक्ष उन्हें हटा ही नहीं सकता, जब तक कि सत्तापक्ष में विभाजन की नौबत न आए। लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने का सीधा अर्थ है कि बहुमत खो चुकी सरकार को भी जाना पड़ेगा। अल्पमत विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य स्पीकर के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति ही होता है। तथ्यात्मक गलतियां ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में भी थीं, पर उन्होंने स्वयं उन्हें ठीक कराते हुए पेश होने दिया।

ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गंभीर आरोप-प्रत्यारोप और टकराव की हद तक चला गया तो उसके मूल में पिछली लोकसभा की कटुता भी रही, जब बिरला ही स्पीकर थे। तब रिकार्ड संख्या में विपक्षी सांसद निलंबित किए गए। उस वक्त राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, पर बोलने न देने और माइक बंद कर देने के आरोप तब भी लगे थे। किसी भी सदन का संचालन अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, पर सत्तापक्ष और विपक्ष की परस्पर समझदारी और सम्मान भाव से ही सदन सुचारु रूप से चल सकता है, लेकिन वे तो एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। सत्तापक्ष के विरुद्ध विपक्ष की आक्रामकता का नजला स्पीकर पर गिरा। अविश्वास प्रस्ताव की परिणति जानते हुए ही विपक्ष ने मत विभाजन नहीं मांगा, लेकिन इससे यह सच नहीं बदलता कि स्पीकर पर विपक्ष का विश्वास नहीं है। जिस ब्रिटेन से हमारी संसदीय प्रणाली प्रेरित है, वहां स्पीकर किसी दल के सदस्य नहीं होते। अपने देश में भी कभी लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर नीलम संजीव रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा दिए बिना भी दोनों पक्षों का सम्मान हासिल करते हुए सुचारु सदन संचालन के सोमनाथ चटर्जी और पीए संगमा सरीखे उदाहरण हैं, पर अब बढ़ते तनाव से इस संस्था की साख प्रभावित होने लगी है। यह राजनीतिक दलों की सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। व्यक्ति आते-जाते रहेंगे, लेकिन संस्थाओं की साख पर आंच नहीं आने देनी चाहिए।

अवधेश राजपूत

मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग का नोटिस राजनीतिक टकराव का विस्तार है। कभी मत्रपत्रों की लूट तो अब ईवीएम पर संदेह के जरिये चुनाव प्रक्रिया की शुचिता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस तरह कठघरे में खड़ा कभी नहीं किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां हमेशा केंद्र सरकार करती है। पसंदीदा नौकरशाहों की नियुक्ति के आरोप भी लगते रहे हैं। नवीन चावला की कांग्रेस से नजदीकियों के तब तमाम उदाहरण दिए गए थे। मनोहर सिंह गिल को तो कांग्रेस ने राज्यसभा सदस्य और केंद्र में मंत्री भी बनाया। फिर अब क्यों बात मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग के नोटिस तक पहुंच गई? चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की धांधली और फिर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती का घटनाक्रम ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल से पहले का है। हां, कुछ नियम-कानूनों में संशोधन अवश्य हुए हैं, जिन्हें विपक्ष पारदर्शिता से विचलन बताता है, पर उन्हें न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। चुनाव आयोग से विपक्ष के ताजा टकराव के मूल में एसआइआर मुख्य मुद्दा है। अतीत में भी मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होता रहा है, लेकिन इस बार जैसी अफरातफरी कभी नहीं मची। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम भी कभी नहीं कटे। शायद इसलिए कि इस बार आइआर की जगह एसआइआर कराया जा रहा है। ऐसे विशेष सघन पुनरीक्षण से पहले सभी दलों और राज्य सरकारों से चर्चा न करने से उठे सवालों का जवाब तो चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, लेकिन मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण से लेकर चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने संबंधी कदमों को सर्वोच्च न्यायालय आयोग का अधिकार बता चुका है।

बिहार से शुरू एसआइआर विवाद के बंगाल पहुंचने तक सर्वोच्च न्यायालय कई बार सुनवाई कर चुका है। कुछ मामलों में न्यायालय ने चुनाव आयोग को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। बंगाल में राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच मोर्चा खुल जाने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने एसआइआर की निगरानी के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए। प्रक्रियागत जटिलताओं के बावजूद एसआइआर असंवैधानिक नहीं है। फिर भी टकराव का मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध देश में पहली बार महाभियोग के नोटिस तक पहुंच जाना सवाल खड़े करता है। महाभियोग की जटिल प्रक्रिया के चलते विपक्ष की इस मुहिम की सफलता संदिग्ध ही है। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग के मुखिया तथा लोकसभा के अध्यक्ष पर विपक्ष का अविश्वास लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। यह चिंता प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एजेंडा में भी सर्वोपरि होनी चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

पड़ोसी देशों का भरोसा तोड़ता ईरान

रामिश सिद्दीकी

खाड़ी देशों के नागरिक क्षेत्रों पर ईरान के लगातार हमले उसके अपने ही हितों को नुकसान पहुंचाएंगे

युद्ध के समय देशों के लक्ष्य बदल जाते हैं। उस समय केवल तात्कालिक बातें जैसे- जवाबी हमला, दबाव, सुरक्षा, शक्ति प्रदर्शन और अस्तित्व बचाना दिखाई देती हैं। दीर्घकालिक सोच अल्पकालिक में बदल जाता है। ऐसे में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि युद्ध कभी शाश्वत नहीं होते। प्रथम विश्वयुद्ध भी समाप्त हुआ और द्वितीय विश्वयुद्ध भी। हर युद्ध अंततः एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है, जहां असली चुनौती लड़ाई नहीं, बल्कि टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ना और बचे हुए लोगों के साथ दोबारा सामान्य जीवन बिताना होता है। इसी दृष्टि से आज पड़ोसी इस्लामी देशों पर ईरान के लगातार हमले दीर्घकालिक रणनीति के रूप में उसके अपने ही हितों के विरुद्ध हैं। किसी भी सैन्य कार्रवाई के पीछे तात्कालिक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके राजनीतिक और सामाजिक मूल्य कहीं अधिक दूर तक जाते हैं।

क्षतिग्रस्त इमारतें फिर बन सकती हैं, बाधित हवाईअड्डे फिर खुल सकते हैं और अर्थव्यवस्था भी समय के साथ संभल सकती है, पर पड़ोसियों के बीच एक बार टूटा विश्वास आसानी से वापस नहीं आता। यह विश्वास हर मिसाइल, ड्रोन हमलों के साथ और कमजोर होता जा रहा है, जो खाड़ी के देशों में नागरिक क्षेत्रों में भय पैदा करता है। यह केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि ईरान और उसके पड़ोसी देशों के भविष्य का भी प्रश्न है। ईरान कोई ऐसा देश नहीं है, जो दुनिया के किसी अलग कोने में बसा हो। करीब सात देशों के साथ उसकी सीमा लगती है। संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में लाखों की संख्या में ईरानी लोग पीढ़ियों से बसे हुए हैं। दुबई जैसे शहरों में ईरानी लोगों की व्यापारिक उपस्थिति लंबे समय से आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। ऐसे में यदि वही देश आज ईरान के हमलों से भय और असुरक्षा महसूस करने लगें, तो यह स्थिति केवल सामरिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक संकट भी खड़े करती है। सोचने की बात यह है कि दुबई, मनामा या कुवैत में रहने वाला कोई ईरानी परिवार आज क्या महसूस कर रहा होगा? जिस देश ने उसे काम, सुरक्षा और जीवन का आधार दिया, उसी देश पर उसके मूल देश का नाम हमलों के साथ जुड़ रहा है। रोजमर्रा का जो भरोसा लोगों को साथ रहने देता है, जब उसी में भय घर कर जाए, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। किसी भी क्षेत्र को केवल सैन्य ताकत नहीं बांधती। उसे वह भरोसा बांधता है कि पड़ोसी एक-दूसरे के नागरिकों को डर और विनाश का माध्यम नहीं बनाएंगे।

दुबई हवाई अड्डे के निकट ईरान का हमला। एपी

जब किसी देश पर हमला होता है, तो उसे आत्मरक्षा का अधिकार होता है। दुनिया इसे समझती है और अंतरराष्ट्रीय कानून भी इस अधिकार को मान्यता देता है, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार असीमित नहीं होता। उसकी वैधता इससे तय होती है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? ईरान यह कहकर अपने पड़ोसी देशों के नागरिक ठिकानों और ऊर्जा स्रोतों पर हमले नहीं कर सकता कि इन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। यह अंतर समझना जरूरी है कि अपनी रक्षा करना एक बात है और युद्ध को इस तरह फैलाना कि उसका डर पड़ोस के आम लोग उठाएं, बिल्कुल दूसरी बात है। जब से अमेरिका-इजरायल एवं ईरान का युद्ध शुरू हुआ है, तब से एक दिन ऐसा नहीं बीता, जब खाड़ी देशों में रहने वाले नागरिकों को भय के साए में न रहना पड़ा हो। न तो इन देशों में रहने वाले लोग ईरान के प्रति कोई द्वेष रखते हैं, न इनमें से कोई देश ईरान पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार है। फिर भी ईरान प्रतिदिन इन देशों को यह कहकर निशाना बना रहा है कि वह इन देशों को नहीं, बल्कि वहां जो अमेरिकी ठिकाने हैं, उन्हें निशाना बना रहा है, लेकिन वह तो नागरिक क्षेत्रों पर हमले कर रहा है। यह न तो दीर्घकालिक नीति हो सकती है और न ही नैतिक रूप से एक टिकाऊ तर्क।

पड़ोसी देशों पर हमलों के साथ ईरान ने होर्मुज जलमार्ग बंद करने का जो निर्णय लिया, वह भी उसके अल्पकालिक सोच की तरफ इशारा करता है। यह केवल समुद्री नक्शे पर एक सामरिक बिंदु नहीं है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण जीवनरेखा है। वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। यदि यहां गंभीर व्यवधान पैदा होता है, तो उसका असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया भर के आम लोगों का जीवन प्रभावित होता है। ईरान के लिए विवेकपूर्ण रास्ता यही होगा कि वह न सिर्फ पड़ोसी खाड़ी देशों के नागरिक ठिकानों और ढांचे के प्रति संयम दिखाए, बल्कि होर्मुज जलमार्ग बंद होने के कारण बढ़ रही समस्याओं और तनाव को भी खत्म करे। आज ईरान को दीर्घकालिक सोच की जरूरत है। युद्ध कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन ईरान की भौगोलिक वास्तविकता जरूर स्थायी है। वर्तमान में प्रत्येक देश को व्यापार, सुरक्षा आदि के लिए अपने पड़ोसी देशों की आवश्यकता पड़ती है। यदि वही विश्वास आज क्षीण हो गया, तो कल किसी भी पुनर्निर्माण प्रक्रिया की नींव कमजोर ही रहेगी। युद्ध के बाद केवल टूटी इमारतें नहीं गिनी जातीं। यह भी देखा जाता है कि समाजों के बीच कितना भरोसा बचा है। पड़ोसियों के बीच यह भरोसा लौटने में अधिक समय लगता है कि साथ रहा जा सकता है। कल ईरान के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होने वाला है कि टूटे भरोसे को फिर से कैसे हासिल किया जाए?

(लेखक इस्लामी मामलों और पश्चिम एशिया के जानकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

दान

दान के कई प्रकार हैं, जिनमें अन्नदान पर काफी बल दिया गया है। कहा गया है कि पड़ोसी यदि भूखा है, तो हमारा कर्तव्य होता है कि उसे भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसी तरह संयुक्त परिवार का कोई सदस्य आजीविका के मामले में अशक्त है, तो उसकी मदद पहले की जानी चाहिए।

यह भी देखना आवश्यक है कि दान सुपात्र को दिया जा रहा है या कुपात्र को? कुपात्र की श्रेणी में वह व्यक्ति आएगा, जो आलसी है और दूसरों की आय पर ही निर्भर रहता है, उसे दान देना गलत हो जाएगा। उसका आलस्य दूर कर तथा येन-केन-प्रकारेण उसे रचनात्मक काम में लगा देना दान देने से ज्यादा उत्तम कार्य है, वरना आलसी व्यक्ति समाज के लिए बोझ बना रहेगा। कुपात्र की श्रेणी में नशा आदि करने वाले भी आते हैं। उन्हें चाहे पैसा दिया जाए या कोई वस्तु, उसे बेचकर वे नशीली वस्तु का ही सेवन करेंगे। इसलिए दान देने के पहले दान लेने वाले के बारे में भलीभांति जानकारी कर लेनी चाहिए। धर्मस्थलों के बाहर कई ऐसे भी भिखारी बैठे रहते हैं, जो कामधाम करें, तो ज्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन उनकी आदतें बिगड़ गई हैं और वे सिर्फ भिक्षा से काम चलाते हैं।

राह चलते भिक्षुकों की अपेक्षा गरीब विद्यार्थियों को पठन-पाठन से संबंधित वस्तु देना ज्यादा उपकारी है। प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था, राहगीरों के लिए रैन बसेरा बनवाना भी दान ही है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसी हिम्मत हारे हुए व्यक्ति को आत्मबल का अहसास करा देना तथा आर्थिक तंगी से अपने भविष्य को लेकर परेशान व्यक्ति की परेशानी दूर करना भी उत्तम काम है। इसके अलावा अपनी संपत्ति का एक निश्चित हिसा परोपकार के लिए निकाल देना चाहिए। दान देने के बाद उससे यश प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए तथा किसी को उपेक्षित दृष्टि से भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसा दान निकृष्ट दान की श्रेणी में ही आएगा।

सलिल पांडेय

सुरक्षा मानकों की अनदेखी

अजय कुमार बियानी

इंदौर में हाल में घटित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग से जुड़ी भीषण आग की घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि आधुनिक विकास माडल की गंभीर खामियों को उजागर करने वाली त्रासदी है। देश में पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्युत वाहनों को तेजी से अपनाया जा रहा है। शासन द्वारा प्रोत्साहन योजनाएं, कंपनियों द्वारा नए माडलों का विस्तार और नागरिकों में बढ़ती स्वीकार्यता, ये सभी संकेत हैं कि भविष्य विद्युत आधारित परिवहन का है। किंतु इस परिवर्तन के साथ आवश्यक सुरक्षा संरचना का विकास उतनी ही गंभीरता से हुआ है या नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न है। ई-वाहनों में प्रयुक्त बैटरियां अत्याधुनिक होते हुए भी संवेदनशील होती हैं। चार्जिंग के दौरान अत्यधिक तापमान, तकनीकी त्रुटि अथवा अनुचित उपकरणों के उपयोग से आग लगने की संभावना बनी रहती है। विशेष रूप से जब घरेलू स्तर पर बिना मानक व्यवस्था के चार्जिंग की जाती है, तब जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। विकसित देशों में इस प्रकार की घटनाओं के बाद कठोर दिशा-निर्देश और सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं, जबकि हमारे यहां अभी भी इस दिशा में स्पष्टता और सख्ती का अभाव दिखाई देता है।

अधिकांश भवनों में धुआं पहचानने वाली प्रणाली, आपातकालीन निकास व्यवस्था और अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता नहीं है

यह घटना शहरी ढांचे की एक और कमजोरी को भी सामने लाती है- अग्नि सुरक्षा के प्रति लापरवाही। अधिकांश आवासीय भवनों में न तो धुआं पहचानने वाली प्रणाली है, न आपातकालीन निकास की समुचित व्यवस्था और न ही अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता। जब तक आग नियंत्रण में आती है, तब तक नुकसान अपरिवर्तनीय हो चुका होता है। यह स्थिति बताती है कि भवन निर्माण से लेकर उसके उपयोग तक सुरक्षा मानकों को केवल कागजों में ही सीमित कर दिया गया है। इस त्रासदी के संदर्भ में उत्तरदायित्व का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या वाहन निर्माताओं ने अपने उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त परीक्षण और जागरूकता प्रदान की? क्या चार्जिंग उपकरण मानकों के अनुरूप थे? क्या स्थानीय प्रशासन ने भवनों की अग्नि सुरक्षा की नियमित जांच की? और क्या विद्युत आपूर्ति से जुड़े विभागों ने बढ़ते भार और संभावित जोखिमों का आकलन किया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ही भविष्य की दिशा तय करेंगे।

यदि नीति निर्माण, क्रियान्वयन और जनजागरूकता तीनों स्तरों पर समन्वय का अभाव रहेगा, तो ऐसी दुर्घटनाएं बार-बार दोहराई जा सकती हैं। आवश्यक है कि ई-वाहनों के लिए सुरक्षित चार्जिंग व्यवस्था को अनिवार्य बनाया जाए, भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाए और नागरिकों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

(लेखक इंजीनियर हैं)

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने भारत

संपादकीय 'ऊर्जा का संरक्षण' अत्यंत सामयिक है। अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष से उपजे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के संकट की आहट ने आम जनता और सरकारों को भविष्य के प्रति सचेत कर दिया है। गांवों में मिट्टी के चूल्हों और गोबर के उपलों जैसे पारंपरिक संसाधनों के पुनः प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटकर विदेशी निर्भरता को कम कर सकते हैं। हमें आधुनिकता के साथ-साथ इन पारंपरिक विकल्पों को भी सहेज कर रखना चाहिए, ताकि वैश्विक आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में हमारी रसोई का पहिया न थमे। कनाडा की यूनिवर्सिटी आफ क्युबेक के विज्ञानी मार्क ब्यूरेगार्ड की यह चेतावनी चिंताजनक है कि वर्तमान उपभोग की दर से पेट्रोल-डीजल वर्ष 2070 तक समाप्त हो सकते हैं। यदि खपत की रफ्तार यही रही, तो यह संकट उससे पहले भी आ सकता है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों का आगमन एक सुखद संकेत है, लेकिन हमें सौर ऊर्जा जैसे और अधिक स्थायी विकल्पों की ओर तीव्रता से बढ़ना होगा। भारत एक प्रकृति संपन्न राष्ट्र है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत और बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनाने की क्षमता प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस का विस्तार न केवल कचरा प्रबंधन करेगा, बल्कि एलपीजी पर निर्भरता भी घटाएगा। यदि केंद्र और राज्य सरकारें अक्षय ऊर्जा के प्रति और गंभीरता दिखाएं तो भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन जाएगा। ऊर्जा के पारंपरिक विकल्प कभी भी समाप्त हो सकते हैं, किंतु प्रकृति प्रदत्त अक्षय स्रोत हमारे सुरक्षित भविष्य की गारंटी हैं।

raju09023693142@gmail.com

मेलबाक्स

प्रशासनिक तंत्र से उम्मीद

प्रशासनिक तंत्र के अधिकारियों से उम्मीद रहती है कि वे जनता की सेवा नियम-कानून के अधीन रहकर करेंगे एवं इनसे नियम-कानून के कड़ाई से पालन करवाने की अपेक्षाएं रहती हैं। ऐसी अपेक्षाएं जब धूमिल पड़ती दिखती हैं तब चुनाव के दृष्टिगत चुनाव आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर फेरबदल किए जाते हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से संचालित हो सके। लोकतंत्र में अस्थायी और स्थायी कार्यपालिका के अभिन्न संबंध पर ही सुशासन का सारा दायित्व रहता है। बावजूद प्रशासनिक अधिकारी अस्थायी कार्यपालिका को नियम सम्मत सलाह देने के बजाय उस दल विशेष के कार्यकर्ता की भूमिका निभाते नजर आते हैं। यानी आगाह और कार्यान्वयन की सम्यक भूमिका से वे दूर नजर आते हैं। लिहाजा प्रशासनिक एवं न्यायिक तंत्र में कार्य करने वाले लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जनता के सेवक के बजाय राजनीतिक दलों के सेवक बना डालती है। इसमें किसी दल विशेष पर आरोप उचित नहीं है। ऐसे में उनके राजनीति में उतरने या यूं कहें आने की संभावना पर नियमन जरूरी है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

कमजोर संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस के अनुसार संयुक्त राष्ट्र आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि 1945 के बाद बने उस वैश्विक ढांचे को दर्शाती है जब शक्तियों का संतुलन बिल्कुल अलग था। उस समय विजयी राष्ट्रों को स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकार दिया गया जिसका प्रभाव आज भी निर्णय प्रक्रिया पर हावी है। वर्तमान परिस्थिति में जब बड़े देश अपने-अपने हितों के अनुसार वीटो का उपयोग करते हैं तब कई बार युद्ध और मानवीय संकटों पर प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं हो पाती। यही कारण है कि अनेक वैश्विक मुद्दों पर सुरक्षा परिषद की भूमिका सीमित दिखने लगती है। स्पष्ट है कि बदलती विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रतिनिधिक, प्रभावी बनाने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार अनिवार्य हो गया है, अन्यथा वैश्विक शांति बनाए रखने की उसकी क्षमता कमजोर पड़ती जाएगी। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता अनिवार्य हो गई है।

amritmaruravi@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

अमीर चंद के आइपीओ का प्राइस बैंड तय

नई दिल्ली: बासमती चावल का निर्यात करने वाली कंपनी अमीर चंद जगदीश कुमार (एक्सपोर्ट्स) लिमिटेड ने अपने आइपीओ का प्राइस बैंड 201-212 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इससे कंपनी का वैल्यूएशन 2,200 करोड़ रुपये हो गई है। कंपनी ने कहा कि उसका 440 करोड़ रुपये का पहला आइपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 24 मार्च को खुलेगा और 27 मार्च को बंद होगा। (प्रेट्र)

शायद अब समय आ गया है कि नियामक निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एकीकरण और पूंजी जुटाने के लिए कुछ लचीलापन दिखाने पर विचार करें।
—एम राजेश्वर राव, आरबीआइ के पूर्व डिप्टी गवर्नर

सेंसेक्स	74,207.24	▼ 2,496.89
निफ्टी	23,002.15	▼ 775.65
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹1,53,300	▼ ₹7,000
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹2,38,700	▼ ₹17,800
डालर	₹92.89	बदलाव नहीं
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 114.8	

कच्चे तेल के दाम में उफान से सहमा बाजार, सेंसेक्स करीब 2,500 अंक लुढ़का

बीएसई के बेंचमार्क सूचकांक में जून, 2024 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट, निफ्टी भी 775 अंक गिरकर 23,002 पर बंद हुआ

मुंबई, प्रेट्र: कच्चे तेल के दाम में तेजी और कमजोर वैश्विक रुझान के चलते गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी तीन प्रतिशत से ज्यादा गिरकर लगभग एक साल के निचले स्तर पर बंद हुए। लगातार तीन दिनों की बढ़त के बाद, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 2,496.89 अंक या 3.26 प्रतिशत (जून 2024 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट) गिरकर 74,207.24 पर बंद हुआ। यह स्तर सात अप्रैल, 2025 के बाद नहीं देखा गया था। दिन में यह 2,753.18 अंक गिरकर 73,950.95 पर आ गया था। वहीं एनएसई निफ्टी 775.65 अंक या 3.26 प्रतिशत गिरकर 23,002.15 पर बंद हुआ। पिछले तीन सत्रों में निफ्टी 2.68 प्रतिशत या 626 अंक चढ़ा था, जबकि सेंसेक्स 2.8 प्रतिशत या 2,140 अंक चढ़ा था।

सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इटरनल, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और बजाज फिनसर्व प्रमुख रूप से नुकसान में रहीं। निफ्टी मिडकैप में 3.19 प्रतिशत और निफ्टी स्मालकैप में 2.94 प्रतिशत की गिरावट रही। सेक्टरवाइज देखें तो सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी आटो में सबसे ज्यादा गिरावट रही।

लिवलांग वेल्थ के संस्थापक हरिप्रसाद ने कहा कि भारतीय शेयर बाजारों में एक तेज और बड़े पैमाने पर गिरावट देखने को मिली। निफ्टी-50 ने एक ही सत्र में अपनी हाल की सारी बढ़त गंवा दी। यह बिकवाली कई बड़े आर्थिक झटकों के एक साथ आने के चलते हुई, जिसने जोखिम के नजरिये का काफी हद तक बदल दिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें 111 डालर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है और इससे आपूर्ति में लगातार रुकावटों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

शेयर बाजार की बड़ी गिरावटें

4 जून, 2024 को 4,389 अंक
लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा को बहुमत नहीं मिलना

23 मार्च, 2020 को 3,935 अंक
कोरोना के चलते लाकडाउन एलान

29 अप्रैल, 1992 को 570 अंक
हर्षद मेहता घोटाले का पर्दाफाश

17 मई, 2004 को 11.1%
लोस चुनाव में वाजपेई सरकार हारी

24 अक्टूबर, 2008 को 10.96%
वैश्विक वित्तीय आपदा

- सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरकर बंद हुए
- सभी सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई

गिरावट के प्रमुख कारण

- शेयर बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमत में आया उछाल है।
- अमेरिका के फेडरल बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि देश में महंगाई उम्मीद के मुताबिक नीचे नहीं आ रही है।
- बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट आई। फेडरल रिजर्व के रेट में कटौती नहीं करने और महंगाई बढ़ने के अनुमानों के कारण ऐसा हुआ।
- यूएस बांड यील्ड कई सत्र की गिरावट के बाद चढ़ गया। 10 साल के बांड पर यील्ड 6.3 आधार उछलकर 4.265% पहुंच गई।
- गुरुवार को डेरिवेटिव्स कांट्रैक्ट की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी वाले दिनों में भारी उतारचढ़ाव होता है।
- गुरुवार को विदेशी मुद्रा बाजार बंद था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतों में तेजी से रुपये पर और दबाव बढ़ेगा।

तेल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट

गुरुवार को तेल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर तेजी से नीचे गिरे। विश्लेषकों का मानना है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव इसलिए बढ़ा क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें उनके रिफाइनिंग और मार्केटिंग लाभ को कम करने का खतरा पैदा कर रही हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शेयर 7.01 प्रतिशत गिरकर बीएसई पर 324.80 रुपये पर बंद हुए। दिन के दौरान, यह 7.87 प्रतिशत तक गिर गया और 52 सप्ताह के अपने सबसे निचले स्तर 321.80 रुपये पर पहुंच गया। बीपीसीएल का शेयर 5.83% गिरकर 286 रुपये पर आ गया और इंडियन आयल का शेयर 3.91% गिरकर 142.70 रुपये पर बंद हुआ।

ईरान के हमले के बाद क्रूड की कीमत 114.80 डालर प्रति बैरल

कतर में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस संयंत्र और कुवैत में दो तेल रिफाइनरियों पर ईरान के हमले के बाद वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत 6.75 प्रतिशत चढ़कर 114.8 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गई। ईरान ने गुरुवार को अपने पड़ोसी देशों के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले तेज कर दिए। उसने लाल सागर स्थित सऊदी अरब की एक रिफाइनरी को निशाना बनाया और कतर के एलएनजी संयंत्रों और कुवैत की दो तेल रिफाइनरियों पर भी हमले किए।

निवेशकों की संपत्ति में 12.87 लाख करोड़ की कमी आई

नई दिल्ली, प्रेट्र: गुरुवार को बाजार में आई तेज गिरावट के चलते निवेशकों की संपत्ति में 12.87 लाख करोड़ की कमी आई। 28 फरवरी को पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से निवेशकों को 37 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण एक ही दिन में 12,87,273.89 करोड़ रुपये की भारी गिरावट के साथ 4,26,13,557.95 करोड़ रुपये (4.61 ट्रिलियन डालर) पर आ गया।

पश्चिम एशिया में जंग से अब तक सेंसेक्स 9% टूटा

19 मार्च	74,207
18 मार्च	76,704
17 मार्च	76,070
16 मार्च	75,502
13 मार्च	74,563
12 मार्च	76,034
11 मार्च	76,863
10 मार्च	78,205
09 मार्च	77,566
06 मार्च	78,918
05 मार्च	80,015
04 मार्च	79,116
02 मार्च	80,238
27 फरवरी	81,287

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

एक नजर में

आइसीआइसीआइ बैंक को जीएसटी मांग नोटिस मिला

नई दिल्ली: आइसीआइसीआइ बैंक ने बताया कि कर अधिकारियों ने उस पर जीएसटी के कथित रूप से कम भुगतान के लिए 768.6 करोड़ रुपये का मांग नोटिस जारी किया है। इस आदेश में 3,84,33,53,972 रुपये के जीएसटी की मांग की गई है, साथ ही बैंक द्वारा उन ग्राहकों को दी गई सेवाओं पर लागू होने वाली उतनी ही राशि का जुर्माना और ब्याज की भी मांग की गई है, जो अपने खातों में एक तय न्यूनतम बैलेंस बनाए रखते हैं। बैंक ने यह भी बताया कि वह इस मामले में उचित कदम उठाएगा। (प्रेट्र)

दो प्रतिशत अपने वाहनों की कीमत बढ़ाएगी बीएमडब्ल्यू

नई दिल्ली: बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने गुरुवार को कहा कि वह एक अप्रैल से अपनी गाड़ियों के सभी माडलों की कीमतों में दो प्रतिशत की वृद्धि करने जा रहा है। यह कदम लाजिस्टिक और मटीरियल की बढ़ती लागत के साथ ही रुपये के गिरते मूल्य के असर को कम करने के लिए उठाया गया है। जर्मन लक्जरी कार निर्माता कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह मूल्य बीएमडब्ल्यू और मिनी दोनों तरह की गाड़ियों की पूरी रेंज पर लागू होगी। बता दें कि मर्सिडीज-बेंच इंडिया और आडी इंडिया पहले ही अगले महीने से अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने का एलान कर चुके हैं। (प्रेट्र)

चीन को तेल रहित खल का निर्यात 20 गुना बढ़ा

नई दिल्ली: उद्योग संगठन साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में चीन को भारत का तेल रहित खल अथवा डी-आयल्ड केक निर्यात 20 गुना से ज़्यादा बढ़कर 7.79 लाख टन हो गया है। इसकी वजह है कि प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले भारतीय उत्पाद के सस्ता होने से मांग बढ़ गई। भारत ने अप्रैल, 2025-फरवरी, 2026 के दौरान चीन को 7,79,016 टन डीओसी निर्यात किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 38,240 टन था। (प्रेट्र)

एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती का इस्तीफा

मुंबई, प्रेट्र: देश के दूसरे सबसे बड़े ऋणदाता एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक नैतिक चिंताओं का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह पहली बार है जब एचडीएफसी बैंक के किसी अंशकालिक चेयरमैन ने कार्यकाल के बीच में पद छोड़ा है। इससे बैंक के कामकाज को लेकर सवाल उठे हैं। उनका कार्यकाल चार मई 2027 को समाप्त हो रहा था।

उधर, आरबीआइ ने बैंक के कामकाज को लेकर गुरुवार को बयान जारी किया। केंद्रीय बैंक ने कहा, 'एचडीएफसी बैंक एक घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक है और जिसके पास मजबूत वित्तीय स्थिति, पेशेवर तरीके से संचालित बोर्ड और सक्षम प्रबंधन दल है। हमारे समय-समय पर किए गए आकलन के आधार पर, इसके आचरण या शासन के संबंध में कोई बड़ी चिंता नहीं है। आरबीआइ ने जोर देते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और उसकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। साथ ही बैंक के पास पर्याप्त नकदी भी मौजूद है। आरबीआइ ने बैंक के अनुरोध पर उसके अंशकालिक चेयरमैन के पद को लेकर एक अंतरिम व्यवस्था को मंजूरी दी है। एचडीएफसी बैंक के आवेदन पर आरबीआइ ने बुधवार को केकी मिस्त्री को 19 मार्च, 2026 से तीन महीने की अवधि के लिए अंतरिम अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि आरबीआइ आगे की कार्रवाई को लेकर निदेशक मंडल और प्रबंधन के साथ जुड़ा रहेगा।

- कहा-बैंक का काम करने का तरीका नैतिकता के अनुरूप नहीं
- आरबीआइ ने कहा-चेयरमैन का इस्तीफा देना चिंता की बात नहीं
- वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू बोले-एचडीएफसी बैंक दमदार बुनियाद वाला मजबूत संस्थान

HDFC BANK

गुजरात कैडर के आइएएस अधिकारी रहे हैं अतनु

अतनु चक्रवर्ती

अतनु ने अपने इस्तीफे में कहा, 'पिछले दो वर्ष में बैंक के भीतर कुछ ऐसी घटनाओं और प्रथाओं को मैंने देखा है जो मेरे व्यक्तिगत मूल्यों एवं नैतिकता के अनुरूप नहीं हैं। यही मेरे इस निर्णय का आधार है।' गुजरात कैडर के आइएएस अधिकारी चक्रवर्ती को आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद पांच मई 2021 से चेयरमैन बनाया गया था।

66 हजार करोड़ कम हुआ एचडीएफसी बैंक का एमकैप

एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के इस्तीफे के बाद बैंक का शेयर 5.13 प्रतिशत टूटकर बीएसई पर 799.70 रुपये पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 8.41 प्रतिशत गिरकर 772 रुपये पर पहुंच गया था, जो इसका 52 सप्ताह का सबसे निचला स्तर है। एनएसई पर स्टाक 5.31 प्रतिशत गिरकर 798.20 रुपये पर बंद हुआ। स्टाक में आई गिरावट के बाद कंपनी का मूल्यांकन 65,946.08 करोड़ कम होकर 12,30,896.85 करोड़ रह गया।

कोल इंडिया ने कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने को उठाए कदम

नई दिल्ली, प्रेट्र: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने गुरुवार को कहा कि घरेलू कोयला उत्पादन उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) सभी क्षेत्रों को शुष्क ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है।

देश के कुल कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाली कोल इंडिया ने एहतियाती कदम उठाते हुए चालू माह में 29 ई-नीलामी आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके तहत 2.35 करोड़ टन कोयले की पेशकश की जाएगी। कोयला मंत्रालय ने कहा, 'इन 29 नीलामियों में से 12 मार्च, 2026 से अब तक पांच नीलामी आयोजित की जा चुकी हैं। इनमें 73.1 लाख टन कोयले की पेशकश की गई थी।

वैश्विक बिकवाली से चांदी 17,800 रुपये गिरी, सोना भी 7,000 टूटा

- सोना अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 1,83,000 से 29,700 रुपये सस्ता हुआ, चांदी भी 1,65,800 रुपये घटी

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारी बिकवाली के चलते गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 7,000 रुपये या 4.37 प्रतिशत गिरकर 1,53,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इस पीली धातु की कीमत 29 जनवरी को दर्ज किए गए अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 1,83,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से 29,700 रुपये या 16.23 प्रतिशत गिर चुकी है। वहीं चांदी 17,800 रुपये या लगभग सात प्रतिशत गिरकर 2,38,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो बुधवार को 2,56,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। चांदी अब 29 जनवरी को दर्ज किए गए अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम से 1,65,800 रुपये प्रति किलोग्राम, या 41 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ नीचे आ गई है। विश्लेषकों के मुताबिक, बढ़ती महंगाई की चिंताएं, केंद्रीय बैंकों का सख्त रुख और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की जा रही है।

युद्ध से वैश्विक महंगाई बढ़ने की आशंका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : युद्ध संकट से वैश्विक महंगाई के बढ़ने की आशंका गहराती जा रही है। अमेरिका के फेडरल बैंक से लेकर कई अन्य वित्तीय एजेंसियां अमेरिका समेत दुनियाभर में महंगाई बढ़ने की आशंका जता रही हैं। जाहिर है कि भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। गैस संकट और पेट्रोलियम पदार्थों के सह उत्पाद की कमी से घरेलू स्तर पर भी मैन्यूफैक्चरिंग की लागत बढ़ती जा रही है। लंबे रूट से माल के आने और कंटेनर की कमी से आयात होने वाले कच्चे माल की लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रानिक्स, प्लास्टिक और केमिकल उत्पादों के महंगे होने की पूरी उम्मीद जाहिर की जा रही है। एसी और कार की कीमत पहले ही बढ़ चुकी है।

सीआइआइ के पदाधिकारी और देकी इलेक्ट्रानिक्स के प्रबंध निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रानिक्स से जुड़े आइटम के निर्माण में प्लास्टिक और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़े होने से युद्ध की वजह से ये पहले ही महंगे हो चुके हैं। ईंधन की लागत भी बढ़ रही है। कंटेनर और लाजिस्टिक कीमत बढ़ने एवं डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट से आयात की लागत लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रानिक्स आइटम के निर्माताओं ने बढ़ी हुई लागत का भार उपभोक्ताओं पर डालना शुरू कर दिया है। शर्मा ने बताया कि अगर और 20 दिनों तक युद्ध चलता है तो निश्चित रूप से सप्लाई चेन बाधित हो सकती है।

- इलेक्ट्रानिक्स आइटम से लेकर स्टील, सीमेंट जैसे कई उत्पादों पर होगा इसका असर
- विशेषज्ञ बोले-20 दिन और युद्ध चला तो निश्चित रूप से बाधित होगी सप्लाई चेन

पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ी तो महंगाई को मिलेगी और हवा

पेटकोक और पैकेजिंग की कीमत में बढ़ोतरी को देखते हुए सीमेंट कंपनियां इस महीने ही सीमेंट की कीमत में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। उद्यमियों का कहना है कि बड़ी कंपनियां अपने पास एक से दो माह के कच्चे माल का स्टाक रखती हैं। गत 28 फरवरी को ईरान युद्ध के 20 दिन हो चुके हैं और एक माह से अधिक समय तक युद्ध के जारी रहने पर आयात के लिए कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित होने लगेगी। फोन समेत अन्य इलेक्ट्रानिक्स आइटम के निर्माण से जुड़े कच्चे माल के लिए भारत आयात पर काफी अधिक निर्भर करता है। लैपटाप, टैबलेट जैसे आइटम की आपूर्ति मुख्य रूप से आयात से ही की जाती है। कच्चे तेल की कीमत 120 अरब डालर तक जा चुकी है और युद्ध की स्थिति को देखते हुए हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमत अब तक नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी होने पर महंगाई को और हवा मिलेगी।

निर्यातकों के लिए 500 करोड़ रुपये की रिलीफ स्कीम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ईरान युद्ध की वजह से पश्चिम एशियाई देशों में निर्यात की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार निर्यातकों के लिए 497 करोड़ रुपये की रिलीफ (रेजिलिएंस एंड लाजिस्टिक्स इंटरवेंशन फार एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन) स्कीम लेकर आई है। गुरुवार को वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से घोषित इस स्कीम के तहत निर्यातकों को इंश्योरेंस के खर्च में बड़ी राहत मिलेगी। युद्ध की वजह से निर्यात होने वाले आइटम की इंश्योरेंस लागत काफी बढ़ गई है। एमएसएमई श्रेणी के निर्यातक बढ़ती इंश्योरेंस लागत को देखते हुए निर्यात करने में हिचकिचाने लगे हैं। इसलिए सरकार उनके इंश्योरेंस के लिए 50 लाख रुपये तक की मदद देगी। अगले पांच साल के लिए चल रहे 25,000 करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत निर्यातकों को यह मदद दी जा रही है। तेल के निर्यात और जो जहाज माल लेकर लौट आए हैं, उन्हें रिलीफ स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया है। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि निर्यातकों के लिए अभी बैंकिंग और वित्त से जुड़ी राहत के लिए भी स्कीम लाई जाएगी। दैनिक जागरण ने राहत पैकेज की जानकारी पहले ही दी थी।

वाणिज्य मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, इजरायल और यमन जैसे देशों में होने वाले निर्यात को रिलीफ स्कीम का लाभ मिलेगा। पश्चिम एशियाई देशों में भारत 65 अरब डालर का निर्यात करता है। रिलीफ स्कीम को तीन भाग में बांटा गया है। पहले भाग के तहत 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक होने वाले निर्यात को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस का लाभ दिया जाएगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया (ईसीजीसी) से निर्यात होने वाले आइटम का इंश्योरेंस होता है। लेकिन निर्यात होने वाले वस्तुओं का 100 प्रतिशत कवर नहीं होता है। अमूमन निर्यातक 75 प्रतिशत तक कवर लेते हैं। अभी युद्ध की वजह से इस प्रकार के इंश्योरेंस का प्रीमियम भी काफी बढ़ गया है। इसलिए निर्यातक इससे भी कम का कवरेज ले रहे हैं। रिलीफ स्कीम के तहत इन आइटम को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मिलेगा और बाकी के कवरेज के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान सरकार करेगी। इस मद में 56 करोड़ का आवंटन किया गया है।

- सरकार उठाएगी खाड़ी के देशों में जाने वाले सामान के इंश्योरेंस का खर्च
- एमएसएमई निर्यातकों के लिए विशेष स्कीम, बैंकिंग स्तर पर भी मिलेगी राहत

स्कीम के दूसरे भाग में 95 प्रतिशत इंश्योरेंस का कवरेज मिलेगा

रिलीफ स्कीम के दूसरे भाग के तहत 16 मार्च, 2026 से 15 जून, 2026 के बीच होने वाले निर्यात को 95 प्रतिशत इंश्योरेंस का कवरेज मिलेगा। इस अवधि में निर्यातकों को सरकार की वित्तीय मदद से अपने सामान के 95 प्रतिशत कवरेज लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तीसरे भाग के तहत उन एमएसएमई निर्यातकों को राहत दी जाएगी जिन्होंने 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच निर्यात किया है, लेकिन बढ़ी हुई लागत के कारण इंश्योरेंस नहीं लिया है। इन निर्यातकों के निर्यात आइटम का 50 प्रतिशत तक का इंश्योरेंस कवरेज का प्रीमियम सरकार देगी।

युद्ध की वजह से व्यापार के लिए असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। बहुत सारे एमएसएमई निर्यातकों ने लागत की वजह से इंश्योरेंस नहीं लिया है। निर्यात के प्रभावित होने पर देश में रोजगार पर भी असर पड़ेगा और सरकार इस प्रभाव को कम करना चाहती है।
—राजेश अग्रवाल, वाणिज्य सचिव

राष्ट्रीय फलक

बदले जाएंगे 'सरके चुनर' गाने के बोल

नई दिल्ली, प्रेट्र : 'सरके चुनर' गीत के अश्लील बोलों को लेकर मचे बवाल के बाद इसकी गायिका मंगली ने माफी मांगते हुए कहा है कि किसी का भी उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इंस्टाग्राम पर तेलुगु लोक गायिका ने लिखा कि गाने के बोल बदले जाएंगे और जल्द ही दूसरा संस्करण जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए गाने को सभी मंचों से हटा दिया गया है। अनजाने में हुई इस गलती के लिए मैं आप सभी से दिल से माफी मांगती हूं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हमें इस चूक का अफसोस है। इस गाने का हिंदी संस्करण सप्ताह की शुरुआत में जारी किया गया था। इसके कथित अश्लील बोलों के कारण विवाद हो गया है। यह मामला संसद में भी उठाया गया, जहां सरकार ने बताया कि गाने पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस गाने के डांस वीडियो में संजय दत्त के साथ नजर आने वाली अभिनेत्री नोरा फतेही और गीतकार रकीब आलम ने विवाद से स्वयं को अलग कर लिया है। फतेही ने कहा कि उन्होंने कन्नड़ संस्करण तीन साल पहले रिकार्ड किया था। जब उन्होंने हिंदी संस्करण सुना तो उन्होंने निर्माताओं को इससे अवगत करा दिया था।

- गीतकार रकीब आलम ने कहा, मैंने फिल्म निर्माताओं को इसे लेकर किया था आगाह

मंगली। इंटरनेट मीडिया

बादशाह के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर वापस, जमानत

राज्य ब्यूरो, जागरण, चंडीगढ़: हरियाणा में दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर विवादों में घिरे मशहूर रैपर बादशाह को राहत मिली है। पुलिस ने उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को वापस ले लिया है। साथ ही, बादशाह ने गुरुवार सुबह पंचकूला में पुलिस के समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके रुख को संतोषजनक मानते हुए उन्हें मौके पर ही जमानत प्रदान कर दी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को अवगत कराया गया कि बादशाह अब जांच में शामिल हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपित की जमानत रद करने से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राकांपा नेता व पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपित आकाशदीप करज सिंह को दी गई जमानत में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले महीने हाई कोर्ट का आदेश तर्कसंगत था।

पीठ ने बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन जियाउद्दीन सिद्दीकी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नौ फरवरी के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने सिद्दीकी की पत्नी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन से कहा कि यह एक तर्कसंगत फैसला है, हर किसी को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। इस व्यक्ति का इस अपराध से कोई संबंध नहीं है।

कोर्ट ने लालू-राबड़ी की 1600 से ज्यादा दस्तावेज देने की मांग ठुकराई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े सीबीआइ मामले में आरोपित लालू यादव और राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में उन्होंने उन 1600 पन्नों के दस्तावेज को उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिन पर ईडी ने भरोसा नहीं किया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेज मांगना उल्टी गंगा बहाने जैसा है, जिससे ट्रायल में अनावश्यक देरी होगी। ऐसी मांग से ट्रायल प्रक्रिया पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो सकती है।

अदालत ने अपने 35 पेज के आदेश में कहा कि आरोपितों की यह मांग सुनवाई को टालने और मुकदमे को लंबा खींचने की एक कोशिश प्रतीत होती है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सुनवाई की शर्तें आरोपित तय नहीं कर सकते, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण कोर्ट का होता है। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि आरोपितों को पहले ही ऐसे दस्तावेज के निरीक्षण का अवसर दिया जा चुका है, जिनका उपयोग सीबीआइ ने साक्ष्य के रूप में नहीं किया है। इसलिए अब जिरह से पूर्व सभी तरह के दस्तावेज मांगे जाने की शर्त न्याय प्रक्रिया के खिलाफ है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में अन्य आरोपित लालू प्रसाद के पूर्व निजी सचिव आरके महाजन और पूर्व रेलवे महाप्रबंधक महीप कपूर की ओर से दायर याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं।

सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर स्थित प्राणी उद्यान बचाव एवं पुनर्वास केंद्र वंतारा द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों के आयात में अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली एक और याचिका खारिज कर दी है।

पिछले साल शीर्ष न्यायालय ने इसी तरह की एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था और यह माना था कि कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जबकि पूर्व जस्टिस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली विशेष जांच टीम द्वारा वंतारा को दी गई क्लीन चिट को स्वीकार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने करणार्थम विरामह फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

कल्पमेधा

हमें उस जीवन की परवाह नहीं करनी चाहिए, जिसकी हमने अपने लिए कल्पना की है, ताकि उस जीवन को स्वीकार कर सकें, जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।

– जोसेफ कैम्पबेल

युद्ध के बीच मुश्किल होती जिंदगी

अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के नियमों की परवाह किए बगैर युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। कई देश नाहक ही इसकी चपेट में आ गए हैं। जो देश इस युद्ध में शामिल नहीं हैं, उनके निर्यात और आयात पर असर पड़ रहा है।

सुरेश सेठ

ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी है, वह पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। उसकी भीषणता का अंदाजा मिसाइलों और घातक बमों के इस्तेमाल से लगाया जा सकता है। क्रूरता की हद यह है कि युद्ध नियमों को ताक पर रख कर नागरिक इलाकों में भी बम गिराए जा रहे हैं। विद्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान में लड़कियों के स्कूल पर बमबारी की गई, जिसमें कई छात्राओं की मौत हो गई। अब अस्पतालों पर भी बम गिराए जा रहे हैं। मानवीय मूल्य पीछे छूट रहे हैं। अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के नियमों की परवाह किए बगैर अमानवीय युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। तबाही के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। कई देश नाहक ही इसकी चपेट में आ गए हैं। जो देश इस युद्ध में शामिल नहीं हैं, उनके निर्यात और आयात पर असर पड़ रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था जोखिम में है। ऊर्जा संकट गहराने से नागरिकों का जीवन मुश्किल में है। उनके सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं।

भारत की बात करें, तो यह एक ऐसा देश है जो अपनी जरूरत का कच्चे तेल और गैस का 85 फीसद हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। ईरान सहित मध्यपूर्व के देशों से इसका कम से कम आधा हिस्सा आ रहा था, लेकिन जंग का जो भीषण स्वरूप सामने आ रहा है, उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। होर्मुज जलमार्ग में कंटेनर और जहाज फंस गए। वहां से अधिक आपूर्ति की गुंजाइश कम हो गई है। बेशक इस युद्ध के जारी रहने का कोई कारण किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि शुरू में तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को अपदस्थ करने की बात थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल के साझा सैन्य हमले में उनकी मौत हो गई। ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम से अमेरिका को डर था कि वह परमाणु बम बना सकता है। मगर क्या उसने वास्तव में ऐसा किया? कई दिनों से चल रही जंग में उसने ऐसा कोई आभास नहीं कराया।

अब तक के युद्ध से स्पष्ट है कि ईरान ने संभवतः परमाणु बम अभी नहीं बनाया, क्योंकि जिस तरह से वह चौतरफा लड़ाई लड़ रहा है, अगर उसके पास यह विध्वंसक हथियार होता, तो वह कब का इसे इस्तेमाल कर चुका होता। ऐसे में सवाल उठता है कि इस युद्ध को नाहक जारी रखने का क्या कारण है? सिवाय इसके कि अमेरिका यह चाहता है कि ईरान में सत्ता वेनेजुएला की तरह उसकी मर्जी से चले और वह अपने यूरेनियम भंडार को हाथ भी न लगाए। यह भी पूछा जा रहा है कि ईरान ने चौतरफा लड़ाई क्यों छेड़ दी है। इसका कारण यह है कि वह इन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों को देखना नहीं चाहता। इसलिए उन पर हमले कर रहा है। अभी उसने अमेरिका के समर्थक देशों से कहा भी है कि अगर वे हमलावर नहीं होते, तो वह उन पर बमबारी नहीं करता। मगर लगता है ये सभी जुबानी बातें हैं और युद्ध खत्म करने के लिए वास्तव में गंभीर प्रयास करने होंगे। इसे ईमानदारी से समझने की जरूरत है।

तीसरी दुनिया के विकासशील देश यह समझ रहे थे कि अपनी आर्थिकी को आयात आधारित से निर्यात आधारित बना लेंगे। तेजी से

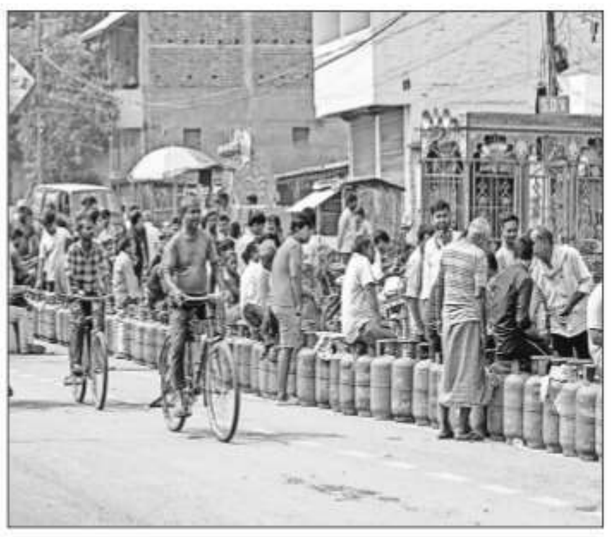

विकास करेंगे। दावा किया गया है कि वर्ष 2047 में अपनी आजादी का शतकीय महोत्सव मनाते समय भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा और हो सकता है अपनी विकास दर से आगे बढ़ते हुए ताकतवर देशों को भी पछाड़ दे, लेकिन यह युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। भारत के निवेश और उत्पादन को गतिमान रखने के लिए ऊर्जा आपूर्ति की बहुत जरूरत है। इसके साथ ही आयात से कहीं अधिक निर्यात होना चाहिए, ताकि भारतीय मुद्रा का न तो विनिमय मूल्य घटे और न ही उसे अपने उद्योग चलाने के लिए समृद्ध देशों के आगे आयात के लिए झुकना पड़े। यह तस्वीर कब बदलेगी, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता।

> **अभी तक भारत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों की अपेक्षित उछाल को नियंत्रित कर रखा है, लेकिन कितने दिन तक रख पाएगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका द्वारा रूस और अन्य बाहरी स्रोतों से एक महीने के लिए कच्चे तेल की खरीद की इजाजत मिलने के बाद भारत कुछ समय के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बेलगाम होने से रोक सकता है। मगर अभी एकदम जो असर सामने नजर आया है, वह है रसोई गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमत। आपूर्ति कम होने के कारण इनकी कीमतें बढ़ने का अर्थ है कि लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। दूसरी ओर वाणिज्यिक गैस का इस्तेमाल कर खाने-पीने की चीजें बनाने वाले अपने दाम बढ़ा देंगे।**

कच्चे तेल की कीमत जो युद्ध शुरू होने के समय 70 डालर प्रति बैरल थी, वह अब उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर कच्चे तेल की कीमत में दस डालर प्रति बैरल वृद्धि होती है, तो महंगाई का आधार अंक बढ़ जाता है। अभी तक भारत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों की अपेक्षित उछाल को नियंत्रित कर रखा है, लेकिन कितने दिन तक रख पाएगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका द्वारा रूस और अन्य बाहरी स्रोतों से एक महीने के लिए कच्चे तेल की खरीद की इजाजत मिलने के बाद भारत कुछ समय के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बेलगाम होने से रोक सकता है। मगर अभी एकदम जो असर सामने नजर आया है, वह है रसोई गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमत। आपूर्ति कम होने के कारण इनकी कीमतें बढ़ने का अर्थ है कि लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। दूसरी ओर वाणिज्यिक गैस का इस्तेमाल कर खाने-पीने की चीजें बनाने वाले अपने दाम बढ़ा देंगे।

अगर स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो देश में रसोई गैस का संकट जल्दी दूर नहीं होगा। हालांकि भारत ने कच्चे तेल की कमी न होने देने के लिए अमेरिका, अफ्रीका और रूस से कच्चे तेल की खरीद शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कच्चे तेल की आपूर्ति फंस जाने के कारण भारतीय तेलशोधक कारखानों को अपनी इकाइयां बंद करनी पड़ रही थीं। अब कोशिश की जा रही है कि दूसरे रास्ते से और अन्य देशों से कच्चे तेल के आयात की हिस्सेदारी बढ़ा कर सत्तर फीसद कर दी जाए। इसके अलावा, रूस ने भी कह दिया है कि भारत जितना चाहे कच्चा तेल उससे खरीद ले। वैकल्पिक स्रोतों से कच्चा तेल आयात करने के फैसले के बाद देश की रिफाइनरियों को अपनी बंद इकाइयां शुरू करने के लिए कह दिया गया है।

यह निराशाजनक ही है कि गैस और तेल संकट के बीच जमाखोरी और मुनाफाखोरी शुरू हो गई। सरकार से लेकर तेल कंपनियां तक कह रही हैं कि अफवाहों से बचें। देश के पास तेल भंडारों की कमी नहीं। मगर आम आदमी इस बात से परेशान है कि कितने दिन इन कालाबाजारी की मनमानी सहे। सरकार के दावे का कितना भरोसा करे, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि तेल खरीद अन्य देशों से ही होगी। और कोई रास्ता भी नहीं दिखता। इसलिए अब कच्चे तेल के सौदे का आकार बदलेगा। दिक्कत यह है कि गैस की घटती आपूर्ति का क्या समाधान निकाला जाए, क्योंकि इसके सिलेंडरों के दाम बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ेंगी। होटल व्यवसाय पर भी असर पड़ेगा।

युद्ध के कारण पश्चिमी एशिया को निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पाद, बासमती चावल, फल-सब्जियां, डेयरी उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ फंस गए हैं। ये जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। इनके खराब होने का डर बेचने वालों को भी रहता है। बेशक युद्ध में भारत की प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं है, लेकिन मांग और कीमतों के बाजार में मार पड़नी शुरू हो गई है। फिलहाल समाधान यही है कि भारत अन्य प्रभावशाली देशों के साथ मिल कर गतिरोध दूर करने में भूमिका निभाएं। युद्धरत देशों से निरर्थक लड़ाई बंद करने के लिए आग्रह करे।

गहराता संकट

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चिंता गहरा रही है कि अगर इसका स्वरूप और बिगड़ता गया, तो आने वाले दिनों में संकट का दायरा ज्यादा व्यापक और गंभीर हो सकता है। सच यह है कि इजराइल और अमेरिका के ईरान पर साझा हमले के बाद अब युद्ध ने जो रुख अख्तियार कर लिया है, उसमें शांति की उम्मीद फिलहाल धुंधली लग रही है। हमले के क्रम में जिस तरह स्कूली बच्चों और आम लोगों तक की फिक्र नहीं की गई, उसे लेकर पहले ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के कई सवाल उठे हैं। अब हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हमलों का निशाना अब दोनों पक्षों के तेल और गैस के वे ठिकाने बन रहे हैं, जिसका वैश्विक स्तर पर गंभीर असर पड़ेगा। खासतौर पर युद्ध के आगे बढ़ने के साथ-साथ खाड़ी के कई देशों में हालात बेहद जटिल होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि इजराइल ने बुधवार को ईरान में स्थित दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस सुविधा केंद्र पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने गुरुवार को कतर के रास लाफान के ठिकाने को निशाना बनाया, जो वहां मुख्य तरल प्राकृतिक गैस को तैयार करने वाला मुख्य केंद्र है।

ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच युद्ध की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति पहले ही कई स्तरों पर बाधित है और इसका स्वाभाविक असर इसकी कीमतों पर पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों के भीतर कच्चे तेल के दाम में तेज बढ़ोतरी और वैश्विक स्तर पर कमजोरी के रुख से शेयर बाजार में गुरुवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एक ओर, बीएसई सूचकांक में करीब 2500 अंक की बड़ी गिरावट हुई, वहीं एनएसई निफ्टी 775 अंक लुढ़क गया। जून, 2024 के बाद इसे सूचकांक में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट बताया गया है। इस तरह की स्थिति को कई बार अन्य कारकों से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इस बार वैश्विक स्तर पर तस्वीर लगभग साफ है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अब ऊर्जा के बुनियादी ढांचों या तेल एवं गैस संयंत्रों पर हमलों में तेजी के बाद कच्चे तेल के दाम में काफी उछाल आया है। इसका एक स्वाभाविक असर निवेशकों की धारणा पर पड़ा है, जिनके भीतर मौजूदा उथल-पुथल को लेकर एक तरह का असुरक्षाबोध पैदा हुआ है।

दरअसल, जब से ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को रोका है, उसके बाद दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति भी बाधित हुई है। भारत जैसे कई देश इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और तेल तथा गैस के लिए वैकल्पिक स्रोतों की ओर देख रहे हैं। इस क्रम में भारत ने रूस से तेल खरीद बढ़ाई है। मगर अब पश्चिम एशिया के युद्ध में शामिल दोनों पक्षों की ओर से जिस तरह प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाले केंद्रों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है, उससे संकट और ज्यादा गहराने की आशंका खड़ी हो रही है। जैसे-जैसे हमलों का स्वरूप जटिल होता जा रहा है, तेल और गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। खासतौर पर कतर के रास लाफान पर हमले के बाद भारत को होने वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। जाहिर है, भारत को अब प्राकृतिक गैस की जरूरत के लिए आस्ट्रेलिया और रूस जैसे अन्य देशों की ओर देखना पड़ सकता है। मगर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अब प्राकृतिक गैस के रणनीतिक भंडारण के विकल्प को ठोस आकार देना होगा।

शुल्क की सीमा

सुरक्षित और जल्दी गंतव्य तक पहुंचने के लिए अब लोग हवाई यात्रा को प्राथमिकता देते हैं। इससे भारत में घरेलू हवाई यात्रा तेजी से बढ़ी है। मगर विमानन कंपनियां अपनी आय बढ़ाने के लिए जिस तरह से अलग-अलग सुविधाओं के नाम पर शुल्क ले रही हैं, उससे यात्रियों की जेब पर नाहक ही बोझ बढ़ा है। दो मत नहीं कि विमान ईंधन की कीमतों में अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव के कारण विमानन कंपनियों का खर्च बढ़ा है, लेकिन यात्रियों से कुछ सुविधाओं के एवज में मनमाने तरीके से और लगातार शुल्क लिए जाने को उचित नहीं कहा जा सकता। इसीलिए सरकार ने विमानन कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर घरेलू उड़ान में साठ फीसद सीटों पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। गौरतलब है कि इस संबंध में यात्रियों ने कई बार शिकायतें कीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा। कायदे से विमान किराए में किसी भी तरह की वृद्धि या कोई भी शुल्क लगाने पर स्थायी नियमन होना चाहिए। टिकटों की बिक्री के दौरान शुरू में कम किराया रख कर यात्रियों को आकर्षित करने और फिर टिकटों के दाम बढ़ाते जाने पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है।

कई बार ऐसा देखा गया है कि संकट के समय या त्योहारों के दौरान विमान किराए मनमाने तरीके से बढ़ा दिए जाते हैं। इस पर डीजीसीए के दखल न देने से विमानन कंपनियां प्रायः इसे अपना अधिकार मान लेती हैं। जबकि हवाई सेवाओं में किसी भी तरह का शुल्क यात्रियों को ध्यान में रख कर ही लिया जाना चाहिए। विचित्र बात है कि एक ही पीएनआर पर परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठाने के लिए भी अतिरिक्त शुल्क लिया जाता रहा। यात्रियों के लिए यह राहत की बात है कि सरकार ने अब इस पर भी रोक लगा दी है। सीट चुनने जैसी सुविधा के लिए अलग से शुल्क लिया जा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या नागर विमानन महानिदेशालय को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। नए निर्देश से बहुत संभव है कि विमानन कंपनियों की कमाई पर असर पड़े, लेकिन यह यात्रियों के हित में उठाया गया जरूरी कदम है।

अदृश्य जंजीरें

कीर्ति अनामिका

शादी समारोहों का आयोजन कई बार कुछ सामाजिक समस्याओं की जड़ों और उसकी समाजशास्त्रीय व्याख्याओं को समझने का मौका भी होता है। खासतौर पर नई बहू के बारे में बात करते हुए अगर उससे घर-परिवार को संभालने की अपेक्षा की जाती है, तो यह कोई हैरान होने वाली बात नहीं होती। मगर कोई पढ़ी-लिखी महिला यह कहे कि शुरू से ही नई बहू से घर के सारे काम कराना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि उसे कौन-कौन-सा हुनर आता है, तो थोड़ी हैरानी जरूर होती है। यही नहीं, कहा यहां तक जाता है कि अगर नई बहू से शुरू से घर के काम नहीं कराया जाएगा, तो उसका 'मन बढ़' जाएगा और आगे वह घर के काम से कन्नी काटने लगेगी। सवाल है कि इस तरह अपेक्षाओं और बातों का स्रोत क्या होता है! खासतौर पर जिस महिला को अपनी ससुराल में घर के सारे काम करने पड़ते हैं, खाना बनाने से लेकर पूरे परिवार के कपड़े धोने तक, उसे घर में बाकी लोगों को आराम देने के लिए नई बहू से ही काम कराने की सामाजिक रिवायत पर फिर से सोचना चाहिए। जिन बहुओं को शुरू में ही घर के काम में झोंक दिया जाता है, उनके बारे में अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि बीमार होने पर उन्हें ठीक से इलाज नहीं मिल पाया, सास के ताने सुनने पड़े, घर में कई तरह की पाबंदी थी। मगर अफसोस कि कई बार ऐसी महिलाएं भी अपनी स्थिति को लेकर सहज रहती हैं और नई बहुओं से वैसा ही करने की अपेक्षा करती हैं।

यह बस उम्मीद ही की जा सकती है कि खुद कई स्तरों पर वंचना झेलने वाली महिला अपने घर में आने वाली नई बहू को सभी तरह से आजादी और सम्मान देगी। मगर व्यवस्था से पीड़ित किसी महिला का वंचना की परंपरा को बनाए रखने की वकालत तकलीफदेह होती है। असल में यह उदाहरण भारतीय परिवार व्यवस्था का नमूना है। सवाल है कि जिस व्यवस्था से कोई पीड़ित है, वह उसका हिमायती कैसे हो सकता है?

इटली के दार्शनिक एंतोनियो ग्राम्शी की 'हेजेमनी', यानी आधिपत्यवाद का सिद्धांत याद किया जा सकता है। उसमें उनका कहना था कि वर्चस्ववादी तबका सांस्कृतिक और वैचारिक औजार के जरिये अपना वर्चस्व बनाए रखता है। स्त्रियों के संदर्भ में आधिपत्यवाद का अर्थ उस सामाजिक व्यवस्था से है, जिसमें पुरुषों या पितृसत्तात्मक शक्ति का प्रभुत्व समाज के लगभग हर क्षेत्र में स्थापित होता है और धीरे-धीरे इसे सामान्य और स्वाभाविक मान लिया जाता है। यह प्रभुत्व केवल बल या कानून के माध्यम से नहीं चलता, बल्कि समाज की सोच, परंपराओं, संस्कृति, भाषा और मान्यताओं के माध्यम से भी कायम रहता है। इस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिकाएं पहले से तय कर दी जाती हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मुख्य रूप से घर, परिवार और देखभाल से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाएं, जबकि सार्वजनिक जीवन, राजनीति, आर्थिक निर्णय और सत्ता के क्षेत्र पुरुषों के अधिकार क्षेत्र माने जाते हैं। समय के साथ ये धारणाएं इतनी गहराई से समाज में रच-बस जाती हैं कि लोग इन्हें स्वाभाविक मानने लगते हैं।

आधिपत्यवाद की खास बात यह है कि इसमें नियंत्रण हमेशा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। महिलाएं सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के प्रभाव में उन्हीं दकियानूस नियमों को स्वीकार कर लेती हैं, जो उन्हें संकुचित या संकीर्ण बनाते हैं। इस तरह यह प्रभुत्व सामाजिक सहमति और वैचारिक प्रभाव के जरिए चलता रहता है।

मीडिया, साहित्य, शिक्षा और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराएं भी इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे स्त्री और पुरुष की निश्चित छवियां और भूमिकाएं प्रस्तुत करती हैं। इसलिए स्त्रियों के संदर्भ में आधिपत्यवाद को समझने का मतलब है यह देखना कि किस प्रकार समाज की संरचनाएं, विचार और परंपराएं मिलकर पितृसत्ता को बनाए रखती हैं और महिलाओं की स्वतंत्रता, अवसरों और निर्णय-क्षमता को सीमित करती हैं। सूक्ष्म तरीके से देखें तो ये सब बातें यहीं तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि वर्चस्ववादी ताकतें अपनी व्यवस्था को आगे बनाए रखने के लिए पीड़िता को ही अपना हथियार बनाती हैं। इसमें पीड़ित महिला इस सोच से बाहर निकलने के बजाय यथास्थिति की वकालत करती है, जबकि मानवीय बराबरी और सम्मान पाने के लिए उसे उठ खड़ा होने की जरूरत होती है।

उपन्यासकार, चित्रकार और कवि जान बर्जर अपनी किताब 'वे आफ सीइंग' में महिलाओं की छवि और उनके सामाजिक स्थान को लेकर कहते हैं कि कला और आधुनिक मीडिया में महिलाओं को अक्सर ऐसे दिखाया गया है कि वे देखे जाने की वस्तु बन गई हैं, जबकि पुरुषों को देखने वाले और निर्णय लेने वाले के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनके अनुसार, समाज में पुरुष और स्त्री की भूमिकाएं अलग तरह से बनाई जाती हैं। पुरुष को सक्रिय, नियंत्रक और देखने वाला माना जाता है, जबकि स्त्री को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वह स्वयं को लगातार इस नजर से देखती है कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं। उसे दूसरों के सामने सुंदर दिखना है, जिसकी परिभाषा देखने वाले ने तय की है।

दरअसल, समाज, कला और मीडिया में स्त्री की छवि इस तरह बनाई जाती है कि वह लगातार खुद को दूसरों की निगाह से देखने लगती है। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि पुरुष, महिला के श्रम का उपभोक्ता है और महिला के मानसिक ढांचे को ऐसे तैयार किया गया है कि वह खुद को पुरुष के नजरिए से ढाल ले। वास्तव में पारंपरिक सांचे में रची-बसी और सोचती एक आम स्त्री यही करती है। उसकी अपनी खुद की नजर नहीं होती, बल्कि खुद को देखने के लिए उसे पितृसत्ता की नजर की जरूरत लगती है!

दुनिया मेरे आगे

> **समाज, कला और मीडिया में स्त्री की छवि इस तरह बनाई जाती है कि वह लगातार खुद को दूसरों की निगाह से देखने लगती है। महिला के मानसिक ढांचे को ऐसे तैयार किया गया है कि वह खुद को पुरुष के नजरिए से ढाल ले। वास्तव में पारंपरिक सांचे में रची-बसी और सोचती एक आम स्त्री यही करती है।**

असहमति की जगह

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटा लिया गया। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण है। वांगचुक लंबे समय से लद्दाख में पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय अधिकारों और क्षेत्र को संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग उठाते रहे हैं। इस मुद्दे पर हुए आंदोलन के दौरान उन पर कठोर कानून के तहत कार्रवाई की गई थी। लगभग छह महीने के बाद केंद्र सरकार ने यह कानून हटाने का फैसला किया, जिससे उनकी रिहाई संभव हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति को स्थान देना उसकी मूल भावना का हिस्सा है। विरोध की आवाज को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में देखना लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है। कठोर कानूनों का इस्तेमाल तभी होना चाहिए, जब वास्तव में देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो। वांगचुक प्रकरण यह संकेत देता है कि संवाद और सहमति का रास्ता हमेशा टकराव से बेहतर होता है। लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि वह अलग-अलग विचारों को जगह देता है और संवाद से समाधान खोजता है। असहमति के स्वर ही किसी भी मजबूत लोकतंत्र की असली कसौटी हैं।

– सावित्री शाह, सिंगरौली, मप्र

मुनाफे की खातिर

मध्य-पूर्व एशिया में जारी युद्ध के कारण तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर आशंकाएं स्वाभाविक हैं। मगर देश के अनेक राज्यों में लगभग सभी वस्तुओं के दामों में वृद्धि होना केवल वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर मुनाफाखोरी और अवसरवादिता भी है। ऐसे समय में राज्य सरकारों और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे बाजार पर कड़ी निगरानी रखें और अनावश्यक मूल्य वृद्धि पर तत्काल अंकुश लगाएं। आवश्यक वस्तु अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के बिना आम जनता को राहत मिलना संभव नहीं है। वहीं, केंद्र सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाल ही में जीएसटी में दी गई छूट का वास्तविक लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे। अक्सर देखा गया है कि कर में राहत का फायदा व्यापारिक स्तर पर ही सीमित रह जाता है।

– खुमानसिंह चुंडावत, मंदसौर

चुनौतियों का दायरा

विकसित भारत का सपना तभी सच हो सकता है जब शासन व्यवस्था अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाए। केंद्र सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई बार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों की लापरवाही सामने आती है। जब तक नीतियों को सख्ती और ईमानदारी से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक केवल घोषणाओं से देश विकसित नहीं बन सकता। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति बेहद गंभीर है। हर दिन लगभग 480 लोगों की जान सड़क हादसों में चली जाती है। बीते पांच वर्षों में 7.7 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या युवाओं की है। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हजारों परिवारों के उजड़ने की कहानी है। सरकार को चाहिए कि वह सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दे और हादसों को रोकने के लिए स्वतः सक्रिय होकर ठोस कदम उठाए।

– अंजना साव, जम्मू

ताक पर नियम

आज मध्य-पूर्व से लेकर मध्य-एशिया तक धधकती युद्ध की आग ने पूरी मानवता को जोखिम में डाल दिया है। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और काबुल के अस्पताल पर हुए हवाई हमले ने एक बार फिर यह कड़वा सच उजागर किया है कि युद्ध के मैदान में नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय नियम केवल किताबों तक सीमित रह गए हैं। युद्ध के दौरान अस्पताल, स्कूल और रिहाइशी इलाकों को निशाना बनाना एक युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। बावजूद इसके, चाहे वह गाजा हो, यूक्रेन या अब काबुल हर जगह युद्ध नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। काबुल में अस्पताल पर हमले में चार सौ लोगों की जान जाना मानवीय संवेदनाओं की हत्या है। यह शर्मनाक है कि रमजान जैसे पवित्र महीने में भी हिंसा का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया मूक दर्शक बनी हुई है।

– प्रसिद्ध यादव, फुलवारी, पटना

असम : भाजपा ने 88 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की

जलुकबारी सीट से लड़ेंगे हिमंत बिस्व सरमा, प्रद्युत बोरदोलोई को भी टिकट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 मार्च।

असम विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को भाजपा ने 88 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। इस सूची में जलुकबारी सीट से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा का नाम भी शामिल है। शर्मा लगातार छठी बार अपनी सीट बरकरार रखने के प्रयास में जलुकबारी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं, कांग्रेस पार्टी से आने वाले प्रद्युत बोरदोलोई इस सूची में सबसे बड़ा नाम है। उन्हें पार्टी ने कांग्रेस से आने के बाद इनाम दिया है। हिमंत बिस्व सरमा पहले ही इस मामले में दावा कर चुके थे कि पार्टी इस चुनाव के लिए एक ही बार में उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी।

पार्टी ने प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। यह काफी अहम सीट है और बोरदोलोई बुधवार को कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी की ओर से जारी सूची में कई पुराने विधायकों को मौका दिया गया है और इसमें युवा, महिला और आदिवासी इलाकों के उम्मीदवारों को भी जगह दी गई है। कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं में शशि कांता दास को राहा (सुरक्षित) सीट से मैदान में उतारा गया है, जबकि कमलाख्या पुरकायस्थ को करीमगंज (उत्तर) से हटाकर कटिगोरा सीट से टिकट दिया गया है। अगप के पूर्व विधायक भूपेन राय जो भाजपा में शामिल हो गए थे, वे अभयपुरी से लड़ेंगे। कैबिनेट मंत्री अजंता नियोग अपनी वर्तमान सीट गोलाघाट से, शिक्षा मंत्री रनोज पेगु वर्तमान सीट धेमाजी (सुरक्षित) से लड़ेंगे।

कांग्रेस ने 20 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की

असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की है। इस सूची में 22 उम्मीदवारों के नाम हैं। जिसमें कोकराझार से माणिक चौ ब्रह्मा, बाहोखुंगरी से सपाली मराक, परबतझोरा से अशरफुल इस्लाम शेख, धुबरी से बेबी बेगम, जलेश्वर से आफताब उद्दीन मोल्लाह, अभयापुरी से प्रदीप सरकार, सिदली चिरांग से मातिलाल, चेंगा से अब्दुल रहीम अहमद, पकाबेटबारी से जाकि हुसैन सिकदर, बकसा से जगदीश मदारी, तामुलपुर से रफ दैमारी, उदलगुड़ी से सोरेन दैमारी, लहरिघाट से आसिफ मोहम्मद नजर, नागांव- बताद्राबा से दुर्लव चामुआ, नादुर से सुनील छेत्री, रोंगोनाडी से जोयंतो खौंड, लखीमपुर से घाना बुरागोहेन, ढाकुआखाना से आनंदा नारण, माकुम से सिबानाथ चेतिया, खुमटाई से रोजेलिना तिर्के, हावड़ा घाट से संजीब टेरोन व आल्गापुर कतनी चेर्रा से जुबैर अनम मजूमदार शामिल है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे को भेजा पत्र

कांग्रेस नेता प्रतीक बोरदोलोई ने लौटाया टिकट, चुनाव लड़ने से किया इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 मार्च।

असम से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतीक बोरदोलोई ने पार्टी को अपना टिकट लौटा दिया है और चुनाव लड़ने से इनकार किया है। इस मामले में प्रतीक की ओर से एक पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेजा गया है। हालांकि इस पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि वे आगे भी कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। मालूम हो कि बोरदोलोई के पिता बुधवार को अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।

इस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में बोरदोलोई ने कहा कि उनके पिता के भाजपा में जाने के बाद क्षेत्र के मतदाताओं में असमंजस की स्थिति बन सकती है। इसलिए वे इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मालूम है कि प्रतीक के पिता को भाजपा की ओर से दिसपुर सीट से टिकट दिया गया है और इनका नाम पार्टी की पहली ही सूची में शामिल है।

प्रतीक ने अपने पत्र में कहा है कि लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहे। इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है।
मालूम हो कि प्रतीक के पिता को भाजपा की ओर से दिसपुर सीट से टिकट दिया गया है और इनका नाम पार्टी की पहली ही सूची में शामिल है।

इस सूची में भाजपा ने कुल 88 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। प्रतीक ने अपने पत्र में कहा है कि लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहे। इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है।

मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के लिए यह स्थिति पहली बार नहीं है। इसी प्रकार भूपेन बोराह ने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। अब ऐसा ही बोरदोलोई की आरे से किया गया है, जो कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है।

पश्चिम बंगाल : भाजपा ने पूर्व आइपीएस व फिल्मी कलाकारों पर लगाया दांव

नई दिल्ली, 19 मार्च (ब्यूरो)।

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व आइपीएम, तृणमूल कांग्रेस और फिल्मी पर्दे के चेहरों को भरतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतारा है। इन नेताओं के नामों वाली दूसरी सूची गुरुवार को पार्टी ने जारी की। इस सूची में जिन नामी चेहरों को शामिल किया गया है, उन नामों में फिल्म कलाकार रूपा गांगुली, निशीष प्रमाणिक और प्रियंका तिबरेवाल समेत 111 नाम शामिल हैं। इसी प्रकार पूर्व आइपीएस अधिकारी राजेश कुमार, पूर्व तृणमूल नेता तापस राय को भी इस सूची में शामिल किया गया है।

पार्टी ने रेखा पात्रा को हिंगलगंज से और रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के भाई दिब्येंदु अधिकारी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। सूची के अनुसार, सबिता बर्मन इटाहार से, दिलीप साहा नबग्राम से, मिताली मल खरग्राम से और गार्गी दास घोष कंडी से चुनाव लड़ेंगी। अनामिका घोष भरतपुर से, स्वपन मजूमदार बोंगांव दक्षिण से, अरूप चौधरी कमरहटी से, सनत सरदार संदेशखलि से और मल्लिका पाइक मंदिरबाजार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह, भाजपा ने प्रियंका टिबरवाल को एंटाली सीट से और सुमना सरकार को बालागढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया है।

भाजपा ने इससे पहले 144 सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। अब तक पार्टी कुल 255 उम्मीदवार तय कर चुकी है और 39 सीट पर अभी निर्णय होना बाकि है। यहां पर आयोग दो चरण में मतदान करा रहा है।

केरल के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भाजपा ने जारी की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 मार्च।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची गुरुवार को जारी की, जिसमें अरनमुला सीट से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुम्मनम राजशेखरन को चुनावी मैदान में उतारा गया है।

अरनमुला सीट से पूर्व राज्यपाल कुम्मनम राजशेखरन मैदान में।

भाजपा ने नट्टिला सीट से सीसी मुकंदन को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार, तनूर सीट से दीपक पुझक्कल और कासरगोड से अश्विनी एमएल चुनाव लड़ेंगे। वहीं मंजरी सीट से पथमाश्री एम और कोंगड सीट से रेनू सुरेश चुनाव लड़ेंगी। भाजपा ने इससे पहले अपनी पहली सूची में 47 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे।

चार राज्यों में उप चुनाव के लिए भाजपा ने घोषित किए उम्मीदवार

नई दिल्ली, 19 मार्च (ब्यूरो)। भाजपा ने चार राज्य गोवा, कर्नाटक, नगालैंड और त्रिपुरा में होने वाले पांच विधानसभा सीटों के लिए उप चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने गोवा की पोंडा सीट से रितेश रवि नाइक, नगालैंड की कोरिडांग सीट से दाओचिर आई इम्चेन और त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से जे चक्रवर्ती को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार वीरभद्रय्या चरंतिमठ बागलकोट सीट से चुनाव लड़ेंगे और श्रीनिवास टी दासकारियप्पा कर्नाटक की दावणगेरे दक्षिण सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इनमें से अधिकतर सीटें सदस्यों के मरने के बाद खाली हुई थी। आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक गोआ, कर्नाटक, नागालैंड व त्रिपुरा की सीट पर नौ अप्रैल और गुजरात व महाराष्ट्र की सीट पर 23 अप्रैल को मतदान कराने जा रहा है। इन चुनावों का परिणाम चार मई को घोषित होगा।

पिनराई विजयन ने धर्मदोम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया

इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को यहां धर्मदोम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विजयन ने पूर्वाह्न करीब 11 बजे थलस्सेरी उप रजिस्ट्रार कार्यालय में अपने नामांकन पत्र जमा किए जिन्हें कन्नूर के रजिस्ट्रार एबी सत्यन ने प्राप्त किया। इस मौके पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के अनुभवी नेता विजयन के साथ पार्टी के जिला सचिव केके रागेश, वरिष्ठ नेता ई पी जयराजन, विधानसभाध्यक्ष एएन शमशीर और उनके राजनीतिक सचिव पी सासी भी थे। धर्मदोम विधानसभा सीट पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने वीपी अब्दुल रशीद को मैदान में उतारा है।

एडीआर की रपट में 31 लोग अरबपति

राज्यसभा के 73 सदस्यों ने आपराधिक मामलों की घोषणा की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 मार्च।

चुनाव सुधारों से संबंधित गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) की एक रपट के अनुसार राज्यसभा के लगभग 32 फीसद मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि इनमें से 14 फीसद अरबपति हैं। यह रपट राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 229 के हलफनामों पर आधारित है। फिलहाल झारखंड की एक सीट खाली है, जबकि तीन सांसदों के हलफनामे उपलब्ध नहीं थे। इस विश्लेषण में हाल में निर्वाचित 37 सदस्य भी शामिल हैं।

यह रपट राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 229 के हलफनामों पर आधारित है। फिलहाल झारखंड की एक सीट खाली है, जबकि तीन सांसदों के हलफनामे उपलब्ध नहीं थे।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के तीन-तीन सांसदों ने भी आपराधिक मामलों का खुलासा किया है। एडीआर की ओर से जारी इस रपट में 31 सांसदों (14 फीसद) की कुल संपत्ति अरबों में है। प्रमुख पार्टियों में, भाजपा के छह सांसदों, कांग्रेस के पांच सांसदों, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चार सांसदों, आम आदमी पार्टी और बीआरएस के दो-दो सांसदों और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तीन सांसदों ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। राज्यसभा में सदस्य की औसत संपत्ति 120.69 करोड़ रुपए आंकी गई है। भाजपा के मामले में प्रति सांसद औसत संपत्ति 28.29 करोड़ रुपए है जबकि कांग्रेस के लिए 128.61 करोड़ रुपए, तृणमूल के लिए 17.70 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी के लिए 574.09 करोड़ रुपए है। अन्य दलों में वाईएसआरसीपी (522.63 करोड़ रुपए), समाजवादी पार्टी (399.71 करोड़ रुपए), बीजू जनता दल (105.63 करोड़ रुपए) और द्रमुक (11.90 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

उत्सव

हिंदू नव वर्ष: मुंबई के गिरगांव में गुड़ी पड़वा उत्सव के दौरान गुरुवार को पारंपरिक पोशाक में भाग लेते कलाकार।

केरल के 70 फीसद विधायकों पर आपराधिक मामले, आधे से अधिक विधायक करोड़पति

नई दिल्ली, 19 मार्च (ब्यूरो)।

केरल के करीब 70 फीसद मौजूदा विधायकों ने उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने की जानकारी दी है तथा आधे से अधिक विधायक करोड़पति हैं। 'एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स' (एडीआर) की एक रपट में यह जानकारी दी गई। एडीआर और 'केरल इलेक्शन वाच' द्वारा किए गए इस विश्लेषण में 132 मौजूदा विधायकों के हलफनामों की समीक्षा की गई और पाया गया कि 92 विधायकों पर आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें से 33 विधायकों यानी 25 फीसद विधायकों ने गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। रपट में कहा गया है कि दो विधायकों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या से जुड़े मामले लंबित होने की जानकारी दी है जबकि तीन पर धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप हैं।

पेज 1 का बाकी

युद्ध की आग में भभका तेल

से कम थी। इसका असर भारत के शेयर एवं सर्राफा बाजारों पर दिया। बीएसई सूचकांक 2,497 अंक का गोता लगा गया, जबकि एनएसई निफ्टी 775 अंक लुढ़क गया। सोना और चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी की कीमतें 17,800 रुपए लुढ़ककर 2.38 लाख प्रति किलोग्राम रह गईं, जबकि सोने की कीमत 7,000 रुपए के नुकसान के साथ 1.53 लाख प्रति 10 ग्राम रह गई। ईरान ने गुरुवार की सुबह कतर के जिस रास लाफान केंद्र को निशाना बनाया, वह दुनिया की करीब पांचवें हिस्से की गैस की आपूर्ति करती है। इन हमलों से यह आशंका बढ़ गई है कि टैंकर यातायात के लिए होर्मुज जलमार्ग के बंद होने से उत्पन्न ऊर्जा संकट अपेक्षा से अधिक लंबा एवं व्यापक हो सकता है जिससे तेल एवं गैस उत्पादन को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है।

कतर आम तौर पर वैश्विक एलएनजी खपत का करीब 20 फीसद आपूर्ति करता है जिसे जहाजों के जरिये भेजा जाता है। ड्रोन हमले के बाद यह सुविधा बंद हो गई। होर्मुज के बंद होने से गैस की आपूर्ति के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं बचा है। होर्मुज जलमार्ग में ईरान के लगातार अवरोधों के कारण पहले से दबाव में बनी हुई वैश्विक आपूर्ति ईरान के इन हमलों से और अधिक दबाव में आ रही है। इस क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के तट के पास एक जहाज में आग लगा दी गई और कतर के पास एक अन्य जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। एक ईरानी ड्रोन से लाल सागर में स्थित सऊदी अरब की एक शोधनागार को निशाना बनाया गया। कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के हमलों की निंदा की। अरब लीग के महासचिव अहमद अबूल घीत ने इसे खतरनाक तरीके से उकसावे वाला बताया। सऊदी अरब ने बताया कि एक ड्रोन ने लाल सागर के किनारे स्थित बंदरगाह शहर यानबू में देश की एसएएमआरईएफ शोधनागार पर गुरुवार को हमला किया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है लेकिन उसने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। यह हमला कुवैत के दो तेल शोधनागारों पर ड्रोन हमले के बाद हुआ। तेहरान ने संयुक्त अरब अमीरात के हबशान गैस संयंत्र और बाब क्षेत्र को भी निशाना बनाया जिसे वहां की सरकार ने युद्ध में उकसाने वाला खतरनाक कदम बताया।

अबू धाबी के अधिकारियों ने कहा कि इन स्थलों पर गैस परिचालन बंद कर दिया गया था। कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर हुए इन हमलों से खाड़ी के अरब देशों पर दबाव बढ़ रहा है। ये देश 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ईरानी हमलों से अपनी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अपने सैन्य अड्डों, असैन्य स्थलों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले झेलने के बावजूद उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई जवाबी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने बताया कि ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइलें दागे जाने के दौरान कब्जे वाले पश्चिमी तट के बेत अवा कस्बे में कम से कम तीन लोग मारे गए और कम से कम 13 अन्य लोग घायल हुए। उधर, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान युद्ध को समाप्त करने का संकल्प लिया। हेगसेथ ने कहा कि ईरान संघर्ष कभी न खत्म होने वाला युद्ध या दलदल नहीं है। उनका देश तेहरान पर युद्ध खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हमला करेगा।

बढ़ते कामों के बीच विकेंद्रीकरण पर जोर दे रहा संघ : भागवत

नागपुर, 19 मार्च (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि संगठन ने अपने बढ़ते काम और लोगों की बढ़ती उम्मीदों के बीच अपने स्वयंसेवकों को सशक्त बनाने के लिए विकेंद्रीकरण की शुरुआत की है। नागपुर में मराठी अखबार 'तरुण भारत' के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि जेन जी (युवा पीढ़ी) उन विचारधाराओं की ओर आकर्षित होती है, जिनमें ईमानदारी और राष्ट्र सेवा की भावना हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस को अच्छे कामों के लिए सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है।

जब उनसे पूछा गया कि आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर हाल ही में संगठन में क्या बड़े बदलाव किए हैं, तो भागवत ने कहा कि संघ का काम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है और इसलिए अब विकेंद्रीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी इकाइयां जरूरी कामों को ज्यादा कुशलता से संभालेंगी, जबकि मित्रता रखने और खुद मिसाल बनकर नेतृत्व करने का मूल तरीका पहले जैसा ही रहेगा।

उन्होंने कहा, 'चूंकि आरएसएस से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, इसलिए स्वयंसेवकों को भी अब ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसलिए, अब और भी छोटी-छोटी इकाइयां बनाई जाएंगी, और जो काम पहले ऊपरी स्तर से होता था, वह अब ये छोटी इकाइयां करेंगी। जब कोई संगठन बड़ा होता है, तो यह एक स्वाभाविक बदलाव है।' भागवत ने बताया कि अब आरएसएस में 46 प्रांतों (प्रशासनिक इकाइयों) के बजाय 86 संभाग होंगे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि आरएसएस के काम करने का तरीका नहीं बदलेगा।

उन्होंने कहा, 'यह पहले जैसा ही रहेगा। काम करने का वह तरीका है मित्रता करना और खुद मिसाल बनकर बदलाव लाना, जो संघ का मूल सिद्धांत है।' जब भागवत से पूछा गया कि विपरीत परिस्थितियों में भी संघ का विस्तार कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन के विस्तार में प्रचार-प्रसार से मदद मिल सकती है, लेकिन आरएसएस की असली ताकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा, 'संघ का विस्तार ऐसे माध्यमों से नहीं होता। इसका विस्तार इसके काम और इसके कार्यकर्ताओं के बीच आपसी स्नेह से होता है।' भागवत ने युवा पीढ़ी के बारे में बात करते हुए कहा कि जेन जी ईमानदारी और राष्ट्र सेवा की ओर आकर्षित होती है और संघ की विचारधारा इन्हीं मूल्यों पर आधारित है।

जेन जी में 14 वर्ष के किशोर से लेकर 29 वर्ष के युवा होते हैं। जब संघ प्रमुख से पूछा गया कि क्या जेन जी के युवा आरएसएस की शाखाओं में शामिल होने के इच्छुक हैं और क्या संगठन उन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, तो भागवत ने कहा, 'वे शाखाओं में आते हैं।

राज्यसभा चुनाव में क्रास वोटिंग पर कांग्रेस सख्त

हरियाणा के चार विधायकों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

चंडीगढ़, 19 मार्च (ब्यूरो)।

राज्यसभा चुनाव में क्रास वोटिंग को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस ने हरियाणा के चार विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सोमवार को इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर क्रास वोटिंग की थी।

पार्टी के आधिकारिक रुख का उल्लंघन करने पर कांग्रेस की ओर से पांच में से चार विधायकों के नाम उजागर करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। पांचवें विधायक के नाम का अब तक खुलासा नहीं किया गया है।प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने गुरुवार को बताया कि पार्टी के चार विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चारों विधायकों से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने बताया कि चारों विधायकों से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।

नोटिस में कहा गया है कि कांग्रेस नेतृत्व के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि इन विधायकों ने कथित तौर पर निर्धारित प्रक्रियाओं और पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों के विपरीत जाकर मतदान किया, जिसके परिणामस्वरूप उनका वोट रद्द/अमान्य हो गया है।

नोटिस में कहा गया है कि अगर उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाता है, तो इसे पार्टी की आधिकारिक स्थिति को विफल करने के उद्देश्य से जानबूझकर किया गया प्रयास माना जाएगा। साथ ही पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। बुधवार को हरियाणा के प्रभारी कांग्रेस महासचिव बी के हरिप्रसाद ने चार कांग्रेस विधायकों के नाम उजागर करते हुए कहा कि उन्होंने संसद के ऊपरी सदन के चुनावों में ह्यक्रास वोटिंगह्न की थी। हरिप्रसाद ने दावा किया, 'नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, साढौरा विधायक रेनू बाला, पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास और हथीन से विधायक मोहम्मद इसराइल ने क्रास-वोटिंग की है।'

दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, कविता की पार्टी के पंजीकरण पर विचार करे आयोग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 मार्च।

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग से कहा कि वह भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की पूर्व नेता के कविता की उस याचिका पर विचार करे जिसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी 'तेलंगाना प्रजा जागृति' के पंजीकरण का अनुरोध किया है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि कविता के आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा।

कविता के वकील ने कहा कि 23 फरवरी को निर्वाचन आयोग ने पंजीकरण संबंधी आवेदन में जो खामियां बताई थीं उन्हें दूर कर लिया गया है।

न्यायालय ने आदेश दिया, चुनाव आयोग से कहा जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर विचार करे।' याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय ले, क्योंकि तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना अप्रैल में जारी होने वाली है। हालांकि अदालत ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग को कोई समय सीमा नहीं दे रही है।

राजनाथ ने वैश्विक संघर्षों का हवाला देते हुए ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 मार्च।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस-यूक्रेन और ईरान-इजराइल संघर्षों का जिक्र करते हुए गुरुवार को कहा कि भारत को ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में एक मजबूत तंत्र विकसित करना चाहिए। सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन में कहा कि इन दोनों संघर्षों ने ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकों के महत्त्व को स्पष्ट रूप से दर्शाया है।

उन्होंने कहा, 'पूरी दुनिया इस समय रूस-यूक्रेन के साथ-साथ ईरान और इजराइल से जुड़े संघर्ष को देख रही है और हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकों की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण होने वाली है।

उन्होंने कहा, 'आज भारत में ऐसा ड्रोन निर्माण तंत्र विकसित करने की जरूरत है जिसमें हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों।' इस सम्मेलन में देश की प्रमुख रक्षा निर्माण कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी भी शामिल हुए। सिंह ने कहा, 'भारत की रक्षा तैयारी और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए यह आवश्यक है कि भारत ड्रोन निर्माण में पूरी तरह आत्मनिर्भर बने।' रक्षा मंत्री ने कृत्रिम मेधा, रोबोटिक्स और अन्य नई एवं महत्त्वपूर्ण तकनीकों के बढ़ते महत्त्व पर भी प्रकाश डाला।

संपादकीय

खराताची राजकीय वरात

दावुनि वैराग्याची कळा । भोगी विषयाचा सोहळा ।। - या तुकोबारायांच्या पंक्तींची तंतोतंत प्रचिती देणारी खळबळजनक घटना नाशिकमध्ये उघडकीला आली आहे. स्वतःला 'कॅप्टन' म्हणवून घेणाऱ्या अशोक खरात नावाच्या वासनांध भोंदूबाबाच्या लीलांचे गलिच्छ तपशील बाहेर आल्याने लोक संतापले आहेत. पतीच्या मृत्यूची भीती दाखवून एका महिलेवर अत्याचार, सोबत तब्बल ५८ व्हिडिओ अशा काळ्या कृत्याचे या खराताचे भांडे तर फुटलेच, वरून आपली राजकीय व्यवस्था किती किडलेली, सारासार विवेक गमावलेली आहे, हेही चव्हाट्यावर आले. हा केवळ एका गुन्हेगाराचा भांडाफोड नाही; तो राजकीय वास्तवाचे सडलेले प्रतिबिंब दाखवणारा आरसा आहे. महिलांचे शोषण, मानसिक गुलामी, अंधश्रद्धेच्या नावाखाली विकृत कारभार हे सारे संतापजनक आहेच; पण त्याहून अधिक धक्कादायक आहे ती या बाबाच्या दरबारात बडे राजकीय नेते, उच्च पदस्थांची लागणारी रांग. समस्यांनी ग्रासलेला, परिस्थितीने पिचलेला सामान्य माणूस अशा बुवाबाबांच्या आश्रयाला जाणे, त्यांच्या कच्छपी लागून सर्वस्व गमावण्याइतका आंधळा व हतबल होणे एकवेळ समजून घेता येईल. पण ज्यांच्या हाती सत्ता, संपत्ती, यंत्रणा अशी सारी सूत्रे आहेत, त्या बड्या नेत्यांनी या असल्या टीनपाट भोंदूंच्या मागे का लागावे? या मंत्री-संत्री लोकांची अशी काय हतबलता असते की भलत्या चमत्कारांचे दावे करणाऱ्या कुण्या बाबाचे पाय धुवून पुसण्याची गरज त्यांना भासावी? मुख्यमंत्री, मंत्री वा तत्सम पदे भूषविलेले सत्ताधारी- विरोधक, पुरुष-महिला या सगळ्यांचीच या खराताच्या 'दरबारात' लागणारी उपस्थिती केवळ योगायोग नाही. त्यामागे प्रामुख्याने तीन कारणे असतात - असुरक्षितता, लालसा आणि काळे व्यवहार. सत्तेवरील लोकांना भीती असते ती सत्ता गमावण्याची. निवडणूक जिंकायची, खुर्ची टिकवायची, प्रतिस्पर्ध्याला हरवायचे या सगळ्यासाठी 'काहीही' करण्याची मानसिकता प्रसंगी कोणत्या टोकाला जाते याचे सांप्रत काळीचे दाखले कित्येक हजार. पण अंधश्रद्धेच्या कर्दमात सामान्यांना लोटून सर्व प्रकारचे भोग सुखनैव भोगणाऱ्या असल्या बाबांच्या पायी लीन होणारे, त्यांची पूजा-अर्चा करणारे राजकीय नेते ही ऱ्हासाची नक्की कोणती पातळी म्हणायची? हे सत्ताधारी किंवा सत्तेच्छू लोक चक्क वासनांधांच्या दरबारात हजेरी लावून असे लवलवून वाकतात याचे दुसरे कारण लालसा. सत्ता, तिच्यातून मिळणारा अमाप पैसा आणि वाढता प्रभाव यातून आपण कुणाला प्रतिष्ठा देतो आहोत, हे समजून घेण्याचे भान राहात नाही. तिसरे कारण आहे काळे व्यवहार लपवण्याची धडपड. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी, चौकशा थांबवण्यासाठी किंवा 'वरच्या' स्तरावरून संरक्षण मिळवण्यासाठी अशा भोंदूंचा वापर केला जातो, हे आता गुपित राहिलेले नाही. अशोक खरात प्रकरणात पुढाऱ्यांच्या या जवळिकीपेक्षा अधिक धक्कादायक आहे ते, ज्यांच्यावर राज्यभरातील महिलांच्या संरक्षणाची घटनादत्त जबाबदारी त्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर याच कथित 'कॅप्टन'च्या देवस्थानाच्या विश्वस्त असाव्यात आणि महिलांचे शोषण करणाऱ्या या बाबासोबतचे त्यांचे व्हिडिओ, छायाचित्रे अटकेनंतर काही तासांत सोशल मीडियात यावीत! म्हणून किमान या भोंदूच्या काळ्या कृत्याचा न्यायनिवाडा न्यायालयात होईपर्यंत नैतिक जबाबदारी म्हणून महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी पद सोडायला हवे. खरात प्रकरणाच्या तपशिलांमुळे एकीकडे सामान्य माणूस संतापलेला असताना त्यातल्या त्यात सकारात्मक बाब म्हणजे नाशिकचे पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी राजकीय दडपणाला न जुमानता केलेली कारवाई. ही केवळ एका आरोपीवरची कारवाई नाही; ती व्यवस्थेतल्या कणखरपणाची झलकदेखील आहे. मात्र, अशी कारवाई अपवाद न ठरता नियम ठरावा. या प्रकरणात फक्त अशोक खरात नावाचा इसम दोषी नाही. त्याच्या दरबारात उपस्थित राहून त्याला वैधता, प्रतिष्ठा देणारे राजकीय चेहरेही तितकेच जबाबदार आहेत. 'आम्ही फक्त दर्शनाला गेलो होतो' हा त्यांचा बचाव आता यंत्रणेने आणि जनतेनेही चालवून घेता कामा नये. ज्यांनी विवेक, विज्ञाननिष्ठा आणि कायद्याचा आदर राखायचा, तेच जर अंधश्रद्धेच्या पायाशी लोटांगण घालत असतील, तर सामान्य माणसाने कोणावर विश्वास ठेवायचा? गावोगावी भोंदूबाबा उगवतात, कारण त्यांना पोसणारी राजकीय माती सुपीक असते. ती माती बदलली नाही तर आजचा खरात जाईल आणि उद्या दुसरा 'कॅप्टन' उभा राहील. कदाचित आणखी प्रभावी, आणखी धोकादायक. तेव्हा या थोतांडाचा निकाल जनतेच्या दरबारातही लागला पाहिजे. न्यायव्यवस्थेने त्याचा चौरंग करायला हवा आणि भोंदू भोगसम्राटांच्या पायावर झुकणाऱ्या राजकीय नेत्यांना जनतेने रोकडा जाब विचारायला हवा.

विधिमंडळात अजितदादांच्या मृत्यूची चर्चा का नाही?

'तो घातपात तर नव्हता ना?' अशी शंका रोहित पवार यांनी तयार केलीच आहे. विधिमंडळात या शंकेचे निरसन करण्याची संधी सरकार का साधत नसावे?

यदु जोशी
राजकीय संपादक, लोकमत

मिळेल त्या व्यासपीठावर जाऊन गेले काही दिवस रोहित पवार हे 'माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू हा अपघात नाही तर घातपात होता' हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते संयुक्त राष्ट्रसंघाकडेही जातील कदाचित. मृत्यूनंतर दादांना ते इतके जपत असतात, आधीच जपले असते तर कदाचित वेगळे चित्र दिसले असते.

राजकारणात ज्यांचे ऐकले नाही त्यांच्याबद्दल मोठा आवाज करून बोलले जात आहे. गेल्यानंतरच माणसाबद्दल आदर वाटू लागतो वा त्याची किंमत कळते असे आपण म्हणतोच ना..! 'आपण दीर्घकाळ ज्या सभागृहात राहिलो, महाराष्ट्राच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले, तिथे आपल्याच मृत्यूची चर्चा का होत नसेल', असा प्रश्न अजितदादांनाही स्वर्गात पडला असेल.

सरकारलाही संधी

आरोपांची राळ ज्यांनी उठविली आहे ते रोहित पवार विधानसभेचे सदस्य आहेत, सभागृहात हा विषय आला तर ते आणखी मोठे गौप्यस्फोट करतील असे त्यांच्या जवळची एक व्यक्ती परवा सांगत होती. हा अपघात होता की घातपात? हे उद्या 'सीबीआय'पासून तत्सम चौकशांमधून समोर येईलच; पण त्याबाबत संशयाचे धुके रोहित यांनी नक्कीच तयार केले आहे. या धुक्यात तर विधिमंडळातील चर्चा हरवली नाही ना अशी शंका येत आहे. तो घातपातच होता असे लोकांना अजूनही वाटत नाही; पण 'तो घातपात तर नव्हता ना?' अशी शंका लोकांच्या मनात रोहित यांनी निर्माण केली आहे. या शंकेचे निरसन करण्याची संधी या विषयावर विधिमंडळात चर्चा घडवून आणत सरकारला साधता येऊ शकते.

अजित पवार यांच्या मृत्यूप्रकरणी सीबीआय चौकशी केली जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने आधीच घेतली आहे. त्यासाठी एक प्रक्रिया असते. राज्य सरकारने केंद्राला तसे पत्र पाठवावे लागते, ते अद्याप पाठविलेले नाही, असा रोहित पवार यांचा आरोप आहे. सीबीआय चौकशीच्या अनुषंगाने आतापर्यंत काय-काय झाले ते सरकारला सभागृहाच्या माध्यमातून राज्याला सांगता येऊ शकेल. चर्चा घेतलीच नाही तर शंकांना उगाच बळ येईल, ते होऊ द्यायचे का ते सरकारने ठरवायला हवे.

मुख्यमंत्र्यांचे पत्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन आठवड्यांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवून अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूची पारदर्शक, कालबद्ध आणि सर्वसमावेशक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यात आ. रोहित पवार यांनी व्यक्त केलेल्या शंकांचाही उलगडा व्हायला हवा

अशी भूमिका घेतली आहे. चौकशी यंत्रणांना आपले सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी हमी या पत्रात देण्यात आली आहे. फडणवीस आणि अजितदादांची एक वेगळीच केमिस्ट्री होती, दोघांचा एकमेकांवर प्रचंड विश्वास होता. 'अपघाताच्या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रत्येक मुद्यातील तथ्य समोर आणलेच जाईल,' असे फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या कुटुंबीयांनाही सांगितले आहे.

सगळे नेमके कशासाठी?

अपघातासंदर्भात एक संशयाचे जे वातावरण तयार केले जात आहे त्याद्वारे मुख्यत्वे राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटातील विशिष्ट नेत्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न आहे. पक्षाची सूत्रे प्रस्थापित नेत्यांकडे राहू नयेत, त्यांना बाजूला केले जावे असे वाटणाऱ्या ज्या व्यक्ती दोन्ही राष्ट्रवादींमध्ये आहेत त्या या मोहिमेत अग्रेसर आहेत. आरोपांमध्ये तथ्य नाही असे समोर आले तर विशिष्ट नेत्याला बदनाम करण्याचाच केवळ हेतू होता हे आणखीच स्पष्ट होईल. बरेचदा अशा दुर्घटनांच्या निमित्ताने काही जणांची राजकीय वाट रोखली जाते, राजकारण बिघडविले जाते, तथ्य समोर येते तेव्हा त्यांची कारकीर्द संपून गेलेली असते.

अजितदादांच्या मृत्यूने असे काही घडू द्यायचे नसेल तर सरकारनेही तथ्य तातडीने समोर आणले पाहिजे. कारण शंका उपस्थित करायला सत्याचा आधार घ्यावाच लागतो असे नाही. शंका-कुशंकांच्या आधारे कोणाला घेरले जात असेल तर ते योग्य नाहीच; पण उद्या शंकाच सत्य निघाल्या तर त्या मागील सूत्रधारांनाही सोडता कामा नये या दोन्ही बाबींचा विचार करून विधिमंडळात चर्चा होणे आणि अपघातप्रकरणाची सीबीआय चौकशी तातडीने होणे गरजेचे आहे.

ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती मृत्यूच्या निमित्तानेही असेच काही जणांना लक्ष्य करण्यात आले होते. मात्र, त्यात काही तथ्य नसल्याचे नंतरच्या काळात स्पष्ट झाले. इतिहासातही अनेक मोठ्या नेत्यांच्या अपघाती मृत्यूमागे षडयंत्राची थिअरी मांडली गेली होती. असे म्हणतात की पुणे-बारामतीत घर असलेल्या एका वैमानिकाने अजितदादांच्या अपघातासंबंधीचा घटनाक्रम, हवाई वाहतुकीचे तांत्रिक मुद्दे, 'त्या' विमानातील तांत्रिक कच्चे दुवे, त्यावेळचे हवामान या आधारे 'अपघात नाही घातपात' अशी मांडणी केली आहे. रोहित पवार यांच्यासह एक-दोन नेत्यांकडे त्याने हे सगळे पोहोचविले आहे. रोहित पवार हे त्यातल्याच बहुतेक मुद्यांची मांडणी करत असतात, जोडीला त्यांनी अन्य काही तज्ज्ञांकडूनही इनपुट घेतले आहेत. पुणे-बारामतीच्या त्या व्यक्तीला वैमानिक होण्यासाठी अजितदादांनीच मदत केली होती, अशी माहिती आहे.

yadu.joshi@lokmat.com

प्रासंगिक

ऐतिहासिक तळ्याचे पाणी पुन्हा 'चवदार' करण्यास कटिबद्ध

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील महाडच्या चवदार तळ्याचा संघर्ष सामाजिक न्यायाचा अभूतपूर्व लढा होता. या सत्याग्रह दिनानिमित्त विशेष लेख.

संजय शिरसाट
मंत्री, सामाजिक न्याय, महाराष्ट्र शासन

भारतीय समाजव्यवस्थेत समानता, स्वाभिमान आणि मानवी हक्कांसाठी उभ्या राहिलेल्या चळवळींमध्ये 'महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह' एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जातो. एका पाण्याच्या तळ्यावरून उभा राहिलेला हा संघर्ष केवळ जलहक्काचा नव्हता, तर तो मानवी अस्मिता आणि सामाजिक न्यायाचा लढा होता. महामानव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या क्रांतिकारी नेतृत्वाखाली २० मार्च १९२७ रोजी महाड येथे झालेला हा संघर्ष केवळ पाणी पिण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर तो हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीच्या शृंखला तोडून मानवी प्रतिष्ठा प्रस्थापित करण्याचा एक प्रारंभबिंदू होता. आज आपण या ऐतिहासिक घटनेच्या शताब्दी वर्षाच्या (२०२७) उंबरठ्यावर उभे असताना, राज्य शासन या स्मृतिभूमीचा कायापालट करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाच्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुयायांना दोन महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या होत्या - जागृतीचा अग्नी अखंड तेवत ठेवा आणि विचारांमध्ये परिवर्तन घडवा. त्यांनी स्पष्ट केले होते की, विचारात परिवर्तन झाल्याशिवाय आचरणात परिवर्तन होऊ शकत नाही. अस्पृश्यांना समानतेचा हक्क नाकारला जात असताना, त्यांनी संघटित लढ्याद्वारे चवदार तळ्याचे पाणी पिऊन सामाजिक परिवर्तनाची दिशा दाखवली. त्यांच्या आंदोलनामागे स्पष्ट विचार, उदात्त उद्देश आणि संघटित कृती होती. बाबासाहेबांच्या मते, समाजपरिवर्तनासाठीचा विचार अत्यंत महत्त्वाचा असून, तोच व्यक्तीच्या आचरणाला दिशा देतो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेली आंदोलने सामाजिक न्याय, समानता आणि जन्मसिद्ध हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी होती. त्यांच्या लढ्याचा मुख्य उद्देश समाजातील हीनत्वाची भावना दूर करून लोकांच्या मानसिकतेत बदल घडवणे हा होता. पाणी ही निसर्गाची देणगी असून, ती सर्वांसाठी समान आहे, हे त्यांनी कृतीतून दाखवून दिले. हा सत्याग्रह केवळ पाण्याचा प्रश्न नव्हता, तर तो मानवी हक्क आणि

स्वाभिमानासाठीचा निर्णायक संघर्ष होता. या आंदोलनातून अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची प्रेरणा आजही मिळते. सामाजिक न्यायमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर, मागील वर्षी २० मार्च २०२५ रोजी मी महाड येथील पवित्र चवदार तळ्याला भेट दिली होती. त्यावेळी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. अनेक अनुयायांच्या मनात एक खोल खंत होती की, ज्या तळ्याने जगाला समतेचा संदेश दिला, त्या तळ्यातील पाणी आज हिरवे पडले असून, ते पिण्यायोग्य राहिलेले नाही. त्यांच्या या तीव्र भावनांनी माझे मन हेलावून गेले. बाबासाहेबांनी ज्या पाण्यासाठी ऐतिहासिक संघर्ष केला, ते पाणी शुद्ध करून सर्वांना पुन्हा एकदा त्याच्या मूळ 'चवदार' स्वरूपात उपलब्ध करून देणे, हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल.

पंजाबमधील अमृतसर येथील शीख धर्मीयांच्या पवित्र सुवर्ण मंदिरात अहोरात्र जलशुद्धीकरण करणारा विशेष प्रकल्प यशस्वीपणे राबविला जात आहे. त्याच धर्तीवर क्रांती आणि समतेची प्रेरणा देणारी ऊर्जाभूमी असलेल्या महाड येथील चवदार तळ्याचा कायापालट करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. या संकल्पपूर्तीसाठी राज्य शासनाने तावडीने पावले उचलत १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करून ५५ कोटी ७९ लाख ८५ हजार ६५३ रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२६-२७ हे वर्ष 'सामाजिक समता आणि समरसता वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. महाडच्या या भूमीला जागतिक दर्जाचे प्रेरणास्थान बनवणे, हाच शासनाचा निर्धार आहे. आज, २० मार्च २०२६ रोजी सत्याग्रहाच्या ९९व्या वर्धापनदिनी, या महत्त्वाकांक्षी जलशुद्धीकरण आणि सुशोभीकरण कामांचा खऱ्या अर्थाने शुभारंभ होत आहे. पुढील वर्षी जेव्हा आपण या सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्ष (२०२७) साजरे करू, तेव्हा हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेलेला असेल. त्या सुवर्णक्षणी चवदार तळ्याचे पाणी खरोखर 'चवदार' होईल आणि प्रत्येक भीमसैनिकाला ते तृप्त होऊन चाखता येईल, याची मला मनोमन खात्री आहे. राज्यातील स्मारके आणि स्मृतिस्थळांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मात्र, केवळ स्मारके उभारणे हा उद्देश नसून, त्यातून सामाजिक समतेचा विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे हेच आमचे खरे ध्येय आहे.

जगभर

३० अब्ज वर्षांत सेकंदाची चूक! चीनचं नवं घड्याळ

घड्याळ म्हटलं, तर एक अतिशय साधी आणि छोटीशी गोष्ट. आजकाल जवळपास प्रत्येकाकडे मोबाइल असतो आणि अगदी साध्यातल्या साध्या मोबाइलमध्येही घड्याळ असतंच आणि ते अचूक वेळ दाखवतं. त्यामुळे प्रत्यक्ष मनगटी घड्याळ वापरण्याची फारशी गरज आता राहिलेली नाही. अर्थात घड्याळाचे शौकिन अजूनही आपल्या हातावर स्टायलिश घड्याळं बांधतातच आणि भिंतीवरची घड्याळंही अजून अनेक ठिकाणी वापरली जातात.

असं असतानाही चीनमधल्या वैज्ञानिकांनी जगातल्या सर्वात अचूक घड्याळांपैकी एक विकसित केलं आहे. हे ऑप्टिकल घड्याळ इतकं अचूक आहे की, पुढच्या सुमारे ३० अब्ज वर्षांत यात झालीच तर फक्त एक सेकंदाची चूक होऊ शकते! खरं तर याला चूकही म्हणता येणार नाही. ३० अब्ज वर्षांत हे घड्याळ केवळ एखाद्या सेकंदानं मागे-पुढे होऊ शकतं! आणखी सोप्या शब्दांत सांगायचं तर, वेळेच्या मापनात केवळ एका सेकंदाचा फरक पडण्यासाठी ३० अब्ज वर्षे लागतील. तेव्हाही तो फरक पडेलच असं नाही! संशोधकांचं म्हणणं आहे, हे तंत्रज्ञान भविष्यात वेळेचं सर्वांत छोटं एकक म्हणजेच सेकंदाची नवी व्याख्या ठरवायला मदत करू शकतं.

चीनमधल्या युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स ॲण्ड टेक्नॉलॉजीनं हे स्ट्रॉन्शियम ऑप्टिकल लॅटिस घड्याळ तयार केलं आहे. ही घड्याळं अणूंमधील ईलेक्ट्रॉनच्या ऊर्जास्तरात बदल होताना निर्माण होणाऱ्या प्रकाशाच्या वारंवारतेचं मापन करून वेळ ठरवतात. ऑप्टिकल घड्याळं सध्या जगात सर्वात अचूक वेळ मोजणारं तंत्रज्ञान म्हणून प्रसिद्ध आहेत. या घड्याळांची वेळ अत्यंत अचूक आणि काटेकोर असल्यामुळे सॅटेलाइट नेव्हिगेशन, टेलिकॉम आणि वैज्ञानिक मापनात त्यांचा वापर केला जाऊ लागला आहे. या घड्याळांमुळे गुरुत्वाकर्षणात होणारे छोटे बदल, पृथ्वीच्या पृष्ठभागात होणारे बदल आणि

ज्वालामुखीच्या हालचाली अधिक अचूकपणे समजून घेणं शक्य होईल.

वैज्ञानिकांचं म्हणणं आहे, जगातल्या वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये अशी किमान तीन घड्याळं समान अचूकतेनं काम करू लागली, तर भविष्यात 'सेकंदा'ची व्याख्या पुन्हा ठरवता येईल. सध्या काही घड्याळं या पातळीपर्यंत पोहोचली असून, लवकरच आवश्यक त्या अटी पूर्ण होऊ शकतात, असं दिसतं. चीनच्या संशोधकांनी जे घड्याळ तयार केलं आहे, ते आधीच्या तंत्रज्ञानापेक्षा अनेक पट जास्त अचूक आहे. ही यशस्वी कामगिरी डार्क मॅटरच्या शोधात आणि वेळेच्या आंतरराष्ट्रीय व्याख्येचं पुनर्निर्धारण करण्यात मदत करू शकते.

या घड्याळांमध्ये अत्याधुनिक वेळ मापन यंत्रणा असून सेकंदाची लांबी मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक सीझियम अणुघड्याळांच्या तुलनेत ती शंभर पट अधिक अचूक आहेत. सामान्य घड्याळांप्रमाणे ही घड्याळं काम करत नाहीत. वेळ अत्यंत अचूकपणे मोजण्यासाठी स्ट्रॉन्शियम अणू आणि लेझर तंत्रज्ञानाचा त्यात वापर केला जातो.

स्ट्रॉन्शियम घड्याळांमधले अणू दृश्यमान प्रकाशाच्या वारंवारतेवर दोलन करतात आणि त्यांची वारंवारता आपल्या कल्पनेपेक्षाही खूप जास्त म्हणजे प्रत्येक सेकंदाला सुमारे ७०० ट्रिलियन वेळा इतकी असते. त्यामुळे वेळ अतिशय बिनचूकपणे मोजता येते. आंतरराष्ट्रीय मापन एककांशी संबंधित निर्णय दर चार वर्षांनी होणाऱ्या वजन आणि मापन संयुक्त परिषदेत (CGPM) घेतले जातात. सध्याचं उद्दिष्ट सेकंदाच्या नव्या व्याख्येसाठी प्रस्ताव तयार करून तो २०३०च्या अधिवेशनात मांडणं. संशोधक त्यासाठी कस्सून तयारी करीत आहेत.

जनमन

युद्धात निरपराधांचीच अधिक होरपळ!

गेल्या काही दिवसांपासून आखाती देशात युद्धाचा भडका उडाला असून, शेकडो लोकांचे प्राण गेले आहेत. कोट्यवधीच्या मालमत्तेची हानी झाली आहे. हजारो भारतीय दुबई व इतर देशात अडकून पडले असून ते भीतीच्या छायेत वावरत असून जीव मुठीत धरून एकेक दिवस कंठीत आहेत. त्यासाठी भारताने अधिक जोरदार प्रयत्न करून त्यांना मायदेशात परत आणावे अशी भारतीय जनतेची मागणी आहे. सर्वजण सातत्याने एका अनामिक अशा भीतीच्या सावटाखाली वावरत आहेत.

इराण, अमेरिका, इस्रायल यांच्या अहंकारी वृत्तीमुळे आपली एकमेकांची संरक्षण क्षमता सिद्ध करण्यासाठी मानवाचा संहार करण्याचे दुष्कृत्य त्यातून होत आहे. कोणीच माघार घ्यायला तयार नाही. माणुसकीला काळिमा फासणारी ही गोष्ट असून त्याचा गंभीर दुष्परिणाम निरपराधी देशांना आणि नागरिकांना भोगावा लागत आहे. इंधन, कच्च्या मालाच्या अभावी, गॅसच्या भयंकर तुटवड्यामुळे हॉटेल व्यवसाय तसेच मोठमोठे उद्योग संकटात आले आहेत किंबहुना ते बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

कृत्रिम टंचाई, महागाई, काळाबाजार वाढला असून सामान्य माणूस त्रस्त झाला झाला आहे. तो महागाई व टंचाईच्या आगीत होरपळून निघत आहे. त्याला दैनंदिन जीवन जगणे मुश्किल झाले आहे. जगात शांतता राखण्यासाठी व युद्ध थांबविण्यासाठी भारताने मध्यस्ती करून इतर मित्रराष्ट्रांनाही आवाहन करावे. तसेच भारतच्या मानवतावादी व सांस्कृतिक परंपरेचे दर्शन घडवावे. भगवान बुद्धाची अहिंसा, प्रेम, संयम व मानवतेची शिकवण आचरणात आणावी.

- डॉ. श्यामसुंदर झळके, सिन्नर

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

आंदोलनांचे अंतरंग

'अदृश्य' झालेल्या मुलांच्या शोधात स्त्रिया जेव्हा वणवण भटकतात..

हुकूमशाही किंवा टोकाच्या राजकीय अस्थिर देशांमधल्या सरकारी यंत्रणाच माणसांना 'गायब' करतात. कुटुंबाला उलट विचारतात, 'तो घरी आला नाही?'

डॉ. नीलम गोऱ्हे
उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद

जगाच्या पाठीवर राजकीय सिद्धांत आणि सत्तासंघर्षाचे खेळ सुरू असताना, या संघर्षाच्या पडद्यामागे एक अशी भीषण शोकांतिका घडत असते, ज्याची नोंद इतिहासाच्या पानांवर क्वचितच होते. जागतिक स्तरावर शांततेचे समर्थन करणारे अनेक गट आहेत. यात प्रामुख्याने अशा छोट्या देशांचा समावेश असतो, ज्यांच्यावर मोठ्या राष्ट्रांनी आक्रमण केले आहे किंवा जिथे देशांतर्गत फुटीरतावाद आणि यादवी सुरू आहे. परंतु, या सर्व राजकीय उलथापालथीत सर्वाधिक होरपळली जाते ती म्हणजे 'स्त्री'.

नुकत्याच एका जागतिक व्यासपीठावर मला काही अशा महिला भेटल्या, ज्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू आता आटले होते; पण त्यांच्या मनातील आक्रोश आजही तितकाच जिवंत होता. त्या व्यासपीठावर 'मदर्स ऑफ डिसअपिअर्ड' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मातांची एक मानवी साखळी उभी होती. ही केवळ एक साखळी नव्हती, तर ती एक 'निशब्द' आंदोलनाची गाथा होती.

या मातांच्या कहाण्या ऐकल्या की अंगावर काटा येतो. एखाद्या दिवशी घरातील तरुण मुलगा, पती किंवा भाऊ कामासाठी किंवा सैन्यातील कर्तव्यासाठी बाहेर पडतो. त्याला पोलिस किंवा सरकारी यंत्रणेद्वारे चौकशीसाठी बोलावले जाते. तो जातो; पण पुन्हा कधीच परत येत नाही. लोकशाही देशांमध्ये एखादी व्यक्ती बेपत्ता झाली तर 'मिसिंग'ची तक्रार घेतली जाते, तपास होतो आणि बहुतांश वेळा त्या व्यक्तीचा थांगपत्ता लागतो. दुर्दैवाने मृत्यू झाला असेल तर तसे तरी कळते. परंतु, हुकूमशाही किंवा टोकाच्या राजकीय अस्थिरतेच्या देशांमध्ये चित्र वेगळे आहे.

तिथे सरकारी यंत्रणाच माणसांना 'गायब' करतात. कुटुंबाने विचारणा केली तर यंत्रणा उलट विचारतात, 'तो घरी परत आला नाही का?' १५-२० वर्षे उलटतात, मुले मोठी होतात; पण त्या माणसाचे स्टेटस 'अदृश्य' हेच राहते. तो जिवंत आहे की मृत, तो कोणत्या तुरुंगात आहे की त्याला संपवण्यात आले आहे, याचे उत्तर ना सरकार देते, ना कायदा.

आज अफगाणिस्तान, पाकिस्तान यांसारख्या देशांमध्ये गुप्तहेर यंत्रणांच्या संघर्षात सामान्य नागरिक भरडला जात आहे. विकासाच्या संधी न मिळाल्यामुळे आंदोलने उग्र बनतात, तेव्हा तिथेही अशा प्रकारच्या अदृश्य होण्याच्या घटनांच्या चर्चा कानावर येतात. रशिया, युक्रेन किंवा अफगाणिस्तान, आफ्रिकेतील काही देशांमधील यादवीत अशा 'गायब' झालेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे.

या छळाला कंटाळून अनेक स्त्रिया दुसऱ्या देशात आश्रय घेतात. परदेशात राहून त्या आपल्या मायदेशातील लोकांशी संपर्क साधून पुराव्यांची जुळवाजुळव करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांचे आंदोलन 'निशब्द' असते, कारण जगाच्या भिंती ओलांडून त्यांचा आवाज त्यांच्या स्वदेशातील सत्ताधीशांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता धूसर असते.

भारतामध्ये लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट असल्याने अशा घटनांचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे, ही जमेची बाजू. परंतु, जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात जेव्हा एखादी माता आपल्या मुलाची वाट पाहत 'अदृश्य' भिंतींशी संवाद साधते, तेव्हा तो केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न राहत नाही, तर तो मानवी सभ्यतेपुढील प्रश्न ठरतो. राजकीय राजवटी येतात आणि जातात; पण या मातांच्या डोळ्यांतील 'नि:शब्द कहाणी' कायमची कोरली जाते.

neeilamgorhe@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.)
'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

इलेक्ट्रिक एसटींचे कंत्राट रद्द करण्यात वेळकाढूपणा : बरगे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या ५,१५० इलेक्ट्रिक बस भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या प्रकल्पाबाबत कंत्राट रद्द करण्यासाठी प्रशासनाकडून होत असलेल्या वेळकाढूपणावर तीव्र टीका करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांच्या निर्देशांनंतरही अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला.

बरगे यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरला नसून एसटी महामंडळाला प्रति किलोमीटर २८ ते ३० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. वाढता आर्थिक बोजा लक्षात घेऊन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हा प्रकल्प तातडीने रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) आणि अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या संयुक्त बैठकीचे निर्देश दिले होते. मात्र, १७ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीला वित्त विभागातील एकही अधिकारी उपस्थित नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचे बरगे यांचे म्हणणे आहे.

मविआला एकच जागा, ८ महायुतीच्या पारड्यात!

परिषद निवडणूक : भाजपला ५ जागा, काँग्रेसला भोपळा?

लोकमत विशेष

यदु जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : विधानसभा सदस्यांमधून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या ९ जागांसाठी पुढील महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता असून महायुतीला ८ तर महाविकास आघाडीला केवळ १ जागा मिळेल, असे आमदारांच्या संख्याबळावरून स्पष्टपणे दिसत आहे. उद्धवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे पुन्हा विधान परिषदेवर जाण्याची शक्यता असली तरी मविआमध्ये एका जागेसाठी रस्सीखेच असेल.

राज्यसभा निवडणुकीत मविआकडे एकच जागा आली होती. त्यावर तिन्ही पक्षांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना संधी दिली. त्यामुळे विधान परिषदेची जागा शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला दिली जाणार नाही हे स्पष्ट आहे. परिणामी आमदारकीचा कार्यकाळ संपत असलेले या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यावेळी विधान परिषदेवर जाणार नाहीत, असे चित्र आहे.

काँग्रेस एका जागेसाठी अडून बसली तर मविआत पेच निर्माण होईल. भाजप व राष्ट्रवादीकडे (अजित पवार) अतिरिक्त मतांच्या आधारे महायुतीची आठवी जागा निवडून येईल ती व आणखी एक अशा दोन जागा आपल्याला द्याव्यात असा आग्रह अजित पवार गट धरू शकतो.

...तर निवडणूक बिनविरोध

१ सर्व नऊ आमदारांचा कार्यकाळ येत्या मे मध्ये संपणार आहे. त्या आधी एप्रिलमध्ये निवडणूक होईल. राज्यसभेवेळी शरद पवार हे उमेदवार असल्याने निवडणूक बिनविरोध झाली होती. यावेळी उद्धव ठाकरे उमेदवार असल्यास निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता असेल.

२ **उद्धवसेनेचे २०, काँग्रेसचे १६ व राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) १० असे एकूण ४६ आमदार आहेत. एक जागा जिंकण्यासाठी २९ चा कोटा आहे. काँग्रेस शिवायही उद्धवसेना-राष्ट्रवादी (शरद पवार) हे एकत्रित एक जागा जिंकू शकतात पण ते काठावरचे असेल.**

एकनाथ शिंदेंचे धक्कातंत्र, की?

विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना पुन्हा संधी मिळेल, असे मानले जाते.

डॉ. ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेवर संधी दिल्याने वंचित राहिलेले पक्षातील बरेचसे नेते विधान परिषदेसाठी इच्छुक आहेत.

त्यामुळे दोन जणांची निवड करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कसरत होणार आहे.

आमचाच दावा : वडेट्टीवार

काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, मविआच्या कोट्यातील एक जागा काँग्रेसलाच मिळाली पाहिजे. राज्यसभेत आम्ही शरद पवार यांच्या पाठीशी उभे राहिलो, काँग्रेसला आता संधी द्यावी.

संघाच्या प्रचारक रचनेत बदल, कार्यपद्धती मात्र कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रचारक रचनेत बदलांना मान्यता मिळाली असून आता प्रांताऐवजी विभागनिहाय प्रचारक राहणार आहेत. हरयाणातील समालखा येथील अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर गुरुवारी सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी याबाबत येथे एका कार्यक्रमात बोलताना ही माहिती दिली. संघकार्य वाढत असल्याने संघाच्या प्रचारक रचनेत बदल करण्यात आला आहे. मात्र संघाची कार्यपद्धती आतापर्यंत होती तशीच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शंभर वर्षांच्या कार्यकाळात संघाचे काम मोठे झाले आहे. त्यामुळे रचना विकेंद्रित होणे आवश्यक झाले. अनेकदा शासन-प्रशासनाशी संबंध येतो. त्यासाठी वेगळी व्यवस्था हवी या विचारातून बदल केला आहे. असे त्यांनी स्पष्ट केले.

काही कम्युनिस्टांनाही संघ चांगला वाटतो

काळासोबत संघाचे कार्य वाढले आहे. आता विरोधक व काही कम्युनिस्ट बोलताना संघाचे आम्ही विरोधक आहोत, असे म्हणतात. मात्र, संघ चांगला आहे असेही ते म्हणतात, असा दावा डॉ. मोहन भागवत यांनी केला.

'जेन-झी'ला सेवाकार्याचे आकर्षण

'जेन-झी' पिढीला सेवेचे आकर्षण आहे. त्यामुळेच त्यांची संघविचारांशी नाळ जुळत आहे. हायराईज इमारती, सोसायटींमध्ये तरुणांशी संपर्क साधण्यावर भर देण्यात येत आहे, अशी माहिती सरसंघचालकांनी दिली.

AI ची अद्भुत दुनिया...

दैनिक 'लोकमत'मध्ये 'AI ची अद्भुत दुनिया' हे विशेष सदर असणार आहे. यावर विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे देऊन भरघोस बक्षिसे जिंकण्याची संधीही मिळणार आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी संधी की सावधगिरीचा इशारा?

आजच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणत आहे. 'चॅटजीपीटी'सारखी एआय आधारित साधने विद्यार्थ्यांना संवादाच्या माध्यमातून शिकण्याची नवीन दिशा देत आहेत. ही साधने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना त्वरित उत्तर देतात, कठीण विषय सोप्या भाषेत समजावतात आणि वैयक्तिक शिकण्याची संधीही निर्माण करतात. त्यामुळे पारंपरिक शिक्षणासोबत डिजिटल व स्मार्ट शिक्षणाचा समतोल साधला जात आहे. मात्र, या बदलत्या प्रवाहात विद्यार्थ्यांनी या साधनांचा योग्य वापर केला तरच त्याचा खरा फायदा मिळू शकतो.

शिक्षण क्षेत्रात एआयचा वापर वाढत असताना, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाच्या सवयींमध्ये मोठे बदल दिसून येत आहेत. पूर्वी तासन्तास पुस्तकं चाळून माहिती शोधावी लागायची; आता काही सेकंदांत संपूर्ण विषय डोळ्यासमोर एका क्लिकने समोर येतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचतो आणि अधिक गोष्टी शिकण्याची संधी मिळते. विशेषतः ग्रामीण आणि मर्यादित साधनसामग्री असलेल्या भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही साधने एक मोठी संधी ठरत आहेत.

स्व-अभ्यासाची वाढती संधी

आज शाळा- महाविद्यालयांत डिजिटल शिक्षणावर भर दिला जात आहे. मोबाइल, टॅबलेटच्या माध्यमातून विद्यार्थी स्वतः शिकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

एआयमुळे स्व-अभ्यास ही संकल्पना अधिक मजबूत होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी फक्त परीक्षेसाठी नाही, तर खऱ्या अर्थाने समजून घेण्यासाठी अभ्यास करू लागतात.

सर्जनशीलतेला चालना

एआय विद्यार्थ्यांना केवळ माहिती देत नाही तर त्यांना विचार करायला लावते. उदाहरणे, स्पष्टीकरणे आणि सराव प्रश्नांद्वारे शिकण्याची प्रक्रिया अधिक रंजक बनते. निबंध लेखन, भाषण, प्रोजेक्ट्स यामध्ये विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता वाढण्यास मदत होते. विद्यार्थी एआयच्या मदतीने इंग्रजीसारख्या भाषांमध्ये आत्मविश्वासाने लिहू लागलेत. इंग्रजी बोलू लागले आहेत. काही विद्यार्थी वेगवेगळे कोर्सेस आणि भाषा शिकताना दिसत आहेत.

विचारशक्तीवरील परिणाम

मात्र, या सर्व सकारात्मक बदलांसोबत काही गंभीर प्रश्नही निर्माण होत आहेत. सर्वांत मोठा धोका म्हणजे विद्यार्थ्यांची स्वतः विचार करण्याची क्षमता कमी होण्याची शक्यता. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर लगेच मिळाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये शोध घेण्याची आणि मेहनत करण्याची सवय कमी होऊ शकते.

माहितीची अचूकता आणि गैरवापर

AI ने दिलेली माहिती नेहमीच अचूक असेल असे नाही. काही वेळा चुकीची किंवा अपूर्ण माहितीही मिळू शकते. परीक्षांमध्ये एआयचा गैरवापर होण्याची शक्यता देखील शिक्षण व्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान बनत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कुठलीही माहिती ही अचूक आहे की नाही हे तपासून बघितले पाहिजे.

योग्य वापराची गरज

आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे संतुलन राखणे. एआयचा वापर हा शिक्षक आणि पुस्तकांचा पर्याय म्हणून नाही, तर पूरक साधन म्हणून केला पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी एआयकडून मिळालेली माहिती समजून घेणे, पडताळून पाहणे आणि स्वतःच्या शब्दांत मांडणे ही सवय विकसित केली पाहिजे.

- इंजि. अविनाश जाधव
(एआय अँड टेक एज्युकेटर)

Artificial Intelligence is reshaping education by making learning faster, smarter, and more accessible. While tools like ChatGPT empower students with instant knowledge and creativity, overdependence can weaken critical thinking. The real success lies in using AI as a guide, not a replacement.

Moral : Balance between technology and thinking is the key to true learning.

भविष्यासाठीची आपली तयारी

तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर शिकवणे ही आजच्या शिक्षणाची गरज बनली आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांना AI चा जबाबदारीने वापर कसा करावा, याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. भविष्यात 'एआय साक्षरता' ही एक महत्त्वाची कौशल्य ठरणार आहे.

कुपन क्र. ७७

प्रश्न : भविष्यात कोणते कौशल्य महत्त्वाचे ठरणार आहे ?

१. एआय साक्षरता ☐
२. अभ्यास ☐
३. वाचन ☐

सानिका शिंदेला भरतनाट्यम् सुवर्णपदक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या २०२५ च्या प्रायोगिक कला (नृत्य-भरतनाट्यम्) पदव्युत्तर पदवी (एमए) परीक्षेत मुंबईच्या भरत कॉलेज ऑफ फाईन आर्टस् अँड कल्चरची विद्यार्थिनी सानिका दिलीप शिंदे ही विश्वविद्यालयात प्रथम श्रेणीत प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाली. तिच्या या यशाबद्दल तिला 'आचार्य पार्वतीकुमार स्मृती सुवर्णपदक' देऊन सन्मानित करण्यात आले. सानिका ही संगीत नाटक अकादमीच्या अध्यक्षा डॉ. संध्या पुरेचा यांची शिष्या आहे.

कला (नृत्य-भरतनाट्यम्) पदव्युत्तर पदवी परीक्षेत भरत कॉलेज ऑफ फाईन आर्टस् अँड कल्चरची विद्यार्थिनी सानिका शिंदे ही प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाली. तिचा 'आचार्य पार्वतीकुमार स्मृती सुवर्णपदक' देऊन सन्मान करण्यात आला.

रामटेक येथे झालेल्या दीक्षांत समारंभात प्रमुख अतिथी प्रा. गणपती यादव यांच्या हस्ते सानिका हिला सुवर्णपदक, प्रमाणपत्र व स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य हे होते. सानिका ही ज्येष्ठ सनदी अधिकारी दिलीप शिंदे आणि अभिनेत्री रूपलक्ष्मी यांची कन्या आहे. दीक्षांत सोहळ्यास कुलसचिव डॉ. अलोने, परीक्षा नियंत्रक डॉ. केशव मोहरीर, कवयित्री डॉ. आशा भालचंद्र पांडे, राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे, माजी राज्य सेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे उपस्थित होते.

'एनएससीआय'ला १२.६६ कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना काळात नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया (एनएससीआय)च्या जागेचा जम्बो कोरोना क्वारंटाइन सेंटर म्हणून वापर केल्याच्या वादात न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १२.६६ कोटींची टोकन रक्कम, वार्षिक ५ टक्के व्याजासह जमा करण्यात आल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली.

न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने महापालिकेचे म्हणणे नोंदवून घेतले. एनएससीआयला दोन आठवड्यात ही रक्कम काढण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली. मात्र, एनएससीआयच्या अतिरिक्त १८,२०५.४२ चौ. मी. मोकळ्या जागेच्या मोबदल्याबाबतच्या मुद्द्यावर सहा आठवड्यांनंतर सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यापूर्वी न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठाने महापालिकेने चुकीचा हिशेब केल्याची नोंद घेत १२.६६ कोटींची भरपाई कशी ठरवली, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते.

एनएससीआयचे म्हणणे... : एनएससीआयने जवळपास ४० कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली आहे. एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२२ या ३० महिन्यांत त्यांच्या जागेचा कोरोना सेंटर म्हणून वापर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. आपत्कालीन परिस्थितीत खासगी जागांचा वापर केल्यास भरपाई दिली जाईल, असे परिपत्रक पालिकेने काढले होते.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्यावर शस्त्रक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे पुणे येथील रुबी हॉल क्लिनिक ह्या खासगी इस्पितळात दाखल झाले आहेत.

त्यांच्या छातीत किंचित दुखत होते व त्यामुळे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी एंजिओग्राफी प्रक्रिया केली. त्यांना छातीत एकच छोटा ब्लॉक आढळल्यानंतर यशस्वी पद्धतीने उपचार करण्यात आले. एंजिओप्लास्टी करण्यात आली. मुख्यमंत्री डॉ सावंत हे आता पूर्ण ठिक आहेत.

बंगालमध्ये ५०हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून ममता बॅनर्जी यांचा संताप -८

पश्चिम रेल्वे

टीएडीके ऐवजी ८ अटेंडंटची नियुक्ती करणे

उपमुख्य सामग्री प्रबंधक, कॅरेज रिपेअर वर्कशॉप, लोवर परेल मुंबई-४०००१३ **निविदा क्र.: टीएडीके_हायरिंग_एलपीएल,दिनांक: १३.०३.२०२६ मागवित आहे. लघु विवरण:** पश्चिम रेल्वे लोअर परेल मध्ये ऑफिसर्स वर्किंगकरिता २४ महिन्याच्या अवधीकरिता टीएडीके ऐवजी ८ अटेंडंटची नियुक्ती करणे. **निविदा मात्रा:** १९२.०० मनुष्य-महिना **एकूण मूल्य:** ७३,७९,६३७/-. **नियत तारीख:** १३.०४.२०२६.
1235

आम्हाला लाईक करा facebook.com/WesternRly

बेस्ट युनियन प्रलंबित मागण्यांवरून आक्रमक, २४ मार्चपर्यंत निर्णय घ्या!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बेस्ट वर्कर्स युनियन आणि संघर्ष कर्मचारी संघटनेने नोव्हेंबरमध्ये उपोषण केले होते. त्यावेळी 'बेस्ट'चे महाव्यवस्थापक यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले. मात्र, मागण्यांवर तीन महिन्यांत निर्णय होऊ शकलेला नाही. येत्या २४ मार्चपर्यंत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय कामगारांनी घेतला आहे.

बेस्ट वर्कर्स युनियनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. बेस्ट प्रशासनाच्या नकारात्मक धोरणामुळे संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांप्रश्नी मार्ग काढावा, अशी विनंती त्यांना युनियनने केली आहे. पालिका व 'बेस्ट'च्या अधिकाऱ्यांना युनियन आणि संघर्ष कामगार कर्मचारी युनियनबरोबर तातडीने चर्चा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही मागणी केली आहे.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या

महापालिका समकक्ष वेतनमान या सूत्रावर आधारित सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची संपूर्ण व योग्य अंमलबजावणी, याचा समावेश असलेला वेतन करार तातडीने करावा.

पदोन्नती, रिक्त जागा, अंतिम देयके, अनुकंपा तत्त्वावरील नोकऱ्या आणि इतर प्रश्नांवर निर्णय घ्यावा.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटीची पूर्ण रक्कम तातडीने द्यावी.

कंत्राटदारांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 'बेस्ट'च्या बसगाड्यांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत 'समान कामाला समान वेतन' तत्त्वाची अंमलबजावणी करून पूर्वलक्षी प्रभावाने थकबाकी द्यावी.

'बेस्ट'चा स्वमालकीचा ३,३३७ बस ताफा राखण्यासाठी, म्हणजेच आयुष्यमान संपलेल्या बसगाड्यांच्या बदल्यात नवीन घेण्यासाठी आवश्यक आर्थिक निधी पालिकेने 'बेस्ट'ला मंजूर करावा.

पालिकेच्या बेस्ट उपक्रमाशी संबंधित 'क' अर्थसंकल्पाचे विलिनीकरण पालिकेच्या "अ" अर्थसंकल्पात तातडीने करावे.

தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்
तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Tamil Nadu
(Established by an Act of Parliament, 2009)
Neelakudi, Thiruvarur Tamil Nadu

டெண்டர் அறிவிப்பு / निविदा सूचना / Tender Notice

1. Supply and Installation of Laboratory Instrument High Speed Spinning Disk Confocal Super Resolution Microscope for Department of Biotechnology at CUTN, Thiruvarur.
2. Supply and Installation of UAV-Based LiDAR and Multispectral Scanning System for Department of Geography at CUTN, Thiruvarur.
3. Supply and Installation of Laboratory Instrument Field Emission Scanning Electron Microscope with EDS System for Department of Materials Science at CUTN, Thiruvarur.
4. Supply and Installation of Laboratory Instrument, High Resolution Mass Spectrometer with NANO-LC / UHPLC for Proteomics Metabolomics and Lipidomic Applications- 01 No and Triple Quad GC*GC/MSMS for Volatile, Pesticides, Metabolomics Application and Other Academic Chemistry Applications - 01 No. for Department of Horticulture at CUTN, Thiruvarur.

டெண்டர் குறிப்பு எண் / निविदा संदर्भ सं./ Tender Ref. No.:	இறுதி தேதி & நேரம் / अंतिम तिथि एवं समय / Last date & Time:
1. CUTN/PUR/2025-26/28 dt.13.03.2026 2. CUTN/PUR/2025-26/29 dt.13.03.2026 3. CUTN/PUR/2025-26/30 dt.13.03.2026 4. CUTN/PUR/2025-26/32 dt.13.03.2026	Please see the CUTN website https://cutn.ac.in/tenders

குறிப்பு / टिप्पणी / Note:
மேலும் விவரங்களுக்கு CUTN இணையதளம் மற்றும் CPP போர்டல் பார்க்கவும்.
अधिक जानकारी के लिए कृपया तकेंवि की वेबसाइट www.cutn.ac.in और सीपीपी पोर्टल देखें।
For more details, please see the CUTN website www.cutn.ac.in and CPP portal.

-sd-
cbc 21299/12/0024/2526 பதிவாளர் /कुलसचिव/REGISTRAR

पश्चिम रेल्वे विशेष गाड्यांच्या फेऱ्या (ट्रिप्स) वाढविणार

गाडी क्र.	पासून	पर्यंत	धावण्याचा दिवस	विस्तारित पर्यंत
०९२०७	बांद्रा टर्मिनस	भावनगर टी.	शुक्रवार	३१.०७.२०२६
०९२०८	भावनगर	टी.बांद्रा टर्मिनस	गुरुवार	३०.०७.२०२६
०९४१५	बांद्रा टर्मिनस	गांधीधाम	गुरुवार	३०.०७.२०२६
०९४१६	गांधीधाम	बांद्रा टर्मिनस	गुरुवार	३०.०७.२०२६
०९०५५	बांद्रा टर्मिनस	उधना	सोम, मंगळ, बुध, गुरु व रवि.	२९.०७.२०२६
०९०५६	उधना	बांद्रा टर्मिनस	सोम, मंगळ, बुध, शनि व रवि.	२९.०७.२०२६
०९०३५	बांद्रा टर्मिनस	उधना	शुक्र, शनि.	३१.०७.२०२६
०९०३६	उधना	बांद्रा टर्मिनस	गुरु, शुक्र.	३०.०७.२०२६
०९०३७	बांद्रा टर्मिनस	भुज	गुरु, शनि.	३०.०७.२०२६
०९०३८	भुज	बांद्रा टर्मिनस	शुक्र, रवि.	३१.०७.२०२६
०९००९	बांद्रा टर्मिनस	भुज	रविवार	२६.०७.२०२६
०९०१०	भुज	बांद्रा टर्मिनस	सोमवार	२७.०७.२०२६
०९०११	बांद्रा टर्मिनस	भुज	मंगळवार	२८.०७.२०२६
०९०१२	भुज	बांद्रा टर्मिनस	बुधवार	२९.०७.२०२६
०९०१७	बांद्रा टर्मिनस	वेरावल	रविवार	२६.०७.२०२६
०९०१८	वेरावल	बांद्रा टर्मिनस	सोमवार	२७.०७.२०२६

वेळ, हॉल्ट्स आणि संरचनेशी संबंधित सविस्तर माहितीकरिता, प्रवासांनी कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in वर भेट द्यावी.

वरिल सर्व गाडयांच्या विस्तारित फेऱ्यांची बुकिंग दि. २०.०३.२०२६ पासून पीआरएस काउंटर्सवर आणि आयआरसीटीसी वेबसाइटवर सुरु होईल. उपरोक्त गाडया विशेष भाड्या(फेअर)वर विशेष गाडी म्हणून धावेल.

पश्चिम रेल्वे
wr.indianrailways.gov.in
आम्हाला लाईक करा आणि आम्हाला फॉलो करा
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सर्व आरक्षित तिकिटांकरिता मूळ ओळख-पत्र सोबत ठेवा.

दीक्षांत समारोहः 645 विद्यार्थियों को उपाधियां, 15 को स्वर्ण पदक

राज्यपाल ने कहा - दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, नवजीवन की शुरूआत है

नवज्योति/जोधपुर। एमबीएम विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह बुधवार को भव्यता और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने की। इस अवसर पर कुल 645 विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान की गईं, जिनमें पांच पीएचडी डिग्रियाँ भी शामिल थीं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 15 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षांत का मतलब शिक्षा का अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन के एक नए अध्याय की शुरूआत है। उन्होंने कहा, ह्लकिताबों तक सीमित रहकर सफलता को मापना पर्याप्त नहीं है। असली परीक्षा अब शुरू होती है। अपने ज्ञान के साथ आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय विकसित करें।ह्व राज्यपाल ने विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण, प्रशासनिक सेवाओं और समाज की भलाई में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षकों से भी अनुरोध किया कि वे विद्यार्थियों को केवल डिग्री धारक न बनाएं, बल्कि जिम्मेदार और प्रतिभाशाली नागरिक तैयार करें। उन्होंने आगे कहा कि कई युवा स्नातक होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं से डरते हैं, लेकिन असली सफलता केवल हिम्मत और आत्मबल से ही हासिल की जा सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री के ह्यजॉब क्रिएटर बनो, जॉब सीकर नहींह्ल के विचार का उल्लेख किया और कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को देश और समाज की प्रगति में भाग लेने के लिए तैयार करे।

इस अवसर पर डॉ. प्रदीप कुमार को उनकी शोध विषय ह्लमैन्युफैक्चरिंग में सतत प्रथाओं का अध्ययनह्ल के लिए पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने प्रोफेसर मिलिंद कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में यह शोध कार्य पूर्ण किया। डॉ. प्रदीप ने कहा कि यह डिग्री समाज और देश के लिए योगदान का अवसर है। समारोह के अंत में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को नामांकन बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देने का सुझाव दिया।

एक नजर में

बी.ई. में 539 उपाधियां (13 स्वर्ण पदक), बी.आर्क में 28 उपाधियां (1 स्वर्ण पदक), एम.ई. 42, एम.सी.ए. 31 उपाधियाँ (1 स्वर्ण पदक) पीएचडी 5 डिग्रियां, स्वर्ण पदक विजेताओं में प्रांजल शर्मा (प्रोडक्शन इंजीनियरिंग), आकृति शर्मा (माइनिंग) और अदिति शर्मा (आर्किटेक्चर) प्रमुख रही।

उपलब्धियों का श्रेय माता-पिता और मार्गदर्शकों को दिया

प्रांजल शर्मा वर्तमान में IIT बॉम्बे में M.Tec कर रही हैं और तकनीकी क्षेत्र में देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। अदिति शर्मा IIT खड़गपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और टाउन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के जरिए समाज सेवा में योगदान देना चाहती हैं। आकृति शर्मा ने बताया कि वे माइनिंग क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं पर काम करेंगी।

DNA 386829

फसल छिडकाव के बाद कृषक की बिगड़ी तबीयत, मौत

जोधपुर। शहर के निकट करवड़ क्षेत्र में एक कृषक की फसल पर दवाई छिडकाव के बाद तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर बाद में उसकी मौत हो गई। उसके भाई की तरफ से पुलिस में मर्ग की रिपोर्ट दी गई। करवड़ पुलिस ने बताया कि अतुणावेश केरू निवासी मूलाराम पुत्र प्रेमाराम माली की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसका भाई कैलाश रात को करवड़ में फसल पर दवाई छिडकाव के बाद खेत से बाहर निकला था। तब उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। पता लगने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। मगर उसकी मौत हो गई।

स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी तेज, वार्डों पर फोकस

जोधपुर/नवज्योति। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 को लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को आयोजित वार्ड प्रभारियों की बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया तथा रैंकिंग सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बैठक में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने, नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने और व्यावसायिक क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी वार्ड में कचरा जमा नहीं होना चाहिए और सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासकर बाजार क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखने और नियमित सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को साफ-सुथरा वातावरण मिल सके। साथ ही स्वच्छता के प्रति नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में उपायुक्त स्वरूप सिंह और स्वास्थ्य अधिकारी सचिन मौर्य मौजूद रहे। उन्होंने वार्ड प्रभारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण के निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करने और जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। नगर निगम प्रशासन के अनुसार इस बार सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी स्तरों पर समन्वय के साथ काम किया जाएगा। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे, ताकि जोधपुर की रैंकिंग में सुधार हो सके।

रैंकिंग सुधार के लिए सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश

रात की चुप्पी में घर में घुसपैठ, पॉक्सो केस ने खोली लापरवाही की परतें

बालकनी से घर में घुसा युवक, सुरक्षा पर उठे सवाल

नवज्योति/जोधपुर। जोधपुर के जिला पूर्व क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। आरोप है कि पड़ोसी युवक रात के समय बालकनी कूदकर घर में घुस गया। यानी मकान की संरचना और निगरानी दोनों कमजोर साबित हुई। परिजन की रिपोर्ट पर पॉक्सो में मामला दर्ज हुआ, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है। सवाल यह भी कि घटना के बाद तुरंत गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस की प्रतिक्रिया धीमी रही? इस मामले ने शहरी कॉलोनियों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। न तो सीसीटीवी, न गार्ड और न ही पड़ोस की सतर्कता—यही कारण है कि आरोपी बेखौफ घर में घुस गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब अपराधी को पकड़ का डर नहीं होता। यह भी जांच का विषय है कि आरोपी पहले से नाबालिग को टारगेट कर रहा था या यह अचानक की घटना थी। अब पुलिस जांच कर रही है, लेकिन असली सवाल है—क्या इस घटना के बाद कॉलोनियों में सुरक्षा बढ़ेगी या मामला फाइलों में दब जाएगा?

फैक्ट्री में मौत, काम के हालात कटघरे में

श्रमिक की मौत के पीछे बीमारी या सिस्टम की लापरवाही?

बासनी औद्योगिक क्षेत्र की हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में श्रमिक की मौत ने काम के हालात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 42 वर्षीय प्रतापराम की अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाने के बाद मौत हो गई। मामले में मर्ग दर्ज है, लेकिन यह जांच जरूरी है कि फैक्ट्री में काम का माहौल कैसा था। क्या पर्याप्त सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद थीं? क्या श्रमिकों की नियमित मेडिकल जांच होती थी? अक्सर औद्योगिक क्षेत्रों में लंबे समय तक काम, धूल-धुआं और दबाव के कारण श्रमिकों की हालत बिगड़ती है। ऐसे में यह सिर्फ अचानक तबीयत खराब का मामला नहीं माना जा सकता। परिजन का दर्द अलग है, लेकिन सिस्टम की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। क्या फैक्ट्री प्रबंधन ने समय पर इलाज कराया? क्या एम्बुलेंस या प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी? जांच के बाद ही साफ होगा कि यह प्राकृतिक मौत थी या लापरवाही की कीमत।

एमआर की खुदकुशी, ब्लैकमेल का एंगल

सुसाइड नोट नहीं, लेकिन आरोप गंभीर—क्या मानसिक दबाव बना मौत की वजह?

झालामंड क्षेत्र में एमआर सिमरनजीत की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किराए के मकान में फंदा लगाकर जान देने के पीछे पिता ने एक महिला द्वारा ब्लैकमेल और परेशान करने का आरोप लगाया है। सबसे बड़ा सवाल—अगर इतना मानसिक दबाव था तो कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? क्या फोन या सोशल मीडिया में कोई सुराग है? पुलिस अभी महिला की तलाश कर रही है, लेकिन जांच का दायरा बड़ा होना चाहिए। क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत विवाद था या किसी बड़े नेटवर्क का मामला? एमआर जैसे प्रोफेशन में तनाव आम है, लेकिन अगर ब्लैकमेल का एंगल सच है तो यह गंभीर अपराध है। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल ब्लैकमेल के खतरे को भी उजागर करती है। अब देखना होगा कि जांच सच्चाई तक पहुंचती है या मामला आरोपों में ही उलझ कर रह जाता है।

पुलिस पर हमला, कानून का डर खत्म?

साउंड बंद कराने गई टीम पर हमला, बस्ती में बढ़ती बेखौफी उजागर

रातानाडा के केसर बाग हरिजन बस्ती में पुलिस टीम पर हमला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि कानून के डर खत्म होने का संकेत है। तेज साउंड बंद कराने पहुंची टीम पर युवकों ने लाठी-पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें सबइंस्पेक्टर सहित तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। सबसे गंभीर बात—वर्दी फाड़ दी गई, यानी पुलिस की साख पर सीधा हमला। घटना के बाद तीन युवकों को शांतिभंग में पकड़ा गया, लेकिन बड़ा सवाल है—क्या इतनी बड़ी घटना में सिर्फ यही कार्रवाई काफी है? यह भी जांच का विषय है कि क्या बस्ती में पहले से अवैध गतिविधियां या असामाजिक तत्व सक्रिय हैं? पुलिस को सूचना थी, फिर भी पर्याप्त बल क्यों नहीं था? इस घटना ने साफ कर दिया कि कानून का डर कमजोर हो रहा है। अगर पुलिस पर ही हमला होने लगे, तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? अब जरूरत है सख्त कार्रवाई की, ताकि ऐसे मामलों में स्पष्ट संदेश जाए—कानून से ऊपर कोई नहीं।

साल से फाइलों में कैद हैरिटेज पाथ 2.07 करोड़ की योजना पर जेडीए मौन

नवज्योति/जोधपुर। भीतरी शहर के ऐतिहासिक स्थलों को एक सूत्र में पिरोकर पर्यटन को नई पहचान देने का दावा करने वाली 2.07 करोड़ की हैरिटेज पाथ योजना पिछले 8 साल से सरकारी फाइलों में दफन पड़ी है। 2018 में बड़े दावों के साथ घोषित इस योजना का आज तक न तो निर्माण शुरू हुआ और न ही कोई जिम्मेदार सामने आया। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने करीब 2 किलोमीटर लंबा यह मार्ग माणक चौक से तूरजी का झालरा, चौहानजी का नोहरा, लायकान मस्जिद होते हुए किल्लीखाना तक जोधपुर स्टोन से विकसित करने का खाका तैयार किया था। इसे दो चरणों में पूरा करने की योजना थी। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक एक ईंट तक नहीं रखी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वर्तमान अधिकारियों को इस योजना की जानकारी तक नहीं है। यानी करोड़ों की परियोजना बिना जवाबदेही के धूल खा रही है। पूर्व पार्षदों ने कई बार इस योजना को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन हर बार मामला सिर्फ आश्वासन तक सीमित रहा। जेडीए ने सिविल कार्य जल्द शुरू करने के दावे किए थे, लेकिन वर्षों बीतने के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। न बजट में प्राथमिकता मिली और न ही कार्ययोजना पर अमल हुआ। सवाल यह उठता है कि जब योजना घोषित हुई थी तो फिर उसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? और अगर जिम्मेदार तय थे, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

पर्यटन बढ़ाने का दावा, जमीन पर शून्य काम; अफसरों को तक नहीं जानकारी

यह लापरवाही केवल एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि जोधपुर के पर्यटन विकास पर सीधा असर डाल रही है। अगर यह हैरिटेज पाथ बनता तो भीतरी शहर के प्रमुख स्थल—फतेहपोल, सिंह पोल, अचलनाथ मंदिर, तूरजी का झालरा, घंटाघर और किल्लीखाना—एक ही पैदल मार्ग से जुड़ जाते। इससे पर्यटकों को पुरानी नगरी की विरासत करीब से देखने का मौका मिलता और स्थानीय व्यापार को भी नया संबल मिलता। लेकिन अफसरशाही की सुस्ती और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी ने इस महत्वाकांक्षी योजना को कागजों तक सीमित कर दिया। शहर के बीचों-बीच पर्यटन का बड़ा अवसर यूं ही बर्बाद हो रहा है।

अब सवाल यही है—क्या यह योजना कभी जमीन पर उतरेगी या फिर हमेशा के लिए फाइलों में ही दबी रह जाएगी? जवाब जेडीए और प्रशासन को देना।

कमठा मजदूर की बाइक चुराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

नवज्योति/जोधपुर। शहर के बासनी सरस्वती नगर डी सेक्टर में कमठा मजदूर की बाइक चुराने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बाइक को जब्त किया है। एक आरोपी के खिलाफ लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट सहित पांच प्रकरण सामने आए है। अभियुक्तों से पूछताछ जारी है। भगत की कोठी थानाधिकारी सुरेश विश्नोई ने बताया कि रामेश्वर नगर निवासी जसवंत सिंह पुत्र भवानी सिंह की बाइक बासनी सरस्वती नगर डी सेक्टर से एक पार्क के सामने से चोरी हुई थी, जिस बारे में रिपोर्ट दी गई थी। वह कमठा मजदूरी करता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजों की जांच के बाद अब दो आरोपियों नागौर के पादुकला हाल कुड़ी सेक्टर 4 निवासी रजनी कुमार उर्फ पप्पू पुत्र प्रहलादराम एवं संत नगर मंगलनगर गुढ़ा विश्नोईयान निवासी राजूराम पुत्र गंगाराम को गिरफ्तार किया है। आरोपी रजनी कुमार के खिलाफ पहले से ही लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज है। पकड़े गए आरोपियों से वाहन चोरी की अन्य घटनाओं के बारे भी पता लगाया जा रहा है।

DNA 391215

पुरानी मशीन हटेगी, नई 3 टेस्ला तकनीक से मरीजों को मिलेगा तेज और सटीक इलाज

अब रात-दिन मिलेगी एमआरआई-सीटी स्कैन सुविधा, एमडीएम में बड़ा बदलाव

नवज्योति / जोधपुर। मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल में अब मरीजों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब यहां 24 घंटे एमआरआई और सीटी स्कैन जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी मरीजों को अब जांच के लिए दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और गंभीर स्थिति में तुरंत जांच संभव हो सकेगी। अस्पताल अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित के निर्देश पर रेडियोडायग्नोसिस विभाग को यह व्यवस्था जल्द लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इसके तहत विभाग ने 24 घंटे सेवा शुरू करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त मांग भी भेजी है। जानकारी के अनुसार यह स्टाफ जल्द उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बाद न्यू डायग्नोस्टिक विंग में दिन-रात जांच शुरू हो जाएगी।

वर्तमान में एमडीएम अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा केवल सुबह और शाम की शिफ्ट तक सीमित है, जिससे कई बार मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। खासकर आपातकालीन मामलों में यह देरी गंभीर साबित होती थी। अब 24 घंटे सेवा शुरू होने से मरीज अपनी सुविधा अनुसार जांच करवा सकेंगे और उपचार में देरी नहीं होगी। अधीक्षक डॉ. राजपुरोहित लगातार अस्पताल में सुधार के नए प्रयोग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक सतर्कता टीम बनाने की पहल भी की है, जिसका उद्देश्य मरीजों से अवैध वसूली और अनैतिक मांगों पर रोक लगाना है। यह टीम मरीजों और परिजनों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को समझेगी और शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इसी कड़ी में अब एमआरआई और सीटी स्कैन सुविधा को 24 घंटे करने का निर्णय भी मरीजों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही अस्पताल में तकनीकी उन्नयन भी किया जा रहा है। वर्तमान में कार्यरत 10 से 15 साल पुरानी एमआरआई मशीन की अवधि 9 अप्रैल को पूरी हो रही है, जिसके बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। उसकी जगह नई अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन लगाई जाएगी, जो कम समय में अधिक सटीक और उच्च गुणवत्ता के परिणाम देने में सक्षम होगी। इस नई व्यवस्था से न केवल जांच प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि मरीजों को बेहतर इलाज भी मिल सकेगा। एमडीएम अस्पताल में हो रहे ये बदलाव सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं।

तेल-गैस क्षेत्रों पर हमले

ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड और असालुयेह शहर की तेल गैस सुविधाओं पर हुए इजराइली हमलों के बाद पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने अब खतरनाक मोड ले गया है। हमले में गैस और तेल के साथ पेट्रोकेमिकल और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले हुए। ऐसे में यह केवल एक सैन्य कार्यवाही नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, भू-राजनीति और क्षेत्रीय स्थिरता पर गहरा प्रभाव डालने वाली घटना है। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है जिसे ईरान और कतर साझा करते हैं। यह ईरान की लगभग 80 फीसदी गैस आपूर्ति का स्रोत है। जो बिजली, उद्योग और घरेलू ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इस गैस फील्ड से

वैश्विक स्तर पर करीब 20 फीसदी गैस आपूर्ति होती है इसे उसकी आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रहार माना जा रहा है। इसके जरिए वह अपनी सैन्य रणनीति को मजबूत करता है। इस हमले का उद्देश्य ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव के रूप में और उसके घरेलू असंतोष को उकसाने वाला कदम हो सकता है। इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने खाड़ी देशों-कतर के रास लाफान गैस क्षेत्र, यूएई के अल हसन, सऊदी अरब के रासनबुरा और आरामको रिफाइनरी क्षेत्र और कुवैत के मीना अल अहमदी और अब्दुल्ला क्षेत्रों की रिफाइनरियों पर मिसाइल हमले बोल दिए। जिसकी वजह से पश्चिमी एशिया क्षेत्र में बेहद तनाव की स्थिति बन गई है। कतर ने इजराइल की कार्यवाही की आलोचना की है। तो अमेरिका ने खुद को हमले से अलग बताया लेकिन चेतावनी दी है। यह संकेत देता है कि संघर्ष बहु-देशीय युद्ध में तेजी से बदल सकता है। अमेरिका ने होर्मुज के पास ईरानी मिसाइल ठिकानों को नष्ट करने के लिए 5,000 पाउंड के गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया। इस हमले का असर तुरंत वैश्विक स्तर पर दिखा। कच्चे तेल की कीमतें 118 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई। यूरोप में गैस कीमतें 30 फीसदी तक बढ़ीं। इराक जैसे देशों में गैस आपूर्ति रुक गई है। भारत के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। यदि यह संकट बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज बंद होने का खतरा बन गया है जिससे ऊर्जा संकट और भीषण होगा। जिसके असर से भारत जैसे आयातक देशों पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा। खाड़ी देश अब सीधे संघर्ष में खिंच सकते हैं जिससे जीसीसी देशों की सुरक्षा चुनौती बढ़ेगी और

वैश्विक व्यापार मार्ग खतरे में पड़ जाएंगे। जहां तक भारत का सवाल है, पश्चिम एशिया संघर्ष के मौजूदा हाल से तेल-गैस संकट बढ़ने के साथ इसके दामों में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ सकती है। ऊर्जा आपूर्ति तो बाधित होगी ही, इसके साथ खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। ऐसे में उसे अपने मित्र देशों-ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना काफी कठिन होगा।

गैस फील्ड पर हमला वैश्विक ऊर्जा राजनीति में बड़ा मोड है। इससे स्पष्ट है कि आधुनिक युद्ध अब ऊर्जा हथियार के रूप लड़ा जा रहा है।

यदि यह संघर्ष जारी रहता है, तो यह वैश्विक मंदी, ऊर्जा संकट और व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ सकता है।

गौरैया अब कस्बों और शहरों से गायब हो रही हैं

प्रकृति की नन्ही दूत गौरैया का संरक्षण जरूरी

दिवस विशेष

गौरैया की संख्या में कमी के पीछे के कारणों में आहार की कमी, बढ़ता आवासीय संकट, कीटनाशक का व्यापक प्रयोग, जीवन शैली में बदलाव, प्रदूषण और मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन को दोषी बताया जाता रहा है। भारत में पक्षियों की कुल मिलाकर 1250 प्रजातियां हैं। जिनमें से 85 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं।

विश्व गौरैया दिवस नन्ही घरेलू गौरैया और अन्य पक्षियों को समर्पित है। गौरैया की संख्या में हो रही तीव्र गिरावट के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को इन परिचित पक्षियों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनके लिए हमारे आस पास का माहौल बेहतर करना है। विश्व गौरैया दिवस 2026 एक बार फिर दुनिया को याद दिलाएगा कि आम पक्षियों को भी देखभाल और ध्यान की आवश्यकता है। कभी उपेक्षित समझी जाने वाली गौरैया अब कई कस्बों और शहरों से गायब हो रही हैं, जो इस दिन को रोजमर्रा की जैव विविधता और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के प्रति चिंता का प्रतीक बनाती है।

गौरैया की मधुर चहचहाहट

गौरैया की मधुर चहचहाहट सुबह और शाम के जीवन का अभिन्न अंग रही है। गौरैया छोटे, फुर्तीले पक्षी होते हैं जो 4 से 7 इंच तक लम्बे होते हैं। उनके गोल, मोटा शरीर और छोटी मजबूत चोंच होती हैं जो खुले बीजों को तोड़ने के लिए उपयुक्त होती हैं। उनके पंखों पर धारियां या गहरे रंग के धब्बे होते हैं। यह हल्की भूरे रंग या सफेद रंग में होती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे पंख और पीली चोंच व पैरों का रंग पीला होता है। जब बच्चा कुछ समझने लगता है तो सर्वप्रथम उसको घर के आंगन में सबसे अधिक जो पक्षी देखने को मिलता है वह नन्ही चिड़िया यानी गौरैया होती है। यह चिड़िया बचपन से ही हमारी साथी बन जाती है जो बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और अपनी मीठी आवाज से उन्हें आकर्षित करती रहती है। गांव देहातों में यह आज भी देखने को मिल जाता है। मगर शहरों में अब ऐसा नजारा शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा।

कम होती संख्या पर चिन्ता

गौरैया मनुष्य के आसपास रहना पसंद करती है। यह लगभग हर तरह की जलवायु पसंद करती है पर पहाड़ी स्थानों में कम दिखाई देती है। नर गौरैया के सिर का ऊपरी भाग नीचे का भाग और गालों पर पर भूरे रंग का होता है। गला चोंच और आंखों पर काला रंग होता है और पैर भूरे होते है। मादा के सिर और गले पर भूरा रंग नहीं होता है। नर गौरैया को चिड़ा और मादा चिड़ी या चिड़िया भी कहते हैं। गौरैया पक्षियों के पैसर वंश की एक जीव वैज्ञानिक जाति है जो विश्व के अधिकांश भागों में पाई जाती है। आरम्भ में यह एशिया, यूरोप और भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती थी। लेकिन मानवों ने इसे विश्वभर में फैला दिया है। यह मनुष्यों के समीप कई स्थानों में रहती हैं। पिछले कुछ सालों में शहरों में गौरैया की कम होती संख्या पर चिन्ता प्रकट की जा रही है।

प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी

जीवन की भाग दौड़ में किसी का ध्यान इनकी घाटी संख्या की तरफ नहीं जा रहा है। बच्चों की सबसे नजदीकी मित्र गौरैया जिस तेजी से कम होती जा रही है उससे लगता है आने वाले समय में यह कहीं विलुप्त ना हो जाए। इसलिए हम सबको मिलकर गंभीरता से ऐसे प्रयास करने चाहिए, जिससे गौरैया को संरक्षण मिल सके और उनकी संख्या में फिर से बढ़ोतरी प्रारंभ हो सके। गौरैया चिड़िया को घरेलू चिड़िया भी कहा जाता है। क्योंकि यह घरों के अंदर भी घोसले बनकर रह लेती है। ये मानव और प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि यह कीड़ों को खाती है जिससे कीड़े पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा धर्मशास्त्र के मुताबिक गौरैया का आना आपके लिए शुभ होता है। जानकारों का कहना हैं कि यह चिड़िया शांति और सदभावना का संदेश लेकर आती है।

टावर से निकलने वाले रेडिएशन

गौरैया की आबादी में करीब 60 फीसदी की कमी आई है। यह कमी ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में हुई है। पश्चिमी देशों में हुए अध्ययनों के अनुसार गौरैया की आबादी घटकर खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर दिल्ली सरकार ने 2012 और बिहार सरकार ने 2013 से गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित कर रखा है। कभी हमारे घर आंगन में गिरे अनाज को खाने गौरैया फुर्र से आती थी और दाना चुगकर उड़ जाती थी। हालांकि गांवों में आज भी कई घरों में गौरैया आ रही है। गौरैया की संख्या में कमी के पीछे कई कारण हैं जिन पर लगातार शोध हो रहे हैं। गौरैया की संख्या में कमी के पीछे के कारणों में आहार की कमी, बढ़ता आवासीय संकट, कीटनाशक का व्यापक प्रयोग, जीवन शैली में बदलाव, प्रदूषण और मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन को दोषी बताया जाता रहा है।

हमारे जीवन के लिए अहम है

गौरैया की संख्या में कमी के पीछे बेतहाशा कीटनाशक का प्रयोग को माना जा रहा है। गौरैया के प्रजनन के लिए अनुकूल आवास में कमी को भी इसकी संख्या में कमी का एक कारण माना जा रहा है। कच्चे घरों का तेजी से कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होने से शहरों में इनके प्रजनन के लिए अनुकूल आवास नहीं मिलते हैं। गौरैया संरक्षण में जुड़े लोग कृत्रिम घर बनाकर गौरैया को प्रजनन के लिए आवास देने की पहल चला रहे हैं। भारत में पक्षियों की कुल मिलाकर 1250 प्रजातियां हैं। जिनमें से 85 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। जिसमें गौरैया का भी नाम शामिल है। गौरैया का सुरक्षित रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खा लेती है। जिससे किसान की फसल खराब होने से बच जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अभी से यह समझने की कोशिश करें कि छोटी सी गौरैया हमारे जीवन के लिए कितनी अहम है।

रमेश सर्राफ धमोरा
यह लेखक के अपने विचार हैं।

जीवन बोध

मनुष्य धर्म

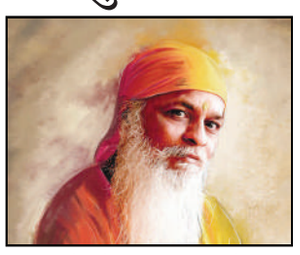

परमात्मा एक है और सारे धर्म मार्ग हैं। उस तक पहुंचने के लिए मनुष्य धर्म ही सबका धर्म है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, पशु नहीं और हिमालय में भी ऋषि, मुनि धर्म को अधिक महत्त्व नहीं देते। वे कहते हैं, आत्मा तो प्रत्येक जन्म के साथ धर्म बदलते रहती है, सदैव आत्मा के साथ आत्मधर्म तो रहता ही है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म बाहरी धर्म नहीं, भीतरी धर्म है और वह है आत्मधर्म। आत्मधर्म ही सबका भीतरी धर्म होता है। यानी संक्षेप में यह समझ लो कि कोई भी कट्टर धार्मिक मनुष्य को कभी भी मोक्ष की स्थिति प्राप्त ही नहीं हो सकती है। यह विशुद्धि चक्र पर विराट तत्त्व होता है। जब तक आप आपके भीतर परमात्मा एक है यह भाव नहीं ला पाते, आपको आपके जीवन में यश नहीं मिलता है। परमात्मा एक ही है, यह भाव आपके भीतर स्थापित हो जाने के बाद ही आपका विराट तत्त्व खुलता है। आध्यात्मिक प्रगति तो आत्मअनुभूति पर ही निर्भर करती है। जब तक यह विराट भाव हमारे भीतर स्थापित नहीं होता, हमें अनुभूति ही नहीं हो सकती है। अनुभूति होना इस ध्यानमार्ग की प्रथम पादान है। फिर प्राप्त अनुभूति को ही हम साधना करके विकसित कर सकते हैं। जिस प्रकार से बीज बोने के बाद कुछ दिनों बाद अंकुरित होता ही है, ठीक इसी प्रकार से, अनुभूति कराने के बाद अनुभूति नहीं हो रही है, यह चक्र की खराबी के कारण होता है।

शिवकृपानंद स्वामी

जल तरंग

उल्टे दुब्बे जी बन गए

एक कहावत है चौबे जी, छब्बे जी बनना चाहते थे पर उनके भाग्य में यह उपलब्धि नहीं थी, उल्टे दुब्बे जी बन कर रह गए। आज अंतरराष्ट्रीय माहौल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में शहंशाह बनकर अपना रुतबा कायम करना चाह रहे थे । इसलिए जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने तभी से वह उछल कूद मचाए हुए हैं । कभी टैरिफ बढ़ाकर किसी देश की अक्ल ठिकाने लगाने की बात कहते हैं तो कहीं युद्ध की धमकी देकर उसे छठी का दूध याद दिलाने का प्रयास करते हैं ।अब और नहीं तो ईरान को अपनी शर्तों पर समर्पण करने को कहकर उसे चुनौती दे रहे हैं। इजरायल के साथ मिलकर दो सप्ताह से युद्ध में बने हुए हैं । हजारों लोग बे समय प्राण त्याग चुके । एक बड़ी धनराशि युद्ध के काम आने वाले हथियार मिसाइल लड़ाकू विमान खर्च हो चुकी। बहुत सी मंजिलें बड़ी संख्या में समाप्त हुई हैं । पर अभी भी वह हर संभव ईरान को समर्पण के लिए बाध्य करना चाह रहा है ।अमेरिका को यह भरोसा रहा होगा है कि थोड़े दिनों के युद्ध में ईरान के घुटने टेक देगा। पर अभी तक घुटने टेकना तो दूर रहा उल्टे वह तो चुनौती देकर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है । इजरायल व अमेरिका दोनों ईरान की सैनिक क्षमता को देख सहमने लगे हैं । अमेरिका में भी युद्ध के चलते महंगाई की आहट सुनाई दे रही है। अरबों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब ट्रंप महोदय इस फिराक में हैं कि जैसे तैसे से युद्ध बंद हो जाए ताकि प्रतिष्ठा भी बनी रहे। यह वही ट्रंप हैं, जो जब तक भारत पाकिस्तान युद्ध को रोककर शांति स्थापित करने की बात करते हैं। पर आज लगता है वह विवश हो रहे हैं। क्या करें कैसे करें की उलझन में पड़े हुए हैं। यह स्थिति इसलिए आन पड़ी हुई कि अमेरिका ने साथी नाटो देशों ने भी युद्ध में उतरना, आ बैल मुझे मार की तरह लग रहा है। वह भला क्यों कर युद्ध में उतरेंगे, लेना एक न देना दो। उन्होंने इस युद्ध को लेकर अमेरिका का साथ छोड़ दिया। आज अमेरिका की स्थिति चल अकेला वाली हो गई। इजरायल भी अब तक अमेरिका के भरोसे बाहें चढ़ाये हुआ था। पर अब उसकी स्थिति भी इतनी सुखद नहीं बन रही। अब अंतराष्ट्रीय सहानुभूति अमेरिका के साथ दिखाई नहीं दे रही। आज जो वहां भी लोग इस युद्ध में अमेरिका को फटे में टांग फंसाने की तरह दोषी मानने लगे हैं । अब अमेरिका के लिए शांति से करवट बदलना भी मुश्किल हो रहा है । जो ट्रंप कभी अपने लिए शांति का नोबेल पुरस्कार चा रहे थे अब उन्हें युद्ध में अपना चेहरा तपाना पड़ रहा है। अब वह युद्ध को जैसे तैसे समेटने की संभावना देख रहे हैं। ईरान की बढ़ती हुई क्षमता की कल्पना किए बगैर उससे भिड़ने में नानी याद आ रही है। वह अपने मित्र देशों के भरोसे सहयोग की कामना कर रहा था, पर कोई भी तैयार नहीं हो रहा है ।अब तो लगता है कि ट्रंप महोदय इस फिराक में हैं कि कोई युद्ध रोकने व शांति स्थापित करने में सहयोगी बन जाए।

दिनेश विजयवर्गीय
यह लेखक के अपने विचार हैं।

आज का विचार

आपका काम ही आपकी पहचान बनाता है, न कि आपका बायो डेटा। बायो डेटा में तो निठल्ले लोग भी अपने आपको मेहनती, ईमानदार लिख देते हैं।
श्री चन्द्रप्रभ जी।

विंडो टू द वर्ल्ड

ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क

ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क शहर के मिडटाउन मैनहट्टन में 42वीं स्ट्रीट और पार्क एवेन्यू पर स्थित एक कम्यूटर रेल टर्मिनल है। यह मेट्रो नॉर्थ रेलरोड और न्यू हेवन लाइनों का दक्षिणी टर्मिनल है, जो न्यूयॉर्क महानगरीय क्षेत्र के उत्तरी भागों को सेवा प्रदान करता है। यह उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे व्यस्त रेल स्टेशन है।

हेल्थ इज वेल्थ

- दिल की बीमारियां दुनियाभर में स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हैं। हर साल इसके कारण लाखों लोगों की मौत हो जाती है। कम उम्र में ही हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट से मौत की खबरें सुनते हैं। दिल की बढ़ती बीमारियों के लिए लाइफस्टाइल और खान पान में गड़बड़ी को प्रमुख कारण माना जाता रहा है।
- जो लोग शारीरिक रूप से कम मेहनत करते हैं, मोटापे का शिकार हैं, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या का शिकार हैं उनमें हृदय रोगों का खतरा अधिक होता है। दिल की बीमारियों के लिए शरीर का हार्मोनल असंतुलन भी बड़ा कारण हो सकता है, जिन पुरुषों में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक होता है।
- यह हार्मोन्स पुरुषों में मांसपेशियों की मजबूती, हड्डियों और चेहरे शरीर के बालों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि अध्ययन में पाया गया है कि जिन लोगों में इस हार्मोन का स्तर अधिक है उनमें यह खतरा अधिक हो सकता है।

अपनों से अपनी सी बात

मनःस्थिति को ठीक करें

मनुष्य में कई प्रकार के बल होते है शारीरिक बल, प्राण बल, मनोबल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल।आज हम बात करेगें मनोबल की, मनस्थिति की।मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन की स्थिति ठीक करनी होगी।मन में जो विजातिय तत्व कोने कोने में भरे हुए हैं, उन्हें निकालना होगा।जब तक मन का डिटॉक्सीफीकेशन नहीं होगा तब तक शरीर डेटॉक्सिफाय नहीं हो सकता।आप कितनी भी खुराक ले लें, व्यायाम कर लें सब बेकार है।सबसे पहले मन को ठीक करना होगा।मन की स्थिति तीन बातों पर निर्भर करती है।भूतकाल की यादें, हमारी मान्यताएं और सूचनाएं जो हम ग्रहण कर रहे हैं।हमारे अवचेतन मन में जो पुरानी बुरी बातें जमा हैं, उन्हें निकालना होगा।जैसे कोई अपने दोस्त से कहे कि मेरे मां बाप बचपन में मेरे बड़े भाई को ज्यादा प्यार करते थे। तो दोस्त क्या कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, मां बाप तो सबको ही समान प्यार करते हैं। ऐसे ही हमें भी अपना दोस्त खुद ही बनकर हमारे मन को समझाना पड़ेगा।कभी किसी ने बरसों पहले हमारे साथ बुरा बर्ताव कर दिया तो उसे भी भूलना होगा, माफ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। सोचें कि आदमी ऐसा ही होता है, उस बेचारे का मन बीमार है।उसके लिए दुआ करें। हमें छुई मुई के पौधे की तरह नहीं बनना है। जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, जो हम पढ़, देख और सुन रहे हैं, उनका भी हमारे मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है।आज हम सारी दुनिया की जानकारी लेना चाहते हैं, जो गलत है।जो हमारी जिम्मेदारी का क्षेत्र है उसी की जानकारी रखें।ज्यादा जानकारी से भी मन की स्थिति बिगड़ती है।अगर हम सेवा क्षेत्र से है, तो ही अस्पताल में क्या चल रहा है उसकी जानकारी रखे अन्यथा नहीं।

ललित अकिंचन

Feedback@dainiknavajyoti.com

चेटीचंड विशेष

सामाजिक एकता और सहिष्णुता का संदेश देने वाला पर्व है

सिंधी समाज की आस्था, संस्कृति और नववर्ष का उत्सव

वासुदेव देवनानी
अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा

चेटीचंड जो सिंधी समाज का प्रमुख त्योहार और नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सिंधी समाज के लिए यह दिन आस्था, परंपरा और सामुदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है।चेटीचंड का पर्व हिंदू पंचांग के चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है।

भारतीय संस्कृति में अनेक पर्व ऐसे हैं, जो केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक भी हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है चेटीचंड जो सिंधी समाज का प्रमुख त्योहार और नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है।

सिंधी समाज के लिए यह दिन आस्था, परंपरा और सामुदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है।चेटीचंड का पर्व हिंदू पंचांग के चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह वही समय होता है जब वसंत ऋतु अपने पूरे सौंदर्य के साथ प्रकृति को नई ऊर्जा देती है। इसी दिन सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल का अवतरण हुआ माना जाता है। सिंधी मान्यता के अनुसार भगवान झूलेलाल जल के देवता और मानवता के रक्षक माने जाते हैं। उनका अवतार उस समय हुआ जब सिंध क्षेत्र में अत्याचार और धार्मिक उत्पीड़न बढ़ गया था। तब वहां के लोगों ने जल देवता से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान झूलेलाल ने जन्म लिया। उन्होंने अत्याचारियों को संदेश दिया कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और मानवता सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार झूलेलाल केवल एक धार्मिक प्रतीक ही नहीं बल्कि भाईचारे और सहिष्णुता के भी संदेशवाहक हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इतिहास के अनुसार सिंध क्षेत्र में एक शासक मिर्ख शाह था, जिसने वहां के हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने सिंधु नदी के तट पर 40 दिन तक प्रार्थना और तपस्या की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जल देवता ने झूलेलाल के रूप में अवतार लिया। किंवदंती के अनुसार उनका जन्म सिन्ध के नसरपुर नगर में हुआ था। बालक झूलेलाल बचपन से ही चमत्कारी थे और उन्होंने शासक को न्याय और सहिष्णुता का संदेश दिया। अंततः शासक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देने की घोषणा की। चेटीचंड केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सिंधी समाज का नववर्ष भी है। इस दिन लोग नए वर्ष की शुरुआत उत्साह और उल्लास के साथ करते हैं। घरों में साफ सफाई की जाती है, नए वस्त्र पहने जाते हैं और विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। मंदिरों और सामुदायिक स्थलों पर झूलेलाल की झांकियां सजाई जाती हैं और भजन कीर्तन किए जाते हैं।

पूजा में जल का विशेष महत्व

इस दिन सिंधी समाज के लोग आयो लाल झूलेलाल और जेको चवंदो झूलेलाल, तहिंजा थींदा बेड़ा पारश्जैसे जयघोष करते हैं। इन जयघोषों के पीछे विश्वास है कि भगवान झूलेलाल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और जीवन की कठिनाइयों से उन्हें पार लगाते हैं। चेटीचंड के अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण परंपरा बहाराणा साहिब की होती है। इसमें एक थाल या कलश में दीपक, नारियल, फूल, फल, मिठाई, गेहूं और पत्तियां सजाई जाती हैं। इस बहाराणा को भगवान झूलेलाल का प्रतीक माना जाता है। सामूहिक रूप से लोग इसे लेकर जुलूस निकालते हैं और किसी नदी, तालाब या समुद्र के किनारे जाकर पूजा करते हैं। यह परंपरा जल देवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का प्रतीक है। जल को जीवन का आधार माना जाता है, इसलिए झूलेलाल की पूजा में जल का विशेष महत्व होता है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां

चेटीचंड के अवसर पर देश और विदेश में बसे सिंधी समुदाय के लोग बड़े उत्साह से कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों में भजन, लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती हैं। कई स्थानों पर भगवान झूलेलाल की भव्य झांकियां निकाली जाती हैं। भारत के विभिन्न शहरों जैसे अजमेर, जयपुर, उदयपुर, मुम्बई आदि में सिंधी समाज के लोग शोभायात्राएं निकालते हैं। इनमें पारंपरिक वेशभूषा, लोकनृत्य और भक्ति गीतों के माध्यम से समाज की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाता है।1947 में भारत विभाजन के बाद सिंधी समाज का बड़ा हिस्सा भारत के विभिन्न भागों में आकर बस गया। उस समय उनके सामने पहचान और संस्कृति को बचाए रखने की चुनौती थी। ऐसे समय में चेटीचंद जैसे त्योहारों ने समाज को एक सूत्र में बांधे रखा।

सामाजिक एकता का संदेश

चेटीचंड केवल एक समुदाय का त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सहिष्णुता का संदेश देने वाला पर्व है। भगवान झूलेलाल की शिक्षाओं में मानवता, समानता और धर्मनिरपेक्षता की भावना निहित है। उनका संदेश था कि सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया जाना चाहिए। आज के समय में जब दुनिया में कई जगह धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष देखने को मिलते हैं, तब झूलेलाल का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। चेटीचंड हमें याद दिलाता है कि विविधता में ही भारत की असली शक्ति है। चेटीचंड सिंधी समाज की आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक है। नए वर्ष के स्वागत के साथ यह त्योहार जीवन में आशा, उत्साह और सकारात्मकता का संदेश भी देता है। इस प्रकार चेटीचंड केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत, सामुदायिक एकता और मानवता के मूल्यों को जीवित रखने का पर्व है। यही कारण है कि सिंधी समाज इस दिन को अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और गर्व के साथ मनाता है।

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 20 मार्च 2026

ऊर्जा संकट एक चुनौती और भविष्य को बदलने का अवसर भी है।
– *थॉमस फ्रीडमैन, अमेरिकी लेखक*

गहराता ऊर्जा संकट

ईरान में सत्ता परिवर्तन और उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के नाम पर जो लड़ाई शुरू हुई थी, वह अब एनर्जी वॉर में बदल चुकी है। दोनों पक्ष एक-दूसरे के ऑयल-गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर तुले हैं। इस जंग ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। गैस और तेल के दाम यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। इससे दुनिया के मंदी में फंसने का डर सता रहा है।

पार्स पर निशाना । इस्राइल ने पहले साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कतर और सऊदी अरब के तेल-गैस ठिकानों पर अटैक किए। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा नैचुरल गैस रिजर्व है, जो कतर तक फैला है। ईरान की घरेलू ऊर्जा जरूरत यहीं से पूरी होती है। इससे पहले अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर हमला किया था, जहां से ईरान का 90% तेल आयात होता है।

गैस फील्ड पर हमले

चढ़ते दाम । गैस फील्ड पर हमलों के बाद यूरोप में एक ही दिन में नैचुरल गैस की कीमतों में 30% का उछाल आया। वहीं क्रूड ऑयल 114 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। मौजूदा संघर्ष शुरू होने के बाद से इसमें करीब 60% की तेजी आ चुकी है। भारत की बात करें, तो देश पहले ही LPG को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसे में कतर के Ras Laffan LNG टर्मिनल पर अटैक से उसकी चिंताएं बढ़ेंगी। भारत अपनी जरूरत की लगभग आधी नैचुरल गैस कतर से ही खरीदता है।

लंबा नुकसान । यह लड़ाई जिस ढंग से आगे बढ़ रही है, पूरे पश्चिम एशिया के लंबे वक्त तक अस्थिर रहने का खतरा खड़ा हो गया है। इस इलाके के देशों की आय का सबसे बड़ा जरिया पेट्रोलियम है। इनके प्रॉडक्शन और सप्लाई चेन में गड़बड़ी आने पर उसे दोबारा सामान्य करने में समय लगेगा। खाड़ी देश लगभग एक तिहाई तेल और 18% नैचुरल गैस की आपूर्ति करते हैं। इसके बिना बाकी दुनिया का भी काम नहीं चल सकता।

आपसी मतभेद । अमेरिका और इस्राइल चाहते हैं कि ईरान की जनता आगे बढ़कर मौजूदा सत्ता को बेदखल कर दे। लेकिन, जिस तरह से वे ईरान के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, उससे सवाल उठता है कि अगर रेजीम बदलती है, तो भी वह मलबे का ढेर बन चुके देश को कैसे संभालेगी? डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें पार्स गैस फील्ड पर हमले की जानकारी नहीं थी। ऐसा लगता है कि कुछ बातों को लेकर अमेरिका और इस्राइल में भी मतभेद हैं। एकतरफा और मनमाने हमले बात और बिगाड़ेंगे।

तिराहा

यू-टर्न

सुखनंदन के माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। हर दो मिनट में फोन मिलाए जा रहे थे, पर उधर से एक ही आवाज आ रही थी, 'उपभोक्ता का नंबर अभी बंद है, कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें।' यह मोबाइल नंबर सुधर्मा का था। डेढ़ घंटे पहले दफ्तर से निकली थीं, लेकिन घर की दो किमी की दूरी पूरी नहीं हो पाई थी। तभी हॉर्न की आवाज गूंजी और चिंता का शोर शांत हुआ।

प्रेम शंकर मिश्र

'आग लगे शहर के ट्रैफिक को। हर ओर जाम और समाधान के नाम पर केवल यू-टर्न। बाएं मुड़ने के सारे रास्ते बंद हैं, यू-टर्न लो, दाएं मुड़ो', गाड़ी से उतरते हुए सुधर्मा ने कहा। सुखनंदन के साथ अब तक चिंता में साझेदार जयचंद टिप्पणी में व्यंजना तलाश बैठे। बोले, 'भाभी जी देश, काल, परिस्थिति की अद्भुत पारखी हैं।' सुधर्मा उनको घूरते हुए चली गईं।

दुःख दूर हुआ तो सुखनंदन का दर्शन उबाल मारने लगा। बोले, 'जयचंद! यू-टर्न यातायात का साधारण नियम मात्र नहीं, जीवन की यात्रा का भी सबसे सुरक्षित कवच है। साधारण बुद्धि के लोगों को लगता है कि यू-टर्न से मंजिल की दूरी बढ़ती है लेकिन वास्तव में यह लक्ष्य को निकट लाता है। इसलिए, विलक्षण लोग इसे अपने कर्म, आचरण एवं व्यवहार का हिस्सा बनाकर रखते हैं।'

'सड़क पर तो बोर्ड लगा होता है, लेकिन जीवन में कब यू-टर्न लेना है यह कैसे पहचानें?' जयचंद ने जिज्ञासा व्यक्त की। 'इसके लिए दिल-दिमाग में बोर्ड लगाकर उस पर लिख दो - लाभ। जहां संभावना दिखे वहां विचार, व्यवहार कर्म को यू-टर्न पर डाल दो', सुखनंदन ने समझाया। 'यह अवसरवादिता नहीं हुई?', सवाल जारी था। 'नहीं, अवसरवादिता वह होती है, जब आप निर्णय से पीछे हटते हैं। यू-टर्न में आप उल्टे पांव नहीं चलते, बल्कि दिशा बदलते हैं। बस इसकी अभिव्यक्ति का प्रारूप व शब्द उपयुक्त तलाशना होगा, जैसे - जनहित, सम्यक विचारोपरांत, संकट की घड़ी, मैंने कब कहा था, श्रद्धा में कमी रह गई....आदि।'

एकदा

संकलन : **अनुभव कुमार**

लेखक की ताक़त

बिहार के मोतिहारी में 1903 में जन्मे ब्रिटिश लेखक George Orwell का असली नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था। वह बचपन से ही अन्याय और असमानता को लेकर संवेदनशील थे। यही संवेदनशीलता उन्हें सन 1936 में फासीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए Spanish Civil War तक ले गई । लेकिन वहां उन्होंने जो देखा, उसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। युद्ध के मैदान में उन्होंने महसूस किया कि सच सिर्फ दुश्मन नहीं छिपा रहे थे, बल्कि अपने लोग भी झूठ का सहारा ले रहे थे। घायल अवस्था में 1937 में जब वह अस्पताल में पड़े हुए थे, तो उनके सामने एक कठिन प्रश्न था, 'क्या वह वही लिखें जो लोगों को अच्छा लगे, या वह लिखें जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा?' उन्होंने सचाई का रास्ता चुना, चाहे वह कितना ही असहज क्यों न हो। बाद में उन्होंने अपने अनुभवों को **'Homage to Catalonia'** नाम की पुस्तक में पूरी ईमानदारी से लिखा। इसमें उन्होंने अपने पक्ष की गलतियों को भी उजागर किया। जॉर्ज का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सचाई के प्रति ईमानदारी ही लेखक की सबसे बड़ी ताकत होती है। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन वही सबसे बड़ी बहादुरी है।

Subrata Dhar

तेहरान की आंखों देखी... आज़ाद लड़कियां और भारत से प्यार करने वाले लोग

आंखों देखा हाल और ईरान का सच

दुनिया में ईरान के बारे में जो कहा जाता है, वह पूरा सच नहीं। पिछले नवंबर में मैं तीन दिन के लिए तेहरान गया था। वहां पहुंचने पर अमेरिका में रहने वाले मेरे एक दोस्त ने मेसेज किया कि ईरान में तो सभी महिलाएं हिजाब पहनती होंगी? लेकिन, असल में ऐसा कुछ नहीं था। कुछ बुजुर्ग महिलाओं को छोड़कर किसी ने हिजाब नहीं पहना था। हिजाब तो छोड़िए, किसी के सिर पर स्कार्फ तक नहीं था।

सुजीत जॉन

सड़कों पर पुरानी कारें । हां, कई बरसों से पश्चिमी प्रतिबंध के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। एयरपोर्ट पर मुझे लेने आए शख्स को कारों का बहुत शौक था। होटल तक पहुंचने के घंटे भर के रास्ते में वह मुझे अलग-अलग कारें दिखाता रहा। उनमें से अधिकतर यूरोप की थीं। उसने मुझे बताया कि अब ये कारें ईरान में नहीं बनतीं। लेकिन, इन्हें चलाने वाले चीन से पुर्जे मंगवाते हैं या यहीं बनवा लेते हैं। सड़कों पर दौड़ने वाली अधिकतर कारें काफी पुरानी थीं। नई कारें दूसरे देशों की थीं और काफी महंगी। ईरान के शहर पुराने हैं और वहां नई आधुनिक इमारतें कम हैं।

सोच से जुदा । ईरान हमारी सोच से काफी अलग है। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने हमें बताया कि आज का ईरान शायद भारत के मुकाबले कम धार्मिक है। उनमें से एक ने कहा कि तेहरान की एक तिहाई मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि वहां कोई जाता नहीं था। ईरान की मस्जिदों में जाने वाले ज्यादातर वही हैं, जिन्हें धार्मिक संस्थाओं के जरिये सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। यह अनुदान की शर्तों में से एक है।

Adobestock

तेहरान में जो देखा
- कुछ बुजुर्गों को छोड़ किसी ने नहीं पहना था हिजाब
- लोग नहीं जाते तो बंद हुईं तेहरान की कई मस्जिदें
- देर रात पार्टी करते मिले युवा, तलाक की दर ज्यादा

काबिले तारीफ गर्मजोशी । वहां जितने लोगों से हम मिले, सभी ने नाइटलाइफ के बारे में बताया। एक शाम हम एक फूड कोर्ट में गए। वहां युवाओं का जमावड़ा था। एक टेबल पर बैठी युवती ने भेड़िये जैसा हेडगियर पहना था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम सैन फ्रांसिस्को या बेंगलुरु में हों। ईरानियों की गर्मजोशी काबिले तारीफ है। वहां के दुकानदार अक्सर कुछ चीजें मुफ्त में दे देते हैं। हमने कई ऐसे कैब ड्राइवरों की कहानियां सुनीं जो भारतीयों से पैसे नहीं लेते। जिस कॉन्फ्रेंस में हम गए थे, वहां साइंस एंड टेक्नॉलजी में ईरान की ताकत दिखाई जा रही थी। उसका मकसद ब्रिक्स देशों को एक मंच पर लाना था ताकि दुनिया की डॉलर पर निर्भरता घटाने के रास्ते तलाशे जा सकें। इसके विकल्प में ईरान की नजर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पर है।

तथ्यों पर चर्चा । कॉन्फ्रेंस में ईरानी सरकार के कई अधिकारियों और शिक्षाविदों ने अपनी बात रखी। इस्राइल और अमेरिका के हमलों के पांच महीने बाद हुए इस कार्यक्रम की सबसे खास बात रही कि किसी ने भी किसी देश पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। भाषण और विमर्श तथ्यों पर आधारित थे।

डॉलर से दूरी । तेहरान सिटी काउंसिल के सदस्य अली असगर घेमी ने मुझसे कहा, 'अमेरिका के साथ हमारा विवाद 50 बरसों से भी ज्यादा समय से चल रहा है। हमने युद्ध और तबाही जैसे नतीजे भी देख लिए। इसलिए, हम हर उस देश के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर पर निर्भरता से मुक्त करना चाहता है। भारत भी यही चाहता है। अमेरिका के साथ आपका भी टकराव है और आपके देश ने उसे बखूबी संभाला है।'

कट्टरता घटी । पश्चिमी देश अक्सर इस शासन को कट्टरपंथी इस्लामी गुटों का समूह बताते हैं। मगर, असलियत कुछ और है। अधिकतर लोगों ने हमसे कहा कि यह शासन कट्टरपंथियों और सुधारवादियों का मिश्रण है और अब सुधारवादियों का पलड़ा भारी हो रहा है। कट्टरपंथी भी अब उतने कट्टर नहीं रहे।

तलाक बढ़े । वापसी की हमारी फ्लाइट में डेटा साइंटिस्ट और इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में ICT विभाग की प्रमुख नरगिस मोट्टाघी भी थीं। वह अपने मंगेतर से मिलने बेंगलुरु आ रही थीं। उनका सपना NASA में साइंटिस्ट बनने का था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के कारण पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि ईरान की कई साइंस और टेक्नॉलजी यूनिवर्सिटी में लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा हैं। लड़के अब उच्च शिक्षा छोड़कर कारोबार कर रहे हैं। इससे शादियों में तालमेल की दिक्कत आ रही है। तलाक की दर करीब 50% हो गई है।

कोई डर नहीं । वीकेंड पर नरगिस एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अकेले ही पूरे ईरान में गाड़ी चलाकर घूमती हैं। कभी-कभी वह हाईवे के किनारे रुक कर सो जाती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए उनका देश पूरी तरह से सुरक्षित है।

(लेखक नवंबर में ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरंसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने ईरान गए थे)

आपके खाने में क्या, यह जानना ज़रूरी है...

भारत में मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग बढ़ रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसका कारण फैक्टरी में बने अल्ट्रा-प्रॉसेस्ड फूड आइटम, एक्स्ट्रा फैट, चीनी और नमक वाले उत्पाद हैं। इसे रोकने के लिए पैक्ड फूड पर पोषण संबंधी जानकारी देना जरूरी है। इसे फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग कहते हैं। इससे खाने का कोई सामान खरीदते समय उपभोक्ता तुरंत समझ सकता है कि इसमें चीनी, नमक या फैट कितना है और यह स्वास्थ्य के लिए कितना सुरक्षित है। इससे स्वस्थ विकल्प चुनना आसान होगा।

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

परामर्श शुरू । हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग पर दोबारा परामर्श शुरू किया। कई विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि वर्षों के अध्ययन के बाद अब ध्यान इसे लागू करने और उपभोक्ताओं को सरल व स्पष्ट जानकारी देने पर होना चाहिए। न्यूट्रिशन अडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (NAPi) ने अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा कि शोध पहले ही हो चुका है, इसलिए और देरी न हो व नीतियां बनाते समय लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए।

जानकारी जरूरी । पैक्ड फूड आइटम पर पोषण संबंधी जानकारी का मुद्दा भारत में लंबे समय से चर्चा में है। इस पर व्यापक सार्वजनिक विमर्श भी होता रहा है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि पैकेट पर साफ-साफ बताया जाए कि इसमें क्या-क्या और कितना है, तो उपभोक्ता सही निर्णय ले सकते हैं। इसके बजाय हेल्थ स्टार रेटिंग जैसी कुछ प्रणालियां भी समग्र संकेत देती हैं।

कॉमन रूम

विशेषज्ञों का मानना है कि जानकारी सरल, स्पष्ट और ऐसी हो कि आम आदमी आसानी से समझ जाए। इससे उनके लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में पैक्ड खाद्य पदार्थों पर पोषण संबंधी जानकारी को अधिक स्पष्ट बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

संतुलित प्रक्रिया । नीतियां बनाते वक्त सभी संबंधित पक्षों की राय ली जाती है। सरकार और नियामक संस्थाएं विशेषज्ञों, उपभोक्ता समूहों, उद्योग प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेकर फैसला करती हैं। इससे प्रक्रिया संतुलित और व्यावहारिक बनती है।

भारत के लिए जरूरी । स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, भारत को जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए जागरूकता और नीतिगत पहल, दोनों पर ध्यान देना होगा। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और पैक्ड खाद्य पदार्थों पर सही जानकारी मिलकर लोगों को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित कर सकते हैं। इन्हीं सब वजहों से पैकेट पर पोषण की पूरी जानकारी देना महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार, वैज्ञानिक, उद्योग और समाज के सहयोग से ही प्रभावी और व्यावहारिक व्यवस्था बनाई जा सकती है।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

क्यों और कैसे के सवाल में फंसने नहीं देता हौसला

हरीश बड़थ्वाल

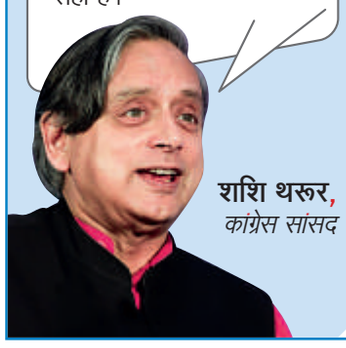

जब कोई सफलता के शिखर पर पहुंचता है, तो आम धारणा बनती है कि उसके पीछे मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि, अच्छी संगति और पर्याप्त संसाधनों का हाथ रहा होगा। लेकिन, जब कोई सीमित साधनों और साधारण परिवेश से उठकर ऊंचाइयों को छूता है, तो उसकी यात्रा चर्चा का विषय बन जाती है और वह स्वयं एक प्रेरणा। यह केवल सफलता की कहानी नहीं होती, यह कहानी होती है हौसलों, विश्वास और आंतरिक शक्ति की।

ऐसे लोगों के पास भले ही शुरुआती सुविधाएं कम रही हों, लेकिन उनके भीतर ऐसी जिद होती है, जो उन्हें परिस्थितियों से बड़ा बना देती है। उन्होंने जो कुछ भी पाया, वह अपनी लगन, दूरदर्शिता और साधना के बल पर पाया। इसके विपरीत, जिन्हें सब कुछ सहज ही मिल गया, वे कई बार उसके मूल्य को समझ नहीं पाते और वही सुविधा उनके पतन का कारण बन जाती है।

AI Image

वास्तव में, हौसले केवल बाहरी संघर्ष से नहीं बनते, यह भीतर की स्थिरता और स्पष्टता से जन्म लेते हैं। जिस व्यक्ति के मन में अपनी मंजिल के प्रति अटूट निष्ठा होती है, वह दुनिया की राय से प्रभावित नहीं होता। वह यह नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, वह कैसा दिखता है या उसका जीवनस्तर क्या है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका लक्ष्य और उसकी साधना। इन हौसलों के पीछे आत्मविश्वास के साथ गहरा आध्यात्मिक आधार भी है। ईश्वर के प्रति आस्था, अपने कर्म में विश्वास और कुछ नया करने की लालसा। सभी मिलकर व्यक्ति के भीतर ऐसी ऊर्जा का संचार करते हैं, जो उसे निरंतर आगे बढ़ाती है। इसलिए सच्ची महानता इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना धन या संसाधन हैं, बल्कि इस बात में है कि हम अपने भीतर कितनी स्थिरता, सादगी और सेवा भाव को बनाए रखते हैं। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना स्वाभाविक है, लेकिन उनमें अहंकार जोड़ देना विनाश की शुरुआत है। वास्तविक सफलता वही है, जो व्यक्ति को भीतर से समृद्ध बनाए, उसे जमीन से जोड़े रखे और उसके हौसलों को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करे।

कांटे की बात

ईरान युद्ध अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। यह भारत के संप्रभुता, अहिंसा जैसे मूल्यों के भी विरुद्ध है, लेकिन विदेश नीति सिर्फ नैतिकता के आधार पर नहीं चल सकती। ईरान पर भारत सरकार का रुख सही है।

शशि थरूर, *कांग्रेस सांसद*

सप्ताह की शख़्सियत

भारत-ईरान रिश्तों की अहम कड़ी रहे लारिजानी

ईरान के सुरक्षा प्रमुख रहे अली लारिजानी की मौत ने मौजूदा संकट को और उलझा दिया है। लारिजानी ने लंबे समय तक सत्ता में अहम भूमिका निभाई। वह गांधी-नेहरू के ईरान पर प्रभाव की भी बात करते थे। उनकी कूटनीति ने कठिन समय में भी दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग बरकरार रखा।

भारत के लिए भरोसेमंद

भारत और ईरान के बीच तेल व्यापार और आर्थिक संबंधों को बनाए रखने में लारिजानी की अहम भूमिका रही। उनका मानना था कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक रिश्ता भी है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद संवाद जारी रखने पर उनका जोर रहा। उनकी सोच ने भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के विकल्प खुले रखे व द्विपक्षीय भरोसे को कमजोर नहीं होने दिया।

AI Image

कई भूमिकाओं में माहिर

लारिजानी ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और डिप्लोमैट की भूमिकाएं एक साथ निभाने वाले ईरानी नेता थे। 2005 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद भी वह सत्ता के केंद्र में रहे और परमाणु वार्ताओं के मुख्य वार्ताकार बने। उन्होंने पश्चिम के साथ बातचीत में संतुलित रणनीति अपनाई। अपनी आखिरी चिट्ठी में उन्होंने दुनियाभर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की, जो उनकी व्यापक राजनीतिक सोच को दर्शाता है।

प्रस्तुति- अभिषेक मिश्र

जनता जंक्शन

इरफ़ान

कौन भुनाएगा पश्चिम एशिया का चुनावी सवाल

अखिलेश प्रताप सिंह

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इन चुनावों में यूं तो राज्यों के मुद्दे हावी रहने चाहिए या राष्ट्रीय स्तर के कुछ मुद्दों को हवा देने की कोशिश हो सकती है, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय पहलू भी इसमें जुड़ गया है। इस किस्से का सिरा जुड़ा है ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमले से। इससे पैदा होने वाली चुनौती NDA को भी तकलीफ दे सकती है और राज्यों में सत्तारूढ़ दलों को भी।

महंगाई बढ़ने का डर

पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच क्रूड ऑयल और नैचरल गैस की कीमतें बढ़ी हैं और भारत में इनकी आपूर्ति प्रभावित हुई है। जनवरी में 65-66 डॉलर प्रति बैरल पर रहा कच्चा तेल अब 100 डॉलर के पार है। भारत अपनी जरूरत का 88% कच्चा तेल आयात करता है और इसका करीब आधा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से आता रहा है। भारत के LNG इंपोर्ट का करीब 60% हिस्सा कतर और UAE जैसे देशों से होर्मुज स्ट्रेट के जरिए आता रहा है। LPG में चुनौती इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 60% हिस्सा आयात करता है, लेकिन इसका 90% तक होर्मुज स्ट्रेट से आता रहा है।

क्रूड सप्लाई और पेट्रोल-डीजल के मामले में ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि रूस से ज्यादा क्रूड खरीद होने लगी है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के चौथे बड़े निर्यातक भारत में फिलहाल तंगी की स्थिति नहीं है। हालांकि रूसी तेल अब पहले जैसा सस्ता नहीं रहा। मौजूदा संकट में उसके भाव भी बढ़ गए हैं। समीकरण यह है कि क्रूड ऑयल अगर अगले 10-12 महीनों में 110-115 डॉलर प्रति बैरल पर रहा, तो इसके आयात का सालाना बिल 65 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा। इससे भारत को और ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इससे रुपया और नीचे आएगा। तमाम चीजों का आयात महंगा होता जाएगा।

विशुद्ध राजनीति
कसौटी

यह महंगाई इन विधानसभा चुनावों के चार-पांच महीने पहले से बढ़ने लगी थी। BJP कहती रही है कि UPA शासन काल में महंगाई दर बहुत ज्यादा हुआ करती थी और मोदी शासन में इस पर काबू पाया गया है। लेकिन LPG के मसले पर निशाना साध रहे विरोधी दल महंगाई को भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध से ही जुड़ा दूसरा बड़ा मसला उर्वरकों का है। भारत जितना फर्टिलाइजर आयात करता है, उसका 26.2% हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। खुद वित्त मंत्रालय चिंता जता रहा है कि युद्ध लंबा चलने पर LNG और क्रूड पर निर्भर फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ सकता है। खरीफ सीजन से पहले केरल, पश्चिम बंगाल और असम के लिए यह संवेदनशील मामला है।

क्या बढ़ेंगे पेट्रोल के दाम

सरकार LPG सिलिंडरों के दाम बढ़ा चुकी है। विपक्ष इसका हवाला देते हुए वोटरों से कह सकता है कि चुनाव बाद पेट्रोल-डीजल के दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के 10 दिन बाद हरकत में आई। दूसरी ओर, BJP वोटरों को यह समझा सकती है कि अंतरराष्ट्रीय स्थितियों से बड़ा असर पड़ा है। BJP यह सवाल भी उछाल सकती है कि असम में महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से नीचे है, तो तमिलनाडु, बंगाल और केरल में ज्यादा क्यों है। ऐसे सवालों के जवाब वोटरों के गले में जो ठीक से उतार पाएगा, उसके लिए चुनावी लड़ाई आसान हो जाएगी।

रीडर्स मेल

PNG बेहतर विकल्प

यह पत्र 19 मार्च के संपादकीय 'बदलाव का समय' से संबंधित है। पश्चिम एशिया में ईरान और इस्राइल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण तेल संकट गहराता जा रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। भारत अपनी गैस जरूरत का लगभग 60% आयात करता है, जिसमें से 90% इसी मार्ग से आता है। ऐसे में देश में एलपीजी की बढ़ती मांग चिंता का विषय है। इसका एक बेहतर विकल्प PNG हो सकता है, जो सुलभ, सुरक्षित और निरंतर उपलब्ध हो सकती है। इस दिशा में गंभीरता से विचार आवश्यक है। राज्यों को भी इस बारे में सोचना चाहिए।

वारिस अली, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। यह समाचार पत्र स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित, आशीष पांडे द्वारा संपादित (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी) तथा मनीष सिन्हा द्वारा, **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, 13/1 & 2, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाज़ियाबाद (उ.प्र.)** से और नवनीत आहूजा द्वारा, प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर-11, IMT मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051 से मुद्रित। फोन : 23302000, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.

Join This Community and Get Lifetime Free Access all this Content.

✅ Receive Earliest Newspapers updates from 5 AM with All Editions

♦ Indian Newspaper

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ International Newspapers channel

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ Magazine Channel

National & International
[Genaral & Exam related]

♦ Editorials [English & Hindi]

[National + International Editorials]